



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2017/श्रावण 19, 1939

No. 206]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 2017/ SRAVANA 19, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2017

अंतिम जांच परिणाम

**विषय:** कनाडा, चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय यूनियन मूल की अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम क्लोरेट" के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने संबंधी जांच।

**फा.सं.14/13/2015-डीजीएडी.—** समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

## **क. मामले की पृष्ठभूमि**

1. यतः मेसर्स गुजरात अल्कालीज एंड केमिकल्स लिमिटेड और मेसर्स टीमेक क्लोरेट्स लिमिटेड (जिन्हें आगे "याचिकादता" कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 संशोधित (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने कनाडा, चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय यूनियन

(जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित निर्यातित "सोडियम क्लोरेट" (जिसे आगे संबद्ध वस्तुएं भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया है।

## ख. क्रिया-विधि

2. इस जांच में निम्नोक्त वर्णित क्रिया-विधि का अनुसरण किया गया है:-

- (क) प्राधिकारी को उपरोक्त नियमावली के अंतर्गत संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उद्योग की ओर से याचिकादाता से एक लिखित आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन होने और उससे घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने का आरोप लगाया गया है और साथ ही उसमें संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है।
- (ख) संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन होने, घरेलू उद्योग को उसकी परिणामी क्षति होने तथा कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध होने के प्रथम दृष्टया पर्याप्त प्रमाण के आधार पर प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच शुरू की थी, ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटन-रोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि सोडियम क्लोरेट के आयातों पर लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई "क्षति" को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी।
- (ग) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही करने से पहले भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों/प्रतिनिधियों को पाटन-रोधी आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बारे में अधिसूचित किया है।
- (घ) प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 12 मई, 2017 को प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की है।
- (ङ) प्राधिकारी ने जांच शुरू करने संबंधी सार्वजनिक अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध वस्तुओं के सभी ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ता एसोसिएशनों को प्रेषित की थी और उन्हें सलाह दी थी कि वे पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत करा दें।
- (च) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र के अगोपनीय वृत्तों की एक प्रति प्रदान की थी। किसी हितवद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर इस आवेदन-पत्र की एक प्रति उसको भी प्रदान की गई थी।
- (छ) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को उसने संबद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए निर्यातक की प्रश्नावलियां भेजी थीं:-

(क) मेसर्स एकजो नॉबल पल्प एंड परफोरमेंस केमिकल्स

(ख) मेसर्स अरकेमा फ्रांस

- (ज) जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने कानूनी निवेदनों के साथ प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

(क) मेसर्स एकजो नॉबल पल्प एंड परफोरमेंस केमिकल्स

(ख) मेसर्स अरकेमा फ्रांस

- (झ) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ता एसोसिएशनों को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:-

(क) मेसर्स जेनिथ इलेक्ट्रोकेम प्राईवेट लिमिटेड

(ख) मेसर्स बिंदल्स पेपर मिल्स लिमिटेड

(ग) मेसर्स के. आर. पल्प एंड पेपर्स लिमिटेड

- (ज) जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/निर्यातकों ने आयातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-
- (क) मेसर्ज जेनिथ इलेक्ट्रोकेम प्राईवेट लिमिटेड
  - (ख) मेसर्ज बिंदल्स पेपर मिल्स लिमिटेड
  - (ग) मेसर्ज के. आर. पल्प एंड पेपर्स लिमिटेड
  - (घ) मेसर्ज इंडियन पेपर मैनुफेक्चरर्स एसोसिएशन
  - (ङ) मेसर्ज बिल्ट ने हालांकि एक पत्र प्रस्तुत किया है, लेकिन उसने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- (ट) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय वृत्तान्त को एक सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया था, जिसे सभी हितबद्ध पक्षकारों की जांच के लिए एक सार्वजनिक फाईल में खुला रखा गया था। इस सार्वजनिक फाईल को अनेक बार अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने देखा है। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने सार्वजनिक फाईल को देखने तथा उसके दस्तावेजों की प्रतियों का अनुरोध किया था उन्हें सार्वजनिक फाईल को दिखया गया था और उनकी प्रतियां प्रदान की गई थीं।
- (ठ) प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा उसे सार्वजनिक फाईल द्वारा उपलब्ध कराया गया था।
- (ड) जितना आवश्यक समझा गया था, याचिकादाता और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से और सूचना मंगाई गई थी। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जितना आवश्यक समझा गया था, घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त किए गए आंकड़ों की जांच की गई थी।
- (ढ) यह जांच अक्टूबर, 2014 से दिसंबर, 2015 (15 महीनों) तक के लिए की गई है (जिसे आग "जांच अवधि" अथवा "पीओआई" भी कहा गया है)। तथापि, क्षति की जांच अवधि में 2012-13, 2013-14, 2014-15 तक की अवधि और जांच अवधि भी शामिल होगी।
- (ण) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वह जांच अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे प्रदान करने की व्यवस्था करें। डीजीसीआईएंडएस से उक्त सूचना प्राप्त हो गई है और वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ उसे अपनाया गया है।
- (त) भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और क्षति रहित कीमत का आकलन करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच जितना संभव हुआ है, अनुबंध-3 में निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर की है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यदि पाटन मार्जिन से कमतर पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है, तो क्या वह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (थ) प्राधिकारी ने नियम 6 (6) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचारों को मौखिक रूप से प्रकट करने का अवसर प्रदान करने के लिए 10 अप्रैल, 2017 को मौखिक सुनवाई की थी जिसमें विभिन्न पक्षकारों ने भाग लिया था। इस मौखिक सुनवाई के दौरान जिन हितबद्ध पक्षकारों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित में भी प्रस्तुत करें जिससे कि प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के साथ उनका पारस्परिक आदान-प्रदान किया जा सके ताकि वे बाद में वे उनके प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकें।

- (द) इस जांच की कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का निदान, प्राधिकारी द्वारा जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है, इस दस्तावेज में कर दिया गया है।
- (ध) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें।
- (न) वर्तमान जांच की कार्यवाही के दौरान जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच में अत्यधिक अडचन डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपना निर्णय दर्ज किया है।
- (प) प्राधिकारी ने नियम 16 के अंतर्गत 27 जुलाई, 2017 को एक प्रकटन विवरण जारी किया था और सभी हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान किया था कि वे 7 अगस्त, 2017 तक इस प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर दें।
- (फ) इस जांच परिणाम में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा \*\*\* सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर उसी प्रकार से विचार किया गया है।
- (ब) संबद्ध जांच के लिए जांच अवधि के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई औसत विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 64.17 रूपए है।

## ग. विचाराधीन उत्पाद और "समान वस्तु"

### ग 1. घरेलू उद्योग के विचार

3. घरेलू उद्योग द्वारा व्यक्त किए गए विचार निम्नानुसार हैं :-

- (क) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम क्लोरेट है, जिसे सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के अंतर्गत एक अकार्बनिक मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एनएसीआईओ3 के रसायनिक सूत्र के साथ सोडियम क्लोरेट एक सफेद क्रिस्टेल्लीन पाउडर होता है, जो कि जल में आसानी से विलय हो जाता है। यह एक हाईड्रोस्कोपिक है। यह आक्सीजन जारी करने के लिए 300 सी से ऊपर वियोजित हो जाता है और सोडियम क्लोराईड छोड़ देता है।
- (ख) सोडियम क्लोरेट का मुख्य वाणिज्यिक उपयोग, क्लोरीन डायोक्साईड (सीआईआ2) बनाने के लिए किया जाता है। सीआईआ2 का सर्वाधिक अनुप्रयोग, जो कि क्लोरेट के उपयोग का लगभग 95% होता है, पल्प की ब्लिचिंग के लिए किया जाता है। औद्योगिक रूप से सभी परक्लोरेट मिश्रण का उत्पादन, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा सोडियम क्लोनेट के विलयनों के ऑक्सीडेशन द्वारा किया जाता है।
- (ग) संबद्ध वस्तुएं टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत उप-शीर्ष संख्या 2829 11 00 के अंतर्गत आती हैं। तथापि, सीमा-शुल्क का यह वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से वर्तमान जांच पर बाध्यकारी नहीं है।
- (घ) संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित सोडियम क्लोरेट के बीच कोई अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित तथा संबद्ध देशों से आयातित सोडियम क्लोरेट, वास्तविक और तकनीकी लक्षणों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा शुल्क वर्गीकरण जैसी गुण-विशेषताओं की दृष्टि से एक समान ही हैं। उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं और इन दोनों उत्पादों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त कर रहे हैं। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सोडियम क्लोरेट और संबद्ध देशों से आयातित सोडियम क्लोरेट को समान वस्तु माना जाना चाहिए।

**ग 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन**

4. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्यातक और किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई निवेदन नहीं किया गया है।

**ग 3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

5. विचाराधीन उत्पाद "सोडियम क्लोरेट" है, जो कि एनएसीआईओ3 के रसायनिक सूत्र के साथ सोडियम क्लोरेट एक सफेद क्रिस्टेलीन पाउडर होता है, जो कि जल में आसानी से विलय हो जाता है। यह आक्सीजन जारी करने के लिए 300 सी से ऊपर वियोजित हो जाता है और सोडियम क्लोराईड छोड़ देता है। विचाराधीन उत्पाद के मापन का सामान्य वाणिज्यिक यूनिट किलोग्राम होता है। इसे वजन के आधार पर उद्धृत किया जाता है और इसे किलोग्राम अथवा मी.टन में बेचा जाता है।

6. संबद्ध वस्तुओं को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत उप-शीर्ष 2829 11 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा-शुल्क का यह वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से प्रस्तावित जांच पर बाध्यकारी नहीं है।

7. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का यह मानना है कि संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध उत्पाद, वास्तविक और तकनीकी लक्षणों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रोद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा शुल्क वर्गीकरण जैसी गुण-विशेषताओं की दृष्टि से एक समान ही हैं। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त कर रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा निर्मित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुएं समान वस्तु हैं।

**घ. घरेलू उद्योग और उसका आधार****घ 1. घरेलू उद्योग के विचार**

8. घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (क) यह याचिका मेसर्स गुजरात अल्कालीज एंड केमिकल्स लिमिटेड और मेसर्स टीमेक क्लोरेट्स लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। देश में "सोडियम क्लोरेट" का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। व्हाईट टीमेक क्लोरेट ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन अप्रैल, 2012 में शुरू किया है, जबकि जीएसीएल ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन, अप्रैल, 2014 में शुरू किया है।
- (ख) याचिकादाताओं का उत्पादन भारतीय उत्पादन का प्रमुख भाग बनता है और इसलिए याचिकादाताओं को नियमावली में घरेलू उद्योग की परिभाषा के भीतर "घरेलू उद्योग" माना जाना चाहिए।
- (ग) याचिकादाताओं ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयात नहीं किए हैं और इसके अतिरिक्त वे नियम 2 (ख) के अनुसार चीन में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक अथवा प्रयोक्ता से भी संबंधित नहीं हैं।
- (घ) मेसर्स टीमेक ने अपना उत्पादन अप्रैल, 2012 में शुरू किया है और जीएसीएल ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन, अप्रैल, 2014 में शुरू किया है। इस प्रकार ये घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में नए प्रवेशक हैं।
- (ङ) केमफैब क्लोरेट लिमिटेड याचिकादाता की निजी कंपनी है और इसे वर्ष 2009 में बंद कर दिया गया था। टीसीएम लिमिटेड ने भी अपना प्रचालन बहुत पहले बंद कर दिया था। इसके अतिरिक्त केमाफिन और त्रिवेणी दोनों सोडियम क्लोरेट की उपभोक्ता कंपनियां हैं और ये विनिर्माता नहीं हैं। ट्रावनकोर कोचीन कमिकल्स लिमिटेड आईएसआरओ के लिए विनिर्माण की संविदा कर रही है और घरेलू बाजार में इसका अपना कोई वाणिज्यिक क्रियाकलाप नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

## घ 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

9. इस संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-
- (क) आवेदक एक मात्र उत्पादक नहीं है क्योंकि ट्रावनकोर कोचीन कमिकल्स लिमिटेड, केमफैब क्लोरेट्स, केमोफाईन इंडस्ट्रीज, त्रिवेणी इंटरकेम प्राईवेट लिमिटेड के नाम का प्रकटन नहीं किया गया है। श्री क्लोरेट्स (जेनिथ इलेक्ट्रोकेम) के पास संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने का अभी भी वैध लाईसेंस है।
- (ख) प्राधिकारी द्वारा आवेदक के 100% उत्पादन के दावे को स्वीकार करना गलत है क्योंकि बाजार में अन्य उत्पादक भी विद्यमान हैं। केमफैब क्लोरेट्स लिमिटेड, टीसीएम लिमिटेड, श्री क्लोरेट्स, केमोफाईन इंडस्ट्रीज और त्रिवेणी इंटरकेम प्राईवेट लिमिटेड अन्य घरेलू उत्पादक हैं।
- (ग) याचिकादाताओं की अत्यधिक उत्पादन क्षमता, वर्ष 2015-16 में ही हुई है और उससे पहले उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं था कि वह आपूर्ति कर सकें और इस प्रकार उन्हें घरेलू उद्योग नहीं कहा जा सकता है।
- (घ) हमने अपने निवेदनों में यह विस्तार रूप से उल्लिखित किया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के दो और उत्पादक विद्यमान हैं, लेकिन घरेलू उद्योग फिर भी यह दावा कर रहा है कि वे ही एक मात्र उत्पादक हैं। प्राधिकारी को इस संबंध में घरेलू उद्योग के विवरण की सख्ती से संवीक्षा करनी चाहिए। पाटन-रोधी जांच में यह एक नया मानक नहीं हो सकता है कि आवेदक यदि नियम 2 (ख) के अंतर्गत निर्धारित मानदंड को पूरा करते हैं, तो वे किसी भी प्रकार का कोई गलत निवेदन करें। इस संबंध में यह पुनः निवेदन किया जाता है कि श्री क्लोरेट (मेसर्स जेनिथ इलेक्ट्रोकेम प्राईवेट लिमिटेड) (जिसकी क्षमता 2500 मी.टन/प्रति वर्ष है) और ट्रावनकोर कोचीन केमिकल्स लिमिटेड (जो कि राज्य का पीएसयू है) (जिसकी क्षमता 5000 मी.टन/प्रति वर्ष है) भी ऐसे उत्पादक हैं, जिनके पास भारत में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता विद्यमान है।
- (ङ) याचिकादाताओं के इस दावे के संबंध में कि वे विचाराधीन उत्पाद के एकल उत्पादक हैं, यह निवेदन किया जाता है कि ऐसा दावा वास्तविक रूप से गलत है और यह प्राधिकारी को अत्यधिक भ्रमित करने के एक प्रयास मात्र है। यह स्मरण कराया जाता है कि दिनांक 10.04.2017 को हुई सार्वजनिक सुनवाई के दौरान भी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसा दावा किया गया था। तथापि, आवेदक द्वारा अपने लिखित निवेदन में ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
- (च) जैसा कि दिनांक 13.04.2017 के अपने लिखित निवेदनों में हमने उल्लेख किया है, उनसे यह स्पष्ट होता है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के अनेक उत्पादक हैं। हमने अपने लिखित निवेदनों में ऐसे चार अन्य उत्पादकों की एक प्रारंभिक सूची भी प्रस्तुत की थी। प्राधिकारी कृपया हमारे इस तर्क से सहमत होंगे कि आवेदक उद्योग का यह दायित्व बनता है कि वह अपने घरेलू उद्योग होने के "आधार" के बारे में सही और विश्वसनीय सूचना देने के साथ-साथ घरेलू उद्योग के व्यौरे प्रदान करे। इस संबंध में उसके द्वारा प्रक्रियात्मक अथवा कानूनी रूप से अपने दायित्व को ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को अंतरित करना उपयुक्त नहीं होगा, जिन्होंने देश में उत्पादकों अथवा कुल उत्पादन के संबंध में आवेदकों के दावों को अस्वीकृत करने के लिए उचित सूचना प्रदान की है।
- (छ) यह स्पष्ट होता है कि याचिकादाताओं ने जानबूझ कर प्राधिकारी से जटिल सूचना को छिपाया है, ताकि वे वर्तमान आवेदन-पत्र में अपने आधार को सिद्ध कर सकें और क्रमशः नियम 5 और नियम 2 (ख) में उल्लिखित अनुसार घरेलू उद्योग के बतौर अपना दावा प्रस्तुत कर सकें। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदकों द्वारा ऐसी गलत घोषणा का स्वतः जांच शुरू करने पर सीधा प्रभाव पड़ता है, हमारा प्राधिकारी से विनम्र निवेदन है कि वे कृपया जांच को समाप्त कर दें क्योंकि आवेदक ईमानदारी से पेश नहीं हुए हैं।
- (ज) उपरोक्त के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के हमारा प्राधिकारी से अनुरोध है कि सुनवाई के बाद प्राप्त हुई सूचना अथवा सुनवाई से पहले ऐसी सूचना को, जिसे सार्वजनिक फाईल में नहीं रखा गया है, कृपया हमें संप्रेषित किया जाए ताकि हम अपने हितों की समुचित ढंग से रक्षा करने में समर्थ हो सकें। साथ ही हमारा प्राधिकारी से यह भी अनुरोध है कि कृपया "आधार" के संबंध में आवेदकों से मूल सूचना प्राप्त होने के बाद हमें नई सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए और उसकी सूचना हमें दी जाए।

- (झ) मेसर्ज पेपर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने निवेदन किया है कि सोडियम क्लोरेट के केवल दो घरेलू उत्पादक हैं। भारत में लगभग 20,000 मी.टन सोडियम क्लोरेट विनिर्मित किया जा रहा है, जबकि कागज उद्योग द्वारा लगभग 40,000 मी.टन सोडियम क्लोरेट की खपत की जा रही है। सोडियम क्लोरेट के उत्पादन और खपत के बीच 20,000 मी.टन का अंतर व्याप्त है, जिसे कनाडा, चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय यूनियन से आयात करके पूरा किया जा रहा है क्योंकि घरेलू उत्पादक घरेलू मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं।

### घ 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

10. आवेदन-पत्र मेसर्ज गुजरात अल्कालीज एंड केमिकल्स लिमिटेड और मेसर्ज टीमेक क्लोरेट्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिन्होंने यह दावा किया है कि वे एक मात्र घरेलू उत्पादक हैं। किसी भी याचिकादाता ने संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं किया है अथवा वे संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित नहीं हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि ऐसे कुछ अन्य उत्पादक भी हैं, जो संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। तथापि, इसको सिद्ध करने के लिए कोई आधार अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही यह भी नोट किया जाता है कि इस सतत जांच में किसी भी उक्त घरेलू उत्पादक ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

11. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की प्रमुख प्रयोक्ता एसोसिएशन, नामतः मेसर्ज पेपर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अपने निवेदनों में यह उल्लेख किया है कि सोडियम क्लोरेट के केवल दो घरेलू उत्पादक हैं, नामतः मेसर्ज गुजरात अल्कालीज एंड केमिकल्स लिमिटेड और मेसर्ज टीमेक क्लोरेट्स लिमिटेड। इसलिए प्राधिकारी ने इस तथ्य को और साथ ही इसको ध्यान में रखते हुए कि किसी भी ऐसे हितबद्ध पक्षकार ने जो कि विचाराधीन उत्पाद का स्वतः एक उत्पादक है, इस जांच के शुरू होने का कोई विरोध नहीं किया है, पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में उल्लिखित घरेलू उद्योग की परिभाषा के भीतर याचिकादाताओं को पात्र घरेलू उद्योग माना है और आवेदन-पत्र उपरोक्त नियमावली के नियम 5 (3) में उल्लिखित घरेलू उद्योग के आधार के मानदंड को पूरा करता है।

12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू करने के बाद तथा जांच की कार्यवाही के दौरान उत्पादक ने स्वतः प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के साक्ष्य प्रस्तुत किया है, हालांकि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि विचाराधीन उत्पाद के कुछ अन्य उत्पादक भी हैं।

### ड. गोपनीयता, आंकड़ों की सम्पूर्णता और अन्य मुद्दे

#### ड 1. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

- (क) वर्तमान जांच के दायरे से संयुक्त राज्य अमरीका के बहिष्करण के कारण प्रारंभ में जांच शुरू करना अमान्य है और इस अकेले आधार पर वर्तमान जांच की शुरुआत को समाप्त कर दिए जाने की आवश्यकता है।
- (ख) इस दावे के संबंध में कि याचिकादाताओं को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि प्रतिवादी ने घरेलू बिक्रियों के साथ-साथ लागत संबंधी सूचना प्रदान नहीं की है और उसे अगोपनीय वृत्तान्त में निगमन करना असंभव है, यह निवेदन किया जाता है कि उक्त आरोप तुच्छ, भ्रान्ति पूर्ण और अनिष्टकर हैं। इस संबंध में दिनांक 23.03.2017 के हमारे पत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो कि वास्तव में सार्वजनिक फाईल में भी उपलब्ध है, जिसमें प्रतिवादी ने ऐसे कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उसे सामान्य मूल्य से संबंधित आंकड़ों पर ध्यान दिए बिना क्यों विशिष्ट पाटन मार्जिन स्वीकृत किया जाना चाहिए। याचिकादाता द्वारा सार्वजनिक फाईल को देखने में विफल होना और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और सूचना का संज्ञान लेना, उन्हें तुच्छ और अप्रमाणित टिप्पणियां करने का कोई अधिकार नहीं दे देता है।
- (ग) आवेदक उद्योग के द्वारा किए गए इस आशय के निवेदन के संबंध में कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तरों का अगोपनीय वृत्तान्त अत्यधिक गोपनीय है, यह निवेदन किया जाता है कि उक्त आरोप निराधार है और अवास्तविक है। वास्तव में प्राधिकारी के निर्देशों और इस संबंध में अनुपालन की जा रही पद्धति के अनुसार प्रतिवादी के उत्तर का अगोपनीय वृत्तान्त

तैयार किया गया है। इसलिए पर्याप्त कारण बताते हुए प्रतिवादी द्वारा गोपनीयता का दावा किया गया है, जो कि कानूनी प्रावधानों और प्राधिकारी की सुस्थापित पद्धति के पूर्णतया सुसंगत है।

- (घ) याचिकादाताओं ने अपने सनक और कल्पना के अनुसार गैर-कानूनी रूप से और शरारत पूर्ण ढंग से आवेदन-पत्र के प्रपत्र को परिवर्तित कर दिया है। प्रपत्र 4-क में प्रारंभिक स्टॉक और अंत-स्टॉक जैसी प्रमुख सूचना प्रदान नहीं की गई है।

## **ड 2. प्राधिकारी द्वारा जांच**

13. सूचना की गोपनीयता के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीय के दावों की पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे सार्वजनिक फाईल में नहीं रखा है। साथ ही प्राधिकारी ने उपरोक्त नियम तथा अपनी सुसंगत पद्धति के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों पर भी विचार किया है।

14. आंकड़ों की सम्पूर्णता और परिशुद्धता के बारे में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और फ्रांस में सहयोगी उत्पादक/निर्यातक, मेसर्स अरकेमा द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की जांच की है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने आयात के आंकड़ों की परिशुद्धता को प्रमाणित करने के लिए डीजीसीआईएंडएस से भी आयात के आंकड़े प्राप्त किए हैं।

## **च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण**

### **च 1. घरेलू उद्योग के विचार**

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (क) हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे सार्वजनिक सूचना की उपलब्धता का पता चलता हो। याचिकादाताओं ने श्रेष्ठ उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य संरचित किया है। यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि यदि ऐसी कोई सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, तो हितबद्ध पक्षकार यह प्रमाणित करने के लिए स्वतंत्र है कि आयात कीमत, पाटित कीमत नहीं है।
- (ख) प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में जांच अवधि, अक्टूबर, 2014 से दिसंबर, 2015 (15 महीने) माना है। क्षति की जांच अवधि में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 और जांच अवधि को शामिल किया गया माना गया है।
- (ग) जांच अवधि का निर्धारण करने का प्रयोजन ऐसी अवधि पर विचार करना है, जब कि ऐसा प्रमाणित होता है कि दावा की गई क्षति का कारण पाटन का विद्यमान होना है। निर्धारण की तारीख, घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण पाटन होने के मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है। चूंकि यह प्रमाणित हो चुका है कि पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, इसलिए इस प्रयोजनार्थ जांच के दौरान केवल विद्यमान दशाओं पर ही विचार करना प्रासंगिक, उपयुक्त और आवश्यक होना चाहिए।
- (घ) चीन के उत्पादकों को इस कारण से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियां माना जाना चाहिए कि चीन में लागत और कीमतें, उचित रूप से बाजार प्रतिबलों को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। अनुबंध-1 के पैरा 8 में ऐसे प्राचल विनिश्चित हैं, जिन पर बाजार अर्थव्यवस्था वाला दर्जा स्वीकार करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि जब तक इन शर्तों को पूरा नहीं कर लिया जाता है, तब तक चीन की लागतों और कीमतों को अपनाया नहीं जा सकता है।
- (ङ) बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे पर विचार करना, जांच अवधि के दौरान प्रचलित प्राचलों पर आधारित होता है। चूंकि अनुबंध-1 के पैरा 8 में सूचीबद्ध कारकों के कारण चीन में लागतों और कीमतों के विरूपण किए जाने के कारण चीन में लागतों और कीमतों को स्वीकृत किया जाना है, इसलिए याचिकादाता का निवेदन है कि चीन के उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियां माने जाने का निर्णय लेने के लिए जांच अवधि प्रासंगिक है।

- (च) चूंकि अनुबंध-1 के पैरा 8 में उल्लिखित कारणों से दिसंबर, 2016 तक चीन की कंपनियों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए याचिकादाता का निवेदन है कि चीन के उत्पादकों को तब तक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियों माना जाने की आवश्यकता है, जब तक कि जांच अवधि में अभिगमन नीति नयाचार में विनिश्चित अवधि को शामिल किया जाता है।
- (छ) नियम 2 (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह सुस्थापित कानूनी स्थिति है कि घरेलू उत्पादक द्वारा आयात अथवा किसी निर्यातक अथवा आयातक के साथ उसके संबंध की जांच अवधि के प्रसंग में की जाती है। यदि आधार के प्रयोजनार्थ केवल जांच अवधि प्रासंगिक होती है, तो केवल जांच अवधि को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक होना चाहिए।
- (ज) चीन के उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के परिवेश में प्रचालन कर रही कंपनियां माना जाना चाहिए और प्राधिकारी अनुबंध-1 के पैरा 7 के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की कार्यवाई कर सकते हैं।
- (झ) सामान्य मूल्य का निर्धारण, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में कीमत अथवा संरचित मूल्य के आधार पर इस कारण से नहीं किया जा सकता है कि संबद्ध सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। याचिकादाताओं ने यह दावा किया है कि उचित समायोजन करके भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया गया है।
- (ञ) चीन से पाटन मार्जिन न केवल अत्यधिक है, बल्कि यह पर्याप्त भी है। इस प्रकार भारत में विचाराधीन उत्पाद के अत्यधिक पाटन के विद्यमान होने की संपुष्टि होती है। समस्त क्षति अवधि के दौरान चीन के आयात की मात्रा अत्यधिक बनी हुई है।
- (ट) चूंकि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद भी संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों की कीमतें/दरें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए घरेलू उद्योग ने यूरोपीय यूनियन और कनाडा में उत्पादन की लागत के श्रेष्ठ अनुमानों के आधार पर यूरोपीय यूनियन और कनाडा में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
- (ठ) याचिकादाताओं ने अरकेमा के इस आरोप का सुद्धता से खंडन किया है कि उनके उत्पाद में कोई पाटन नहीं है। वास्तव में अरकेमा के मामले में पाटन मार्जिन, आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट अनुमानों से बहुत अधिक होना चाहिए।
- (ड) एकजो नॉबल ने अपनी घरेलू बिक्रियों और उत्पादन की लागत के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की है। प्रत्यक्षतः एकजो नॉबल ने प्रश्नावली के उत्तर के सार्वजनिक वृत्तान्त में तथ्यों को अत्यधिक निरूद्ध किया है।

## **च 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

- (क) संरचित किया गया सामान्य मूल्य इसलिए गलत है क्योंकि ऐसा दावा किया गया है कि कनाडा/यूरोपीय यूनियन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जो कि सही नहीं हैं और गलत मूल्य का परिकलन किया गया है।
- (ख) सीएनवी विधि के समनुरूप नहीं है क्योंकि कच्चे माल को आवेदक को उपलब्ध कीमत पर लिया गया है और न कि उस कीमत पर जिस पर संबद्ध देशों में यह उपलब्ध है। कच्चा माल और प्रयोज्यता के मानदंड - खपत के कारक को मानक मानदंडों के अनुसार लिया गया है जब कि वास्तव में इसे भारत में अत्यधिक कुशल कंपनी के अनुसार लिया जाना चाहिए। परिवर्तन लागत और एसजीए व्यय को घरेलू उद्योग के आंकड़ों के अनुसार लिया गया है, जबकि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग बहुत कम है, जिसके फलस्वरूप अधिक लागत होती है तथा व्याज लागत को भी घरेलू उद्योग के मानक के अनुसार लिया गया है, जबकि वास्तव में यह बहुत अधिक है क्योंकि याचिकादाता अपेक्षाकृत नए हैं।
- (ग) घरेलू उद्योग ने निबल निर्यात कीमत को कम करने के लिए समुद्री भाड़े का बहुत अधिक दावा किया है और यह दावा अनसुना है। हमारा प्राधिकारी से अनुरोध है कि घरेलू उद्योग के समुद्री भाड़े के दावे को स्वीकार नहीं किया जाए और उसे सहयोगी निर्यातकों/पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए सत्यापन योग्य आंकड़ों के अनुसार अपनाया जाए।
- (घ) अरकेना ने भारतीय प्राधिकारियों को न केवल प्रारंभिक प्रश्नावली में अनुरोध की गई सभी सूचना प्रदान की है, बल्कि कुल मिला कर प्राधिकारियों द्वारा अनुरोध किए गए अतिरिक्त तत्व और स्पष्टीकरण भी दिए हैं। अरकेमा भारत में अनुचित पाटन करने की अनुचित पद्धति में संलिप्त नहीं हुआ है। यूरोपीय यूनियन के आयातों पर पाटन-रोधी उपायों को लागू करना भारत में उसके उत्पाद के अनेक प्रयोक्ताओं के हित के विरूद्ध होगा। संबंधित उत्पाद का घरेलू उत्पादन स्थानीय मांग को पूरा करने के

लिए विकट रूप से अपर्याप्त है और बिना किसी कारण से यूरोपीय यूनियन पर शुल्क लागू करना अनुचित होगा, जिसके फलस्वरूप स्थानीय बाजार में संबंधित उत्पाद की अत्यधिक कमी हो जाएगी और कीमतों में वृद्धि होगी जो कि निचले स्तर के क्षेत्रों के लिए हानिकर होगी।

- (ड) स्वीडन से निर्यातक, मेसर्स एकजो नॉबल ने सामान्य मूल्य और तदनुसार सामान्य मूल्य से संबंधित सूचना का दावा नहीं किया है। निर्यातक ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि नियम 6 (8) के अनुसार श्रेष्ठ उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य संरचित किया जाए। इस संबंध में निर्यातक ने यूरोपीय यूनियन, कोरिया जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 600 मी.मीटर से कम चौड़ाई के 400 सीरीज के स्टेनलैस स्टील ग्लास रोल्ड फ्लेट उत्पादों और पोस्को कोरिया निरूपण पर संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय यूनियन, चीनी ताईपाई, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसिटोन (सिंगापुर से एक निर्यातक, मेसर्स मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड) और ईरान से क्लीयर फ्लोट ग्लास (मेसर्स अरदाकान फ्लोट ग्लास कंपनी, ईरान) के मामलों का हवाला दिया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए निर्यातक ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि मेसर्स एकजो नॉबल द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर को स्वीकार कर लिया जाए और उन्हें पृथक विशिष्ट मार्जिन स्वीकृत किया जाए।
- (च) यूरोपीय कमीशन ने निवेदन किया है कि जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना और याचिका से ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता ने विद्युत की लागत (प्राकृतिक गैस) के लिए अंतर्राष्ट्रीय दरों का प्रयोग करके भारतमें लागू होने वाली परिवर्तन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य संरचित किया है। चूंकि गैस की कीमत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तुलना में अत्यधिक भिन्न हो सकती है, इसलिए कमीशन का यह विचार है कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कीमत का प्रकटन किया जाना चाहिए और कमीशन यह समझने में असमर्थ है कि याचिका के अगोपनीय वृत्तान्त में प्रयुक्त लागत के संबंध में कोई सही अथवा श्रेणीबद्ध सूचना क्यों निहित नहीं है। इसके अतिरिक्त याचिका में अन्य कच्ची सामग्री के लिए प्रयुक्त किए गए मूल लागत के आंकड़ों अथवा उनके स्तर के संबंध में कोई सूचना निहित नहीं है। कमीशन यह समझने में भी असमर्थ है कि ऐसी सूचना को क्यों गोपनीय रखा जाना चाहिए।
- (छ) यूरोपीय कमीशन ने निवेदन किया है कि भारत ने विश्व व्यापार संगठन के एडीए के अनुच्छेद 6.5.1 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जिसमें ऐसा प्रावधान है कि गोपनीय रूप से प्रस्तुत की गई सूचना के वास्तविक अर्थ को उचित रूप से समझे जाने वाले सार्थक अगोपनीय वृत्तान्त प्रदान किए जाने चाहिए। इस प्रकार कमीशन का जांचकर्ता प्राधिकारी से एतद्वारा यह अनुरोध है कि उन्हें याचिका के अगोपनीय वृत्तान्त का संशोधित वृत्तान्त प्रदान किया जाए ताकि कमीशन और अन्य हितबद्ध पक्षकार वास्तविक अर्थ को समझ सकें और अभिरक्षा के अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें।
- (ज) यूरोपीय कमीशन ने निवेदन किया है कि यह नोट किया जाना चाहिए कि यूरोपीय यूनियन में उत्पादकों का उनके आकार और उनसे प्राप्त आर्थिक व्यवस्था के कारण संभवतः भिन्न लागत ढांचा होता है। यह तथ्य है कि भारतीय याचिकादाताओं ने केवल हाल ही में अर्थात् क्रमशः अप्रैल, 2012 और 2014 में उत्पादन करना शुरू किया है। इसके अतिरिक्त उनकी कार्यक्षमता के स्तर पर और सामान्य मूल्य की संरचना करने के लिए जिन परिवर्तन दरों को लागू किया गया है, उन पर भी संदेह उत्पन्न होते हैं। प्रयुक्त किए गए कच्चे माल की लागत संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कमीशन न ही ऐसी लागत की मदों पर और न ही सामान्य मूल्य के स्तर पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में है। अंततः सामान्य मूल्य से संबंधित अनुबंध 3.2 में दी गई सीमा (0.5 - 1.0) काफी व्यापक प्रतीत होती है और यह अनुच्छेद 6.6.1 की अपेक्षा को पूरा करती हुई प्रतीत नहीं होती है।
- (झ) यूरोपीय कमीशन ने निवेदन किया है कि सामान्य मूल्य स्थापित करने और पाटन मार्जिन के परिणामी स्तर को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई कार्य-प्रणाली और प्रयुक्त किए गए आंकड़ों की पर्याप्तता पर संदेह होता है। अगोपनीय फाईल की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जांच प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को पर्याप्त नहीं समझा जाना चाहिए और याचिका को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

**च 3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

- (क) यूरोपीय यूनियन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन करने के यूरोपीय कमीशन के प्रेक्षकों के संबंध में प्राधिकारी ने यूरोपीय यूनियन से सहयोगी निर्यातक के उनके उत्तर के आधार पर मूल्यांकन किया है और यूरोपीय यूनियन से उत्पादकों/निर्यातकों की अधिशेष श्रेणी के लिए सहयोगी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का उपयुक्त रूप से उल्लेख किया गया है।
- (ख) उत्पादकों/निर्यातकों के लिए कारखाना-गत निर्यात कीमत का परिकलन करने के लिए याचिकादाताओं द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य और समायोजन के परिकलन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि यूरोपीय यूनियन से दो उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से एक पूरा और अन्य अधूरा है, इसलिए प्राधिकारी घरेलू उद्योग के दावे के साथ अधिशेष श्रेणी के लिए कारखाना-गत निर्यात कीमत के लिए समायोजन का संयोजन कर सके हैं। ऐसे मामले में जहां संबद्ध देशों से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी को सहयोग नहीं दिया है, वहां प्राधिकारी के पास श्रेष्ठ उपलब्ध सूचना का प्रयोग करने के सिवाए कोई और विकल्प नहीं था, जिसमें आयातकों के उत्तर और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य शामिल हैं। प्राधिकारी की ऐसी सुसंगत पद्धति रही है कि वह ऐसी किसी भी अन्य उपयुक्त सूचना का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि व्यवहारिक और उचित होती है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि पाटन की मात्रा का मूल्यांकन करना एक उत्पादक/निर्यात विशिष्ट होता है, संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए यह अनिवार्य होता है कि वे ऐसा निर्धारण करने में प्राधिकारी को सहयोग करें। अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा पाटन मार्जिन का मूल्यांकन करने के अन्य कोई भी प्रेक्षकों अर्थात् संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों से भिन्न, को ऊपर उल्लिखित विभिन्न विकल्पों के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित किया जा सकता है। प्राधिकारी ने ऐसे निवेदनों पर उचित रूप से विचार किया है।

**च 3.1. चीन के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य**

15. धारा 9 (1) (ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:-

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत :

16. चूंकि चीन से किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली के उत्तर द्वारा वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, इसलिए प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 पर विचार किया है। चीन जनवादी गणराज्य से भारत में आयातित संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य की संरचना, घरेलू उद्योग के लिए स्वीकृत स्तर पर प्रमुख कच्चे माल और प्रयोज्यताओं, परिवर्तन लागत, व्याज, एसजीए आदि के लिए घरेलू उद्योग के अनुकूलतम खपत के मानदंडों पर विचार करते हुए नियम 6 (8) के अनुसार श्रेष्ठ उपलब्ध सूचना के आधार पर की गई है। डीजीएडी की सुसंगत पद्धति के अनुसार उचित लाभ के लिए व्याज की बिक्रियों की लागत के \*\*\*% की स्वीकृति दी गई है जिसमें व्याज शामिल नहीं है।

**च 3.2. चीन के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण**

17. चूंकि चीन से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर नहीं दिया है। इसलिए प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण, डीजीसीआई एंड एस के कारोबार-वार आंकड़ों के आधार पर किया है। तदनुसार चीन जनवादी गणराज्य से सभी निर्यातकों के संबंध में कारखाना-गत स्तर पर भारित औसत निबत निर्यात कीमत का निर्धारण, नियम 6 (8) के अनुसार श्रेष्ठ उपलब्ध सूचना के आधार पर समुद्री भाडे, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, पत्तन व्यय और अंतरदेशीय भाडा परिवर्तन, जो कि क्रमशः \*\*\*यूएस\$/मी.टन, \*\*\*यूएस\$/मी.टन, \*\*\*यूएस\$/मी.टन, \*\*\*यूएस\$/मी.टन, \*\*\*यूएस\$/मी.टन, और \*\*\*यूएस\$/मी.टन है, के लिए उचित समायोजन करने के बाद किया गया है और उसका उल्लेख नीचे पाटन तालिका में किया गया है। इस प्रकार आंकलित कारखाना-गत निर्यात कीमत और सीआईएफ मूल्य क्रमशः \*\*\*यूएस\$/मी.टन और \*\*\*यूएस\$/मी.टन बनता है।

### च 3.3. कनाडा के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

18. यह नोट किया जाता है कि कनाडा में किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करके प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार कनाडा में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य की संरचना सामान्य मूल्य की संरचना, घरेलू उद्योग के लिए स्वीकृत स्तर पर प्रमुख कच्चे माल और प्रयोज्यताओं, परिवर्तन लागत, व्याज, एसजीए आदि के लिए अनुकूलतम खपत के मानदंडों पर विचार करके की है। डीजीएडी की सुसंगत पद्धति के अनुसार उचित लाभ के लिए व्याज की बिक्रियों की लागत के \*\*\*% की स्वीकृति दी गई है जिसमें व्याज शामिल नहीं है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य नीचे पाटन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

### च 3.4. कनाडा में निर्यात कीमत का निर्धारण

19. चूंकि कनाडा से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर नहीं दिया है। इसलिए प्राधिकारी ने कनाडा के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण, डीजीसीआईएंडएस के कारोबार-वार आंकड़ों के आधार पर किया है। तदनुसार कनाडा से सभी निर्यातकों के संबंध में कारखाना-गत स्तर पर भारित औसत निबत निर्यात कीमत का निर्धारण, नियम 6 (8) के अनुसार श्रेष्ठ उपलब्ध सूचना के आधार पर समुद्री भाडे, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, पत्तन व्यय और अंतरदेशीय भाडा परिवर्तन, जो कि क्रमशः \*\*\*यूएस\$/मी.टन, \*\*\*यूएस\$/मी.टन, \*\*\*यूएस\$/मी.टन, \*\*\*यूएस\$/मी.टन, \*\*\*यूएस\$/मी.टन, और \*\*\*यूएस\$/मी.टन है, के लिए उचित समायोजन करने के बाद किया गया है और उसका उल्लेख नीचे पाटन तालिका में किया गया है। इस प्रकार आंकलित कारखाना-गत निर्यात कीमत और सीआईएफ मूल्य क्रमशः \*\*\*यूएस\$/मी.टन और \*\*\*यूएस\$/मी.टन बनता है।

### च 3.5. यूरोपीय यूनियन से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय यूनियन से संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं, जिनमें उन्होंने पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए सूचना प्रदान की है:-

(क) मेसर्ज एकजो नॉबल पल्प एंड परफोरमेंस केमिकल्स

(ख) अरकेमा फ्रांस, यूरोपीय यूनियन

(1) प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्ज एकजो नॉबल ने केवल भारत में अपनी निर्यात कीमत के बारे में सूचना प्रदान की है, लेकिन उत्पादन की लागत और घरेलू बिक्रियों की सूचना नहीं दी है। इस संबंध में प्राधिकारी उनके इस आशय के निवेदनों को नोट करते हैं कि विगत में प्राधिकारी ने कुछ उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई केवल निर्यात कीमत पर विचार किया है और उनके लिए सामान्य मूल्य संरचित किया है। साथ ही प्राधिकार यह भी नोट करते हैं कि मेसर्ज एकजो नॉबल द्वारा उद्धृत किया गया कोई भी मामला, वर्तमान मामले के समान नहीं है। प्राधिकारी का यह मानना है कि कोई भी उत्पादक/निर्यातक आंशिक रूप से चुन कर निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर नहीं दे सकता है। प्रश्नावली के उत्तर में प्राधिकारी द्वारा मांगे गए आंकड़ों के पूरे होने की आवश्यकता है, ताकि प्राधिकारी उनका संयुक्त मूल्यांकन कर सकें। प्राधिकारी मेसर्ज एकजो नॉबल की आंशिक रूप से प्रस्तुत की गई सूचना को स्वीकार नहीं करते हैं और

इसलिए उन्हें असहयोगी मानते हैं तथा उन पर केवल अधिशेष श्रेणी में विचार करते हैं तथा श्रेष्ठ उपलब्ध सूचना के अनुसार सहयोगी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई यूरोपीय यूनियन में बिक्री संबंधी उपलब्ध सूचना और साथ ही डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के संदर्भ में पाटन-रोधी उपाय का निर्धारण करते हैं।

(2) मेसर्ज अरकेमा, फ्रांस द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जितना संभव था स्थल पर जांच की गई है तथा जांच की कार्यवाही के दौरान उठाए गए विभिन्न मुद्दों की जितना प्रासंगिक और व्यवहारिक था जांच की गई है। उत्पादक/निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण, सत्यापित आंकड़ों/सूचना के आधार पर किया गया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान फ्लेक्ड (एलप्युर एक्स) और ब्लक (एलप्युर एस) ग्रेड दोनों की घरेलू बिक्रियों के ब्यौरे पल्प क्षेत्र को प्रस्तुत किए हैं, जो कि क्रमशः \*\*\* मी.टन और \*\*\* मी.टन हैं। उत्पादक/निर्यातक ने पैकिंग, अंतरदेशीय भाड़े और कमीशन के लिए क्रमशः \*\*\*यूरो/मी.टन, \*\*\*यूरो/मी.टन और \*\*\*यूरो/मी.टन तक का समायोजन करने का दावा किया है। फुटकर स्तर पर नॉन-पल्प क्षेत्र में की गई बिक्रियों के लिए उत्पादक/निर्यातक ने व्यापार के स्तर पर समायोजन करने का अतिरिक्त दावा किया है। उत्पादक/निर्यातक ने जांच अवधि में भारत में फ्लेक्ड किस्म के उत्पाद अर्थात् एलप्युर एक्स की निर्यात बिक्रियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं और अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, पैकिंग और अन्य प्रभारों के लिए क्रमशः \*\*\*यूरो/मी.टन, \*\*\*यूरो/मी.टन और \*\*\*यूरो/मी.टन तक का समायोजन करने का दावा किया है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की कार्यवाही के दौरान उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली में दिए गए इस आशय के अपने उत्तरों को ही दोहराया है कि भारत को घरेलू और निर्यात बिक्रियों की तुलना एक समान आधार पर की जानी चाहिए अर्थात् भारत को निर्यात किए गए फ्लेक्ड उत्पाद की तुलना, यूरोपीय यूनियन के घरेलू बाजार में फ्लेक्ड उत्पाद की बिक्री के साथ की जाए और न कि ब्लक के साथ तथा वह भी पेपर और पल्प का मुख्य प्रयोक्ता उद्योग के लिए उसी व्यापारिक स्तर पर हो।

प्राधिकारी ने पेपर और पल्प क्षेत्र के लिए अलग-अलग ग्रेड के स्तर पर तुलना की है, जहां मुख्य बिक्रियां की गई हैं और जहां व्यापार का स्तर भी तुलनीय है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक ने भारत में फ्लेक्ड ग्रेड में बड़े थैलों (नॉन-ब्लक) नामतः एलप्युर एक्स में निर्यात किए हैं और उसी किस्म के उत्पाद नामतः एलप्युर एक्स को घरेलू बाजार में भी बेचा है, जो कि अत्यधिक बिक्रियों की अवसीमा को पूरा करता है। फ्रांस में उत्पादक/निर्यातक के स्थल पर जा कर दल द्वारा मौके पर की गई जांच और जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर तथा बाद में निर्यातक की सत्यापन रिपोर्ट पर मांगे गए स्पष्टीकरण/उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने फ्लेक्ड और ब्लक ग्रेडों दोनों के लिए पृथक् रूप से उत्पादन की कारखाना-गत लागत का निर्धारण किया है, जो कि क्रमशः \*\*\*यूरो/मी.टन और \*\*\*यूरो/मी.टन है।

व्यापारिक परीक्षण की सामान्य कार्यवाही के आधार पर और बाद में फ्लेक्ड किस्म की ऐसी सभी घरेलू बिक्रियों, जिनसे घरेलू बाजार में जांच अवधि के दौरान घाटा हो रहा था, को अभिज्ञात करने के बाद प्राधिकारी ने फ्लेक्ड किस्म के उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य का मूल्यांकन किया है, जो कि \*\*\*यूरो/मी.टन है। इस संबंध में प्राधिकारी ने घरेलू बाजार में जांच अवधि के दौरान तुलनीय एलप्युर एस ग्रेड के लाभप्रद कारोबार पर औसत लाभ को वरीयता दी है, ताकि फ्लेक्ड श्रेणी के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया जा सके।

जांच अवधि के दौरान भारत में एलप्युर एक्स ग्रेड के लिए अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, पैकिंग और अन्य प्रभारों के लिए समायोजन करने के बाद कारखाना-गत निर्यात कीमत \*\*\*यूरो/मी.टन मानी गई है।

उपरोक्त के बाद पाटन मार्जिन \*\*\*यूरो/मी.टन (\*\*\*) बनता है।

यूरोपीय यूनियन में मेसर्ज एकजो नॉबल सहित अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने यूरोपीय यूनियन में सामान्य मूल्य पर बिक्रियों के ग्रेड/स्तर पर ध्यान दिए बिना सभी घरेलू बिक्रियों पर सहयोगी निर्यातक के आंकड़ों के आधार पर विचार किया है। इस आधार पर मूल्यांकित किया गया पाटन मार्जिन \*\*\*यूरो/मी.टन (\*\*\*) बनता है।

**च 3.6. पाटन मार्जिन**

21. उपरोक्त यथा निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों पर विचार करने के बाद परिकलित किया गया पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	चीन (सभी उत्पादक/निर्यातक)	कनाडा (सभी उत्पादक/निर्यातक)	यूरोपीय यूनियन	
				अरकेमा	अन्य
सामान्य मूल्य	अमरीकी डालर/ मी.टन	***	***	***	***
निबल निर्यात कीमत	अमरीकी डालर/ मी.टन	***	***	***	***
पाटन मार्जिन	अमरीकी डालर/ मी.टन	***	***	***	***
पाटन मार्जिन	%	***	***	***	***
पाटन मार्जिन (सीमा)		0-10	20-30	10-20	20-30

**छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण**

22. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क लागू करने के लिए आवेदन-पत्र मेसर्ज गुजरात अल्कालीज एंड केमिकल्स लिमिटेड और मेसर्ज टीमेक क्लोरेट्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है और ये भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक मात्र हैं। नियमावली के नियम 2 (ख) के अनुसार याचिकादाताओं को इस जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग माना गया है। इसलिए लागत और क्षति का निर्धारण करने के लिए याचिकादाताओं की सूचना की जांच की गई है, जो कि नियम 2 (ख) में परिभाषित अनुसार घरेलू उद्योग बनते हैं।

**छ 1. घरेलू उद्योग के विचार**

- (क) चूंकि संबद्ध देशों से निर्यात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की जारी समान वस्तुओं से सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए इन आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त है। संबद्ध देशों से उत्पादकों द्वारा विनिर्मित उत्पाद परस्पर रूप से और याचिकादाताओं द्वारा विनिर्मित उत्पादों की तुलना में तुलनीय गुण क्षमताएं रखते हैं। अन्य शब्दों में संबद्ध देशों और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की जा रही वस्तुएं परस्पर रूप से समान वस्तुएं हैं।
- (ख) समस्त क्षति अवधि में मांग में वृद्धि हुई है, लेकिन जांच अवधि में उसमें मामूली गिरावट आई है। वर्ष 2013-14 के दौरान आयातों में भी वृद्धि हुई है और उसके बाद भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादन शुरू कर दिए जाने के कारण उनमें मामूली गिरावट आई है। भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद भी आयात सम्पूर्णतया और सापेक्षिक रूप से बहुत अधिक रहे हैं।

- (ग) कीमत में कटौती होने के संबंध में विदेशी उत्पादकों ने अपनी कीमतों को अमरीकी डालर 600-700 प्रति मी.टन से घटा कर अमरीकी डॉलर 470-440 प्रति मी.टन कर दिया है।
- (घ) आयात घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास कर रहे हैं क्योंकि आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमतों के स्तर से काफी कम है। संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद को बहुत अलाभकारी कीमतों पर बेचने के लिए विवश कर रही हैं। काफी समय से इस तथ्य के बावजूद कि लागतों में कोई गिरावट नहीं आई है, कीमत में अत्यधिक ह्रास हुआ है।
- (ङ) घरेलू उद्योग की क्षमता मांग के समान है और क्षमता उपयोग के अनुकूलतम स्तर को प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन पाटित आयातों के कारण उसे अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है, हालांकि क्षमता उपयोग बढ़ गया है।
- (च) उत्पादन के रूप में घरेलू उद्योग की संवृद्धि सकारात्मक है। तथापि, पाटित आयातों के कारण बिक्रियों के अनुकूलतम स्तर और बाजार के हिस्से को प्राप्त नहीं किया गया है। यहां तक कि बिक्रियों का वर्तमान स्तर, अनुकूलतम कीमतों से काफी कम है जिसके कारण वित्तीय घाटे हो रहे हैं।
- (छ) ऐसे कम स्तर होने के बावजूद जिस पर कि घरेलू उद्योग वस्तुओं का उत्पादन करता है, देश में पाटन के कारण माल-सूचियों में वृद्धि हुई है।
- (ज) समस्त क्षति अवधि में उत्पादन और बिक्रियों में वृद्धि होने के बावजूद भी लाभ, व्याज पूर्व लाभ, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ सभी बहुत बदतर स्थिति में रहे हैं।
- (झ) वर्तमान जांच अवधि में प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों सकारात्मक और अत्यधिक हैं।
- (ञ) घरेलू उद्योग उत्पाद की क्षति रहित कीमत वसूल करने में समर्थ नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किया जा रहा लाभांश उस स्तर से काफी नीचे है, जिसे विश्वभर में उचित और सही माना जाता है।
- (ट) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू कर दिए जाने के बावजूद भी पाटित आयातों की मात्रा अत्यधिक बनी हुई है।
- (ठ) पाटित आयातों के कारण कीमत के घटने से घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को घटाने के लिए विवश हो गया है।
- (ड) संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कीमत ह्रास के प्रभाव के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के वित्तीय घाटों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- (ढ) देश में अत्यधिक मांग और क्षमताएं होने के बावजूद भी घरेलू उद्योग को अपने उत्पादन, बिक्रियों, क्षमता उपयोग और बाजार के हिस्से को अपनी क्षमताओं की सीमा तक बढ़ाने से रोका गया है।
- (ण) लाभ, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ और नकदी लाभ पर पाटित आयातों के सीधा प्रभाव पड़ने के कारण उनमें गिरावट आई है।
- (त) घरेलू उद्योग के अंशदायी मार्जिन में तेजी से गिरावट आई है, जिसका मुख्य पाटन होना है।
- (थ) आर्थिक प्राचलों की संख्या के रूप में घरेलू उद्योग की संवृद्धि नकारात्मक हो गई है।
- (द) घरेलू उद्योग की माल-सूचियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

## **ख 2. निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

- (क) घरेलू उद्योग को कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है क्योंकि उसकी क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों में वृद्धि हुई है। उसका लाभ उसी स्तर पर स्थिर बना हुआ है, जिस स्तर पर यह आधार वर्ष में था, लेकिन वर्ष 2013-14 और 2014-15 से उसमें वृद्धि हुई है और लाभ में गिरावट आने के लिए आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। कीमत में कटौती नकारात्मक रही है क्योंकि घरेलू उद्योग की वस्तुओं की कीमतें, संबद्ध देशों से पहुंच कीमत से कम रही हैं।

- (ख) जांच अवधि में घरेलू उद्योग के हिस्से में 51% की वृद्धि हुई है और संबद्ध देशों का हिस्सा, आधार वर्ष में 78% से घट कर जांच अवधि में 48% रह गया है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है और यह जांच पश्चात अवधि में 90% तक और उससे अधिक हो गया है तथा घरेलू उद्योग को लाभ अर्जित हुआ होना चाहिए।
- (ग) क्षति अवधि में उत्पादन, क्षमता उपयोग और विक्रियों में वृद्धि हुई है।
- (घ) लाभ उसी स्तर पर स्थिर बना हुआ है, जिस स्तर पर यह आधार वर्ष में था, लेकिन वर्ष 2013-14 और 2014-15 से उसमें वृद्धि हुई है और लाभ में गिरावट आने के लिए आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।
- (ङ) कीमत में कटौती नकारात्मक रही है क्योंकि घरेलू उद्योग की वस्तुओं की कीमतें, संबद्ध देशों से पहुंच कीमत से कम रही हैं।
- (च) याचिकादाताओं के घाटों में अब गिरावट आ रही है। चूंकि याचिकादाता कंपनियां नई हैं, इसलिए उनके प्रारंभिक घाटों के लिए आयातों/आरोपित पाटन को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।
- (छ) याचिकादाताओं ने कम कीमत पर बिक्री करने अथवा नकारात्मक नकदी प्रवाह होने का दावा नहीं किया है और न ही विश्लेषण करने के बाद ऐसा पाया गया है।
- (ज) याचिकादाताओं ने रोजगार और उत्पादकता पर आयातों के नकारात्मक प्रभाव पड़ने का कोई उल्लेख नहीं किया है।
- (झ) इस तथ्य के बावजूद कि याचिकादाता बाजार में अपेक्षाकृत नए हैं, वे अल्पावधि में बाजार के 51% हिस्से को अधिप्राप्त करने में समर्थ हुए हैं और इस प्रकार क्षति अवधि/जांच अवधि में क्षति होने का दावा करने के बावजूद भी उन्होंने संवृद्धि दर्शाई है और इसलिए उनकी क्षति का आरोप निराधार है।
- (ञ) आरोपित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- (ट) कीमत में कटौती और कीमत ह्रास सकारात्मक है और इसलिए कीमत में ऐसी कोई कटौती नहीं हुई है।
- (ठ) विक्रियों, उत्पादकता, बाजार के हिस्से और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग के घाटों में कमी हुई है।
- (ड) घरेलू उद्योग द्वारा कम कीमत पर बिक्री करने अथवा नकारात्मक नकदी प्रवाह होने का कोई दावा नहीं किया गया है।
- (ढ) यह तथ्य कि संयुक्त राज्य अमरीका को संबद्ध देशों के दायरे में शामिल नहीं किया गया है, हालांकि संयुक्त राज्य अमरीका से आयातों की मात्रा न्यूनतम स्तर से बहुत अधिक है और संयुक्त राज्य अमरीका से कीमत, संबद्ध देशों की संचयी और पृथक रूप से विशिष्ट कीमत से कम है।
- (ण) घरेलू उद्योग के दावे अत्यधिक निजी, स्वार्थ पूर्ण और भ्रामक हैं। वर्तमान मामले में कोई मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार का हिस्सा, आधार वर्ष में 7% से बढ़ कर जांच अवधि में 51% हो गया है, जबकि संबद्ध देशों का हिस्सा, आधार वर्ष में 78% से घट कर जांच अवधि में 48% रह गया है। ऐसा तब हुआ है जब घरेलू उद्योग ने नई क्षमता का विस्तार करने के बाद केवल वर्ष 2015-16 में कुछ अधिक उत्पादन करना शुरू किया था। वास्तव में आयातों ने तेजी से घरेलू उद्योग को मार्ग दर्शा दिया और ऐसे आयातों के कारण उसे कोई क्षति नहीं हो सकती है और भारत में क्षमता की कमी के कारण ऐसे आयात किए जाने आवश्यक थे।
- (त) घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच के दायरे से संयुक्त राज्य अमरीका के मुद्दे को दबाने का प्रयास किया है, जो कि संबद्ध देशों के समान कारणात्मक संबंध को संदूषित करता है और साथ ही नियम 19 को ध्यान में रखते हुए इसका भेदमूलक पहलु भी बनता है। प्राधिकारी कुछ देशों को बाहर रख कर भेदमूलक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। वास्तव में संयुक्त राज्य अमरीका से "आयातों की कम मात्रा" होने का दावा युक्ति संगत नहीं है। नियम में 3% के विशेष स्तर होने का प्रावधान है, जबकि घरेलू उद्योग द्वारा जांच अवधि के लिए प्रस्तुत किए गए आयात विवरण के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका से आयात का स्तर 3% से अधिक है।

यहां तक कि जांच अवधि को स्वतः बढ़ा दिया जाने से ऐसा बहिष्करण करना यथोचित नहीं है क्योंकि मुख्य तथ्यों की जांच करने के बाद जांच अवधि को स्वतः बढ़ाया जाता है और ऐसा नहीं माना जा सकता है कि ऐसा विस्तार स्वतः हो गया है।

(थ) घरेलू उद्योग ने इस तथ्य को छिपाने के लिए कि संयुक्त राज्य अमरीका से कीमत, संबद्ध देशों की कीमतों से बहुत कम है, संयुक्त राज्य अमरीका से कीमत का प्रकटन नहीं किया है। संयुक्त राज्य अमरीका से कीमत 33 रूपए/प्रति किलोग्राम है, जबकि संबद्ध देशों से कीमत 37 रूपए से 42 रूपए प्रति किलोग्राम के बीच है, जो कि संयुक्त राज्य अमरीका की कीमत से बहुत अधिक है।

द. याचिकाकर्ता के क्षति संबंधी दावे के संबंध में, याचिकाकर्ता को संबद्ध देशों से आयात के कारण कोई क्षति नहीं हो रही है। याचिकाकर्ता कीमत कटौती या कम कीमत पर बिक्री या कीमत ह्रास सिद्ध करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत करने में बुरी तरह से विफल रहे हैं। यह और भी आश्चर्यजनक है कि याचिकाकर्ता ने याचिका या लिखित अनुरोध में कहीं भी कम कीमत पर बिक्री का कोई आरोप नहीं लगाया है। इस तथ्य से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि न कोई कीमत कटौती हुई है और न ही कम कीमत पर बिक्री और इसलिए यह कहना बिल्कुल निराधार है कि क्षति पाटित आयातों के कारण हो रही है। यह हमारे तर्क पर ध्यान दिए बिना है कि जो हमारे विस्तृत लिखित अनुरोधों पर आधारित है कि पहली बात यह है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। अंतः आयातों के कारण घरेलू उद्योग के क्षति होने के दावे को सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। क्षति मापदंडों के विस्तृत विश्लेषण से ऋणात्मक क्षति प्रदर्शित होती है जिसे हमारे लिखित अनुरोध में पहले ही दर्शाया गया है। इसलिए संक्षेप के लिए उसे यहां दोहराया नहीं गया है।

ध. यहां यह उल्लेख करना संगत है कि याचिकाकर्ता ने आकड़ों की बाजीगरी दिखाकर कीमत कटौती के संबंध में प्राधिकारी को गुमराह करने का प्रयास किया है।

न. इस संदर्भ में, प्राधिकारी का ध्यान याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त अद्यतन याचिका के पृष्ठ 21 पर पैरा 71 और पृष्ठ 38 पर प्रपत्र IV-ख की और दिलाया जाता है। यह देखा जा सकता है कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने पृष्ठ 21 पर पैरा 71 में सकारात्मक कीमत कटौती का दावा किया है तथापि पृष्ठ 38 पर प्रपत्र IV-ख में उसके विश्लेषण की अद्यतन याचिका में स्पष्ट रूप ऋणात्मक कीमत कटौती दर्शाई गई है।

प. सकारात्मक कीमत कटौती ज्ञात करने के लिए, याचिकाकर्ता ने प्रपत्र IV-ख में दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से आकड़ों को गलत ढंग से और तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने लाइन 9 में सेनवेटयोग्य राशि के बश्चात पंधुच कीमत की गणना सीवीडी/ईडी तथा एसएडी/एसीडी/एसटी से पंधुच मूल्य को घटाकर की है। दूसरी ओर, सेनवेटयोग्य क्रेडिट (लाइन 15) के बाद औसत बिक्री कीमत को केवल उतपाद शुल्क घटाकर और न कि सीएसटी (जो एसएडी/एसीडी/एसटी के बराबर है) को घटाकर परिकलित किया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने आकड़ों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है और सकारात्मक कीमत कटौती दर्शाने के एकमात्र उद्देश्य से अतुलनीय मदों की तुलना करने का प्रयास किया है जो वास्तव में नहीं हुई है। दुर्भाग्यवश इस स्पष्ट तथ्य पर भी प्राधिकारी का ध्यान नहीं जा पाया। प्राधिकारी को इस तथ्य को गंभीरता से लेना चाहिए और याचिकाकर्ता के विरुद्ध सांविधिक प्राधिकारी को गुमराह करने का प्रयास करने के लिए प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने चाहिए।

फ. प्राधिकारी इस बात पर ध्यान दें कि प्रपत्र IV-ख में यद्यपि क्रम सं. 16 (iii) और 17(iii) में "ईडी और सीवीडी के बिना कीमत कटौती" और "ईडी और सीवीडी के बाद कीमत कटौती" के लिए नकारात्मक कीमत कटौती दर्शाई गई है तथापि क्रम सं. 18 (iii) में "सेनवेटयोग्य क्रेडिट के बाद कीमत कटौती" के लिए सकारात्मक कीमत कटौती दर्शाई गई है। यह दोहराया जाता है कि सं. 18 (iii) में सकारात्मक कीमत कटौती सेनवेटयोग्य क्रेडिट के बाद औसत बिक्री कीमत के लिए सेनवेटयोग्य राशि की गणना के कारण हुआ है, याचिकाकर्ता ने इरादतन और सरलता से सीएसटी की उपेक्षा कर दी है। दूसरी ओर सेनवेट क्रेडिट के बाद पंधुच कीमत के लिए सेनवेट योग्य राशि की गणना के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता ने एसएडी/एसीडी/एसटी को शामिल किया है। यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसी गणना से वास्तव में आयातों का पंधुच मूल्य घट गया है और इस प्रकार पंधुच कीमत और औसत घरेलू बिक्री कीमत के बीच अंतर बढ़ गया जिससे सकारात्मक कीमत कटौती प्रदर्शित हुई। प्रपत्र IV-ख में याचिकाकर्ता द्वारा आकड़ों में की गई गड़बड़ी विभिन्न तालिकाओं से स्पष्ट है।

ब. आकड़ों में गड़बड़ी इस स्पष्ट इरादे के साथ की गई है कि किसी भी तरह से सकारात्मक कीमत कटौती दर्शाई जाए और उसके संबंध में प्राधिकारी को गुमराह किया जाए। यह भी बताया गया है कि ऐसी गड़बड़ी को हतोत्साहित करना और उससे कड़ाई से निपटा जाना

चाहिए। चूंकि वर्तमान जाँच याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत गलत आकड़ों पर आधारित है इसलिए इसे तुरंत समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह भी अनुरोध किया जाता है कि तिमाही-वार कीमत कटौती की गणना के लिए और देशों के लिए अलग-अलग कीमत कटौती की गणना के लिए कुछ गड़बड़ी का सहारा लिया गया है।

- भ. डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.2 पूर्वानुमान किया गया है कि क्षति निर्धारित करने के लिए, जांचकर्ता प्राधिकारियों को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या समग्र रूप से अथवा उत्पादन या खपत के अनुसार पाटित आयातों में भारी वृद्धि हुई है। इस जाँच में बिल्कुल इसके विपरीत हुआ है। यद्यपि खपत में 2012-13 से जाँच अवधि (पीओआई) तक 18 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है तथापि संबंधित देशों से आयातों के स्तर में उसी अवधि के दौरान 23 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों में 2013-14 में 25.747 मी.टन से पीओआई में 15.746 मी.टन तक कमी आई है अर्थात् दोनों भारतीय उत्पादकों ने अपने कार्यकलाप शुरू किए और तेजी से संबद्ध देशों को नुकसान पहुंचाते हुए काफी बाजार हिस्सा हासिल कर लिया। उक्त से देखा जा सकता है कि 2012-13 से पीओआई (विश्लेषण की अवधि) के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में न तो समग्र रूप से और न ही सापेक्ष रूप से (उत्पादन या खपत) की दृष्टि से कोई वृद्धि हुई है। उक्त गतिविधियां कोई क्षतिकारी स्थिति नहीं दर्शाती हैं।
- म. यूरोपीय आयोग ने बताया है कि घरेलू उत्पादकों ने स्वयं यह मान लिया कि किसी बाजार में उनकी केवल स्थापना होने, जो अनेक वर्षों के लिए तीसरे देशों के ही हाथों में रहे, से काफी बाजार हिस्सा प्राप्त हो जाएगा और वे वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद शीघ्र ही लाभ के उच्च स्तर तक पहुंच जाएंगे। आयोग स्पष्ट कारणों के ऐसे तर्कों से सहमत नहीं हो सकता है।
- य. यूरोपीय आयोग ने यह भी बताया है कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर काफी अधिक जोर देता प्रतीत होता है और यह तथ्य कि उद्योग ने पिछले वर्षों में घाटा उठाया है। इस संबंध में पहले यह स्मरण करना चाहिए कि घरेलू उत्पादकों ने अपना उत्पादन क्रमशः अप्रैल 2012 और अप्रैल 2014 अर्थात् बिल्कुल हाल में शुरू किया है। इस संदर्भ में, यह तर्कपूर्ण रूप से नहीं माना जा सकता है कि बाजार में कोई नई कंपनी तत्काल लाभ कमाने लगेगी। उसके विपरीत, शुरूआती लागतों की भरपाई कुछ वर्ष कार्य करने के बाद ही हो पाती है। दूसरा, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की स्थिति उतनी नाटकीय नहीं है जितनी याचिका में बताई गई है। उदाहरणार्थ, 2013-14 से प्रति इकाई घाटे काफी मात्रा में कम हो रहे थे (पीओआई के दौरान इंडेक्स -148 से -99)। घरेलू भारतीय उद्योग के लिए कारोबार की प्रतिशत के रूप में (रेंज या इंडेक्स के रूप में सूचित) व्यक्त लाभप्रदता के वास्तविक स्तर के किसी संकेतक के अभाव में आयोग लाभप्रदता के मुद्दे विशेष के संबंध में अपनी विस्तृत टिप्पणी देने के असमर्थ है।
- र. डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.4 के अनुसार उद्योग पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का मूल्यांकन किया जाएगा और क्षति संबंधी अनेक संकेतकों में किसी एक या अनेक से आवश्यक रूप से क्षति के निष्कर्ष का निर्णायक मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। जाँचकर्ता प्राधिकारी को एतद्वारा केवल कतिपय संकेतकों पर ध्यान देने के लिए नहीं अपितु डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार में यथा सूचीबद्ध सभी संगत क्षति संकेतकों को समुचित महत्व देने के लिए कहा गया है। इन संकेतकों से भी कोई निर्णायक क्षति प्राप्त नहीं होती है।
- ल. बाजार में नए प्रवेशकों की स्थिति को देखते हुए, ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ताओं की स्थिति अनेक पहलुओं के अनुसार संतोषजनक तो नहीं फिर भी उत्साहजनक है। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं ने 42 महीने से कम के रिकार्ड समय में काफी बाजार हिस्सा हासिल कर लिया और पीओआई में 47.84 प्रतिशत घरेलू खपत को पूरा किया। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 2015-16/ तिमाही 2 में 51.66 प्रतिशत तक भी पहुंच गया। यह भी नोट किया जाए कि 2013-14 और पीओआई के बीच बिक्री लागत भी बिक्री कीमत की तुलना में काफी तेजी से घट रही है (-15 प्रतिशत बिंदु बिक्री लागत के लिए जबकि -7 प्रतिशत बिंदु बिक्री कीमत के लिए)। अन्य संकेतक जैसे क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, रोजगार, प्रति कर्मचारी और प्रतिदिन उत्पादकता सभी में विश्लेषण अवधि के दौरान सकारात्मक प्रवृत्ति रही है।
- व. जहां तक भंडार का संबंध है, जाँचकर्ता प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए आमंत्रित हैं कि मालसूची में वृद्धि इस तथ्य से संबंधित नहीं है कि पीओआई का समापन वित्तीय वर्ष की समाप्ति से सह-समाप्त नहीं है जहां सामान्यतया कंपनियां तुलन-पत्र प्रस्तुत करने के प्रयोजनों के लिए अपनी मालसूची को कम करके दिखाती हैं।
- श. कीमत कटौती के संबंध में, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि संबद्ध देशों से आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम रही है। इस संबंध में यह सुझाव दिया जाता है कि नए उत्पादकों के रूप में याचिकाकर्ताओं को उच्चतर लागतों को पूरा

करना और उच्चतर कीमतों पर माल बेचना पड़ता है जो कथित कीमत कटौती को स्पष्ट कर सकता है। किसी भी तरह घरेलू उद्योग की उच्चतर लागत/कीमत से पर्याप्त बाजार हिस्सा प्राप्त करने में कोई रूकावट नहीं आई।

- घ. समग्र रूप से ऐसा लगता है कि घरेलू उद्योग बाजार की पहले की कंपनियों को नुकसान पहुंचाकर घरेलू बाजार में उत्तरोत्तर रूप से स्थापित हो रहा है जैसा अधिकांश क्षति संकेतकों में निरंतर सुधार से साक्ष्यांकित होता है।
- स. संबद्ध देशों से आयातों में भारतीय बाजार में दो घरेलू उत्पादकों के प्रवेश के बाद से विश्लेषण अवधि के दौरान भारी कमी आई है। इस संदर्भ में, यह अस्पष्ट है कि आयातों में इस कमी से कैसे घरेलू उत्पादकों को कथित क्षति में वृद्धि हुई होगी। इसके विपरीत, ऐसा लगता है कि घरेलू उत्पादकों की स्थिति में अनेक तरह से सुधार हो रहा है, जैसा ऊपर दर्शाया गया है। उक्त तत्वों को देखते हुए, भारतीय घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और कोई कथित क्षति किसी भी तरह से आयातों के कारण नहीं हुई है। ऐसे अन्य कारक हो सकते हैं जिनसे घरेलू उत्पादकों की स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ा हो।
- ह. यूरोपीय आयोग ने भी बताया है कि एडीए के अनुच्छेद 3.5 के अनुसार, प्राधिकारी को पाटित आयातों से इतर ऐसे किसी अन्य ज्ञात कारक की भी जाँच करेंगे जिससे उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो और ऐसे अन्य कारकों से हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अंतः, अन्य कारकों का गहराई से विश्लेषण विशेष रूप से आवश्यक है।
- (i) बाजार में दो भारतीय उत्पादकों के हाल के प्रवेश को देखते हुए और उत्पादन लागत, परिवर्तन दरों, स्क्रैप अनुपात, उत्पादकता... से संबंधित विश्वसनीय ऐतिहासिक आकड़ों के अभाव में जाँचकर्ता प्राधिकारी को घरेलू भारतीय उद्योग के ऊपर उल्लिखित प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों की तुलना यह आकलन करने के लिए संबद्ध देशों में लंबे समय से स्थापित उत्पादकों के साथ करनी चाहिए कि क्या घरेलू उत्पादक वास्तव में कुशल ढंग से उत्पादन कर रहे हैं और भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं यद्यपि सोडियम क्लोरेट पर पहले से 7.5 प्रतिशत का आयात शुल्क लागू है और पहले व्यापार संरक्षण के तौर पर कार्य करता है।
- (ii) विश्लेषण की अवधि में घरेलू खपत के स्तर जो 26.159 और 31.718 मी.टन के बीच रही है, को देखते हुए और याचिकाकर्ता द्वारा भारी निर्यातों के स्पष्ट अभाव के मद्देनजर, घरेलू उत्पादकों की क्षमता के संबंध में संदेह किए गए थे (+/- 31.550 मी.टन)। ऐसा लगता है कि अन्य बाजार कंपनियों की ऐतिहासिक उपस्थिति को देखते हुए, घरेलू भारतीय उत्पादक स्थापित की जाने वाली क्षमता के स्तर का अनुमान लगाते समय यदि धारणा रखने वाले नहीं तो लापरवाह रहे हैं। उक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि बाजार की सीमा की तुलना में स्थापित क्षमता अधिक प्रतीत होती है और यह कि ऐसा अधिक अनुमान अधिक स्थिर लागतों का कारण बनता है जिससे घरेलू उद्योग के वित्तीय कार्यनिष्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- (iii) शुरुआती लागतें और अन्य कारक अंतर्निहित रूप से किसी उत्पादन कार्यकलाप की शुरुआत को उसकी सामान्य गति में पहुंचने से पहले प्रभावित करते हैं, उनका भी विश्लेषण किया जाना चाहिए क्योंकि उनके विस्तार से घरेलू उद्योग के वित्तीय कार्यनिष्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारतीय प्राधिकारी को इसलिए कतिपय दस्तावेजों के अगोपनीय अंश की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान देना चाहिए ताकि सभी हितबद्ध पक्ष रक्षा संबंधी अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। आयोग भारतीय प्राधिकारियों से केवल कतिपय एकल संकेतकों पर ध्यान न देकर आयातों के समग्र और सापेक्ष मूल्यांकन सहित क्षति संबंधी सभी कारकों का समग्र मूल्यांकन करने और का भी अनुरोध करता है। भारतीय प्राधिकारियों को भी याचिकाकर्ता के वास्तविक कार्यनिष्पाद की लंबे समय से स्थापित याचिकाकर्ताओं के साथ तुलना करने के लिए आमंत्रित किया जाता है ताकि यह आकलन हो सके कि क्या घरेलू उद्योग कुशलता से कार्य कर रहा है और वास्तव में प्रतिस्पर्धी हो सकता है। अन्य कारकों के प्रभाव का भी पूर्णतः विश्लेषण किया जाना चाहिए।

#### **छ. प्राधिकारी द्वारा जाँच**

24. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जाँच की है।
25. पाटनरोधी नियमावली में प्राधिकारी के लिए मात्रा और कीमत प्रभाव दोनों की जाँच करना अपेक्षित है। क्षति के निर्धारण में इन दोनों की तथ्यपरक जाँच की व्यवस्था है, (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जाँच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात

की जाँच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती।

26. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के पैरा (iv) में निम्नानुसार व्यवस्था है : -

*"(iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"*

27. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदंडों में खराबी प्रदर्शित हो। कुछ मापदंडों में खराबी दिख सकती है जबकि कुछ में सुधार हो सकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी क्षति संबंधी सभी मापदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन से कोई क्षति हुई है अथवा नहीं।

28. प्राधिकारी ने अनुरोधों में तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की वस्तुनिष्ठ ढंग से जाँच की है।

### **छ.3.1 संचयी आकलन**

29. संचयी आकलन के संबंध में नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (iii) में निम्नानुसार उपबंध है :

*ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटनरोधी जाँच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयात के साथ सबसे अधिक बनता है; तथा (ख) आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।*

30. वर्तमान मामले में एक से अधिक स्रोतों से संबद्ध वस्तु के संबंध में जाँच हुई है। अंतः प्राधिकारी ने इन देशों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी मूल्यांकन किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि

- क. संबद्ध देशों में से प्रत्येक से विचाराधीन उत्पाद के पाटन का मार्जिन ऊपर विहित सीमाओं से अधिक है;
- ख. संबद्ध देशों में से प्रत्येक से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा ऊपर विहित सीमाओं से अधिक है;
- ग. प्राधिकारी को प्रस्तुत सूचना तर्कसंगत संकेत करती है कि संबद्ध देशों से निर्यात परस्पर और समान बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए वे समान उत्पाद हैं।

31. उक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी मानते हैं कि आयातित उत्पाद और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की दशाओं के आलोक में घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के प्रभावों का संचयी आंकलन करना उचित होगा।

### **क. मांग का आकलन**

32. इस प्रयोजनार्थ, भारत में उत्पाद की स्पष्ट मांग या खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में लिया गया है। भारत में मांग/खपत में संबद्ध देशों में से प्रत्येक के आयातों का हिस्सा प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है -

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	1,725	4,612	11,496	15,699
संबद्ध देश से आयात	एमटी	21,233	25,184	20,118	15,849
कनाडा	एमटी	525	2,982	3,964	1,078
चीन	एमटी	7,573	11,650	1,918	975
यूरोपीय संघ	एमटी	13,135	10,552	14,235	13,797
अन्य देश	एमटी	3,844	1,870	158	571
कुल मांग	एमटी	26,802	31,666	31,772	32,118

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है।

### ख.3.2 पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव - आयात मात्रा और संबद्ध देशों का हिस्सा

34. पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभावों के संबंध में, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदत्त सौदा-वार आयात आकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों और अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा की जाँच की है। संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा और क्षति जाँच अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
संबद्ध देश	मी.टन	21,233	25,184	20,118	15,849
कनाडा	मी.टन	525	2,982	3,964	1,078
चीन	मी.टन	7,573	11,650	1,918	975
ईयू	मी.टन	13,135	10,552	14,235	13,797
अन्य देश	मी.टन	3,844	1,870	158	571
कुल आयात	मी.टन	25,077	27,054	20,276	16,420
कुल आयातों में आयातों का हिस्सा					
संबद्ध देशों का हिस्सा	%	85%	93%	99%	97%
अन्य देशों का हिस्सा	%	15%	7%	1%	3%
निम्न के संबंध में संबद्ध देश के आयात					
भारतीय उत्पादन	%	1228%	534%	174%	103%
खपत	%	79%	80%	63%	49%

35. 2013-14 में आयातों में वृद्धि हुई है और उसके बाद घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के कारण उनमें कुछ हद तक गिरावट आना शुरू हुई। तथापि, घरेलू उत्पादन के शुरू होने के बावजूद, आयात पूरी क्षति अवधि में अधिक बने रहे। लगभग समस्त आयात संबद्ध देशों से हुए हैं। इसके अलावा, उत्पादन और खपत की दृष्टि से आयात पीओआई में भी काफी अधिक रहे हैं।

### छ.3.3 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के कीमत प्रभाव

36. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नानुसार निर्धारित है :

"जहां तक नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।"

37. इस बात की जाँच की गई कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

#### कीमत कटौती

38. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ की है। इस संबंध में, संबद्ध देशों में से प्रत्येक से उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच सभी छूटों और करों के निवल पर व्यापार के समान स्तर पर तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमत को कारखाना-द्वार स्तर पर निर्धारित किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	चीन	कनाडा	ईयू	संबद्ध देश
1	पहुंच कीमत	रु./मी.टन	45,290	43,974	41,801	42,163
2	निवल बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
3	कीमत कटौती	रु./मी.टन	(***)	(***)	(***)	(***)
4	कीमत कटौती	%	(10-20%)	(0-10%)	(0-10%)	(0-10%)

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत कटौती नकारात्मक है जिसके लिए घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उनके पास पहुंच कीमत के बराबर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

#### कम कीमत पर बिक्री

40. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा की गई कम कीमत पर बिक्री की भी जाँच की है। इस प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित बिक्री लागत की तुलना आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है। कीमत कटौती के प्रयोजनार्थ विचार की गई आयातों की पहुंच कीमत को कम कीमत पर बिक्री निर्धारित करने के लिए भी अपनाया गया है। घरेलू उद्योग की भारित औसत बिक्री लागत के साथ आयातों की भारित औसत पहुंच कीमत की तुलना से निम्नानुसार पता चलता है :

क्र.सं.	विवरण	इकाई	चीन	कनाडा	ईयू	संबद्ध देश
1	पहुंच कीमत	रु./मी.टन	45,290	43,974	41,801	42,163
2	क्षतिरहित कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
3	कम कीमत पर बिक्री	रु./मी.टन	***	***	***	***
4	कम कीमत पर बिक्री	%	30-40%	30-40%	40-50%	40-50%

41. यह नोट किया जाता है कि आयातों की पंहच कीमत घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम रही है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण कम कीमत पर बिक्री करनी पड़ी है।

#### **कीमत ह्रास और न्यूनीकरण**

42. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक ह्रास हुआ है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों पर विचार किया है। यह स्थिति नीचे तालिका के अनुसार दर्शाई गई है।

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
बिक्री लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	93	90	69
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	80	77	71

43. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में पूरी क्षति अवधि में गिरावट आई है। तथापि, बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट से काफी अधिक रही है। बिक्री कीमत पूरी क्षति अवधि के दौरान उत्पादन लागत के स्तर से कम रही है। इस प्रकार, आयातों से घरेलू बाजार में घरेलू कीमतों पर ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव का पता चलता है।

#### **छ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव**

44. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है :-

#### **क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां**

45. उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है :

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
क्षमता-संयंत्र	मी.टन	11,500	11,500	31,500	31,500
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	274	274
उत्पादन	मी.टन	1,729	4,712	11,543	15,454
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	273	668	894
क्षमता उपयोग	%	15%	41%	37%	49%
बिक्री मात्रा	मी.टन	1,725	4,612	11,496	15,699
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	267	666	910

46. यह नोट किया जाता है कि दोनों याचिकाकर्ता कंपनियों ने हाल में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। अतः घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन शुरू करने के परिणामस्वरूप वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में भी वृद्धि हुई परंतु यह ईष्टतम से कम रहा।

**ख) लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ**

47. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, बिक्री कीमत, लाभ/हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है :

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
बिक्री लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
लाभ/(हानि) प्रति इकाई	रु./मी.टन	(***)	(***)	(***)	(***)
लाभ/(हानि) -कुल	लाख रु.	(***)	(***)	(***)	(***)
नकद लाभ	लाख रु.	(***)	(***)	(***)	(***)
ब्याज और कर पूर्व लाभ	लाख रु.	(***)	(***)	(***)	(***)
निवेश पर आय	%	(***)	(***)	(***)	(***)

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को लाभ, ब्याज पूर्व लाभ और नकद लाभों की दृष्टि से वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है। नियोजित पूंजी पर आय में भी क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है और पूरी क्षति अवधि में उसका नकारात्मक स्तर बना रहा है।

**ग) मांग में बाजार हिस्सा**

49. घरेलू उद्योग की मांग में बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभावों की निम्नानुसार जाँच की गई है :

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
संबद्ध देशों के आयात	%	79.22	79.53	63.32	49.35
अन्य देशों के आयात	%	14.34	5.91	0.50	1.78
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	%	6.44	14.56	36.18	48.88
कुल	%	100	100	100	100

50. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में उत्पादन की शुरुआत के साथ वृद्धि हुई है। तथापि संबद्ध आयातों के पास काफी बाजार हिस्सा है और यह कि घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता भी है। इससे पता चलता है कि उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग, जिसने अभी हाल में ही उत्पादन शुरू किया है का बाजार हिस्सा प्रभावित हो रहा है।

**घ) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता**

51. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है :

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
कर्मचारियों की सं.	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	136	136
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	132	206	176
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन/सं.	***	***	***	***
प्रतिदिन उत्पादकता	मी.टन/दि.	***	***	***	***

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रोजगार का स्तर बढ़ा है और इसी प्रकार मजदूरी का स्तर भी। इसके अलावा, प्रतिदिन और प्रतिकर्मचारी उत्पादकता में भी क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।

**ङ) मालसूची**

53. संबद्ध वस्तु की मालसूची से संबंधित आकड़े नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं :

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
आरंभिक स्टाक	मी.टन	***	***	***	***
अंतिम स्टाक	मी.टन	***	***	***	***
औसत स्टाक	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	967	2,567	10,114

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची के स्तर में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है।

**च) पाटन की मात्रा**

55. यह नोट किया जाता है कि प्रत्येक संबद्ध देश से आयात पाटित कीमतों पर देश में प्रवेश कर रहे हैं और पाटन का मार्जिन विहित न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक है।

**छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता**

56. याचिकाकर्ताओं ने यह बताया है कि उन्होंने देश में भारी मांग को देखते हुए पहले ही क्षमता विस्तार की योजना बनाई है। पर्यावरण अनुमोदन और अन्य सांविधिक अनुमोदन पहले ही ले लिए गए हैं। तथापि, घरेलू उद्योग को पाटन से क्षति होने के कारण, विस्तार पर कार्य नहीं हो रहा है। इससे पता चलता है कि पूंजी निवेश जुटाने की याचिकाकर्ता की क्षमता प्रभावित हो रही है।

**ज) वृद्धि**

57. घरेलू उद्योग की वृद्धि से संबंधित आकड़ों को नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

वृद्धि	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
उत्पादन	वर्षवार	-	173%	145%	34%
घरेलू बिक्री	वर्षवार	-	167%	149%	37%
बिक्री लागत	वर्षवार	-	-7%	-3%	-23%
बिक्री कीमत	वर्षवार	-	-20%	-3%	-8%
लाभ/हानि	वर्षवार	-	295%	139%	-43%
निवेश पर आय	वर्षवार	-	-462%	12%	52%
नकद लाभ	वर्षवार	-	-335%	-77%	78%

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की वृद्धि कुछ मापदंडों में कमतर हुई है।

**झ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

59. संबद्ध देशों से आयात कीमतों, लागत संरचना में बदलाव, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक जिनकी वजह से घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हुई हैं की जाँच से पता चलता है कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पंहुच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत से कम रहा है, जिससे भारतीय बाजार में भारी कम कीमत पर बिक्री हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की कीमत सामान्यतया प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमतों की लय में होनी चाहिए और घरेलू उद्योग को इन निविष्टि कीमतों और आयातों की पंहुच कीमत पर विचार करते हुए अपनी कीमतों को निर्धारित कर रहा है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चूंकि उन्होंने हाल में उत्पादन शुरू किया है इसलिए घरेलू उद्योग के पास बाजार कीमतों, जो संबद्ध देशों में विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित कीमतों द्वारा तय हो रही हैं, से तालमेल बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पंहुच मूल्य घरेलू कीमतों को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है।

**छ.3.5 अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध**

60. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अधीन ऐसे सूचीबद्ध अन्य कारकों को नोट किया है जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो ताकि पाटन और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जाँच की जा सके।

**तीसरे देशों से आयात**

61. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त संबद्ध वस्तु के आयात आकड़ों की सौदा-वार आधार पर जाँच की है और नोट करते हैं कि लगभग पूरे आयात अन्य देश से आयात की तुलना में संबद्ध देशों से हुए हैं।

**मांग में संकुचन**

62. संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है इसलिए मांग में संभावित गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

**व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा**

63. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

**प्रौद्योगिकी में विकास**

64. घरेलू उद्योग द्वारा अंतिम उत्पाद के उत्पादन के संबंधी में अपनायी जाने वाली मौजूदा प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया विदेशी उत्पादकों से तुलनीय है।

**खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन**

65. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है।

**निर्यात कार्यनिष्पादन**

66. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। इस प्रकार घरेलू उद्योग को क्षति केवल घरेलू प्रचालनों के कारण हुई है।

**अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन**

67. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के कार्यनिष्पादन से घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन का प्राधिकारी द्वारा किया गया आकलन प्रभावित नहीं हुआ है। प्राधिकारी द्वारा विचार की गई सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में है।

**घरेलू उद्योग की उत्पादकता**

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। उत्पादकता ने गिरावट घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

**कारणात्मक संबंध सिद्ध करने वाले कारक**

69. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण विकृति आई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर सिद्ध किया गया है :

- क. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू करने के बावजूद पाटित आयातों की मात्रा काफी अधिक बनी रही है।
- ख. पाटित आयातों के कारण हुई कीमत कमी से घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने को बाध्य होना पड़ा है।
- ग. संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कीमत ह्रास प्रभाव के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के वित्तीय घाटे में भारी वृद्धि हुई है।
- घ. घरेलू उद्योग को क्षमताओं की मात्रा और देश में भारी मांग और क्षमताओं की मौजूदगी के बावजूद अपने उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में वृद्धि से रोका गया है।
- ङ. वित्तीय घाटे और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय पाटित आयातों का सीधा परिणाम है।
- च. घरेलू उद्योग की वृद्धि अनेक आर्थिक मापदंडों के अनुसार ऋणात्मक हो गई है।
- छ. घरेलू उद्योग की मालसूची में भारी वृद्धि हुई है।
- ज. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने कच्ची सामग्री और उपयोग के सर्वोत्तम खपत मानकों पर विचार किया है। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-111 के प्रावधान के अनुसार अन्य कारकों की वजह से घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति को अलग और बाहर किया है।

**ज. क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन**

70. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 111 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के लिए यथा निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना जाँच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देश से आयातों के पंधुच मूल्य के साथ की गई है और इस प्रकार ज्ञात क्षति मार्जिन निम्नानुसार बनता है :

विवरण	इकाई	कनाडा	चीन	ईयू	
				अर्केमा	अन्य
क्षतिरहित कीमत (एनआईपी)	अम.डा./मी.टन	***	***	***	***
पंधुच कीमत	अम.डा./मी.टन	***	***	***	***

क्षति मार्जिन	अम.डा./मी.टन	***	***	***	***
क्षति मार्जिन %	%	***	***	***	***
क्षति मार्जिन (रेंज)	%	30-40	30-40	50-60	50-60

71. यह देखा जाता है कि प्रत्येक संबद्ध देश के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

#### झ. प्रयोक्ता उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

72. भारतीय पेपर विनिर्माता एसोसिएशन ने निम्नानुसार अनुरोध किया है :

क. पल्प और पेपर उद्योग काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, काफी बड़ी हुई कच्ची सामग्री और निविष्टि और ऊर्जा की लागत और भारत द्वारा हस्ताक्षरित विभिन्न मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) के अधीन रियायती/शून्य आयात शुल्क पर तैयार उत्पादों के आयातों से घरेलू बाजार में काफी आक्रामक प्रतिस्पर्धा के वर्तमान परिदृश्य में अस्तित्व बचाना काफी मुश्किल है। पल्प और पेपर उद्योग ने पिछले 5 वर्षों में काफी निवेश किया है और मार्जिनों में काफी गिरावट के कारण वित्तीय दायित्वों को पूरा करना काफी कठिन हो गया है। जैसी आज की स्थिति है, क्षमता में मौजूदा निवेश आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो गया है। 2/3 बड़ी पेपर मिलें पिछले दो वर्षों में बंद हो गई हैं। और यदि सरकार द्वारा तत्काल कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो डर है कि कुछ अन्य मिलों को भी बंदी का सामना करना पड़ सकता है। इससे न केवल सरकार को राजस्व का घाटा होगा बल्कि ऐसे उद्योग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिसका कृषक समुदाय से काफी मजबूत बैकवार्ड संबंध है और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रोजगार सृजित करता है।

ख. भारतीय पल्प और पेपर उद्योग दिनांक 12 मई, 2016 की अधिसूचना द्वारा कनाडा, चीन जनवादी गणराज्य और ईयू के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम क्लोरेट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरुआत से काफी चिंतित है, क्योंकि पल्प और पेपर उद्योग सोडियम क्लोरेट का एक प्रमुख उपभोक्ता है और कुछ पेपर मिलें मै. गुजरात अल्कली एंड कैमिकल्स लि. (जीएसीएल) और मै.टीमेक क्लोरेट्स लि. (टीसीएल) के उत्पादन शुरू करने से पहले भी उसका आयात कर रही हैं।

- अनेक पेपर मिलों ने पल्प की ब्लीचिंग के लिए खतरनाक तरल क्लोरीन से बचने के लिए इसका प्रयोग समाप्त कर दिया है और उसके स्थान पर सोडियम क्लोरेट का प्रयोग शुरू कर दिया है। संशोधित प्रक्रिया में, क्लोरिन डायआक्साइड को सोडियम क्लोरेट से उत्पादित किया जाता है जिसका प्रयोग पल्प की ब्लीचिंग और पर्यावरण अनुकूल और एलीमेंटल क्लोरीन मुक्त (ईसीएफ) पेपर के उत्पादन में किया जाता है। अनेक अन्य पेपर मिलें भी पल्प की ईसीएफ ब्लीचिंग के लिए प्रक्रिया अपनाने हेतु कार्य कर रही हैं।
- कनाडा, चीन जन. गण. और ईयू से आयातित सोडियम क्लोरेट की शुद्धता घरेलू बाजार में उपलब्ध सोडियम क्लोरेट से काफी अधिक है। आयातित सोडियम क्लोरेट के लिए मासिक रनिंग साइकल भी बेहतर है जो घरेलू रूप से उत्पादित सोडियम क्लोरेट के लिए 35 के मुकाबले 45 दिनों का है।
- खतरनाक मद होने के कारण सोडियम क्लोरेट जो शस्त्र अधिनियम के अधीन आता है, को अन्य सामग्रियों की तरह घरेलू बाजार में पाटित नहीं किया जा सकता है क्योंकि केवल लाइसेंस वाले उपभोक्ता ही इसका स्वयं के प्रयोग हेतु प्रयोग कर सकते हैं।
- वर्तमान में, आयातित सोडियम क्लोरेट की कीमत घरेलू रूप से उत्पादित सोडियम क्लोरेट के बराबर है और ऐसी उम्मीद है कि सोडियम क्लोरेट के आयातों पर किसी पाटनरोधी शुल्क के लागू होने से उसकी घरेलू कीमतों में भी वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप इससे घरेलू पल्प और पेपर उद्योग की समग्र विनिर्माण लागत और बढ़ जाएगी और वे कम मार्जिन और कम हो जाएंगे जिनके अधीन इस समय उद्योग कार्य कर रहा है।
- समग्र रूप से पेपर के अंतिम उपभोक्ताओं और विशेष रूप से सर्व शिक्षा अभियान के अधीन स्कूली बच्चों के हितों की रक्षा के लिए यह अनुरोध किया जाता है कि सोडियम क्लोरेट के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का विचार तब तक नहीं किया जाए जब तक देश में मांग-पूर्ति का अंतर समाप्त न हो जाए।

**प्राधिकारी द्वारा जॉच**

73. प्राधिकारी प्रयोक्ताओं के अनुरोधों को नोट करते हैं और यह मानते हैं कि सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा कायम हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होगा और इसलिए उपभोक्ताओं इस उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

74. प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से भारत में इस उत्पाद के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है परंतु ऐसे पाटनरोधी उपायों का अधिरोपण करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से पाटन की प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ कम होगा, घरेलू उद्योग का पतन होने से रुकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में सहयोग मिलेगा। उपभोक्ता अभी भी इस उत्पाद की आपूर्ति के दो अथवा उससे अधिक स्रोत बनाए रख सकते हैं।

**प्रकटन पश्चात टिप्पणियां :**

75. घरेलू उद्योग और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित प्रकटन पश्चात टिप्पणियां की हैं :

(i) घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- एनआईपी का निर्धारण घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि निर्धारित एनआईपी का विस्तृत ब्यौरे को पूरी तरह से प्रकट किया जाए जिसमें (i) अस्वीकृत खर्चें, (ii) दावा की गई उत्पादन लागत में किए गए समायोजन, (iii) लगाई गई पूंजी में किए गए कोई संशोधन शामिल हैं, ताकि याचिकाकर्ता उस पर टिप्पणियां दे सकें।
- प्राधिकारी परिकलित पाटन मार्जिन के संबंध में सार्थक टिप्पणियां देने के लिए संबद्ध देश से निर्यातकों/आयातकों की सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय रूपांतर प्रकट करें।
- प्राधिकारी कृपया विरोधी हितबद्ध पक्षकारों को भेजे गए ई-मेल अथवा पत्र के द्वारा सभी पत्रों और इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए उत्तरों की प्रति उपलब्ध कराए। याचिकाकर्ता किसी गोपनीय सूचना का अनुरोध नहीं कर रहा है। याचिकाकर्ता केवल इस सूचना की एनसीवी के लिए अनुरोध कर रहा है।
- चूंकि सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के आंकड़ों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध/प्रयुक्त सूचना के आधार पर है, अतः उसे प्रकट किया जाए।
- प्राधिकारी वास्तविक पाटन मार्जिन प्रकट करें। वास्तविक पाटन मार्जिन निम्नलिखित कारणों से इस मामले में गोपनीय नहीं हो सकता।
- प्रतिभागी निर्यातक के मामले में- चूंकि क्षति मार्जिन पाटन मार्जिन की अपेक्षा बहुत अधिक है, तथापि, किसी भी स्थिति में एक बार जब निर्दिष्ट प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम जारी करे तो तभी हितबद्ध पक्षकार निर्धारित वास्तविक पाटन मार्जिन जान पाएंगे। उस स्तर पर जो गोपनीय नहीं रहेगा, इस स्तर पर वह गोपनीय नहीं हो सकता।
- अन्य सभी मामलों में-चूंकि सूचना याचिकाकर्ता/घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर है, अतः वह गोपनीय नहीं है।
- चूंकि क्षति विश्लेषण में लिए गए वास्तविक आंकड़े घरेलू उद्योग से संबंधित हैं, अतः उसे घरेलू उद्योग को प्रकट किया जाए। वस्तुतः इसे विगत में घरेलू उद्योग को प्रकट किया गया है।
- उपर्युक्त घरेलू उद्योग के लिए प्रकटन विवरण के संबंध में अपनी सार्थक टिप्पणियां पेश करने के लिए महत्वपूर्ण है। तथापि, इस प्रकार के प्रकटन तक घरेलू उद्योग प्रकटन विवरण के संबंध में निम्नलिखित प्राथमिक अनुरोध करता है। घरेलू उद्योग जब भी उपर्युक्त अनिवार्य तथ्य प्रकट किए जाएं तो और अधिक अनुरोध करने के लिए छूट की मांग करता है।
- याचिकाकर्ता प्रकटन विवरण से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उत्पादक भारत में संबद्ध सामानों के केवल घरेलू उत्पादक हैं; विचाराधीन उत्पाद सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किए जाते हैं, परिणामस्वरूप प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन होता है। निर्धारित पाटन मार्जिन बहुत कम है; घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है तथा यह क्षति संबद्ध देशों से पाटन आयातों के प्रतिकूल कीमत प्रभाव से सिद्ध है। घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले पाटन से बचने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है।

- प्राधिकारी ने नोट किया है कि एक प्रमुख प्रयोक्ता उद्योग ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता केवल संबद्ध सामानों के 2 घरेलू उत्पादक हैं अतः घरेलू उद्योग के आधार पर टिप्पणियों को दोहराया गया है। याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध सामानों का न तो आयात किया है और न वे किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित हैं और इस प्रकार पात्र घरेलू उद्योग हैं एवं पाटनरोधी नियमावली की शर्तों में आधार के प्रावधान को पूर्ण करते हैं।
- चीनी उत्पादकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन बहुत कम है। याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में सामान्य मूल्य के परिकलन को प्रकट करने का अनुरोध किया था। यद्यपि, उपर्युक्त परिकलन अभी तक याचिकाकर्ताओं को प्रकट नहीं किए गए हैं, तथापि याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना और प्रकटन विवरण में निहित सूचना का विश्लेषण स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण जीएसीएल के लिए निर्धारित एनआईपी के आधार पर किया है। तथापि, याचिकाकर्ता अनुरोध करते हैं कि अकेले जीएसीएल के आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित कारणों से वर्तमान मामले में अनुचित है।
  - विचाराधीन उत्पाद हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करता है। जबकि जीएसीएल हाइड्रोजन पैराऑक्साइड के उत्पादन में इस हाइड्रोजन गैस को लेता है। टीमक हाइड्रोजन गैस को नहीं लेता और उसे जाने देता है। चीनी उत्पादक के प्रचालनों के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अनुसंधान यह दर्शाता है कि ऐसे चीनी उत्पादक हैं जो हाइड्रोजन का उपयोग नहीं करते। चूंकि चीन में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक मौजूद हैं जो किसी अन्य उत्पाद के उत्पादन में हाइड्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, अतः इस अवधारणा पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कि चीनी उत्पादक हाइड्रोजन का उत्पादन कर रहे हैं और निचले स्तर के उत्पाद के उत्पादन में उसी का उपयोग कर रहे हैं, निराधार है। याचिकाकर्ता प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे केवल टीमक से संबंधित आंकड़ों/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की कृपा करें। याचिकाकर्ता इस संबंध में नियम 6(8) का उल्लेख करते हैं।
  - सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना का क्षेत्र भी डब्ल्यू टी ओ करार में अच्छी तरह से स्पष्ट कर लिया गया है। अतः यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सहयोग नहीं करता और इस प्रकार कोई संगत सूचना प्राधिकारी से रोकी जा रही है तो ऐसी स्थिति से वह परिणाम निकलेगा जोकि पक्षकार को सहयोग न करने की अपेक्षा कम अनुकूल हो।
  - माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी फेयरडील पोलिकैम एनआईपी बनाम भारत संघ तथा अंडमान निकोबार के मामले में माना है कि डब्ल्यूटीओ करार प्रत्यक्ष रूप से प्राधिकारी पर लागू है। इस प्रकार, भारतीय नियमावली में संगत प्रावधान न होने की स्थिति में, जैसा कि डब्ल्यूटीओ करार के तहत निर्धारित है, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि नियम 6(8) के क्षेत्र का अभिप्राय यह है कि यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सहयोग नहीं करता और इस प्रकार कोई संगत सूचना (इस मामले में सामान्य मूल्य संबंधी सूचना) प्राधिकारी को नहीं दी जा रही है तो ऐसी स्थिति से वह परिणाम निकलेगा जोकि पक्षकार को सहयोग न करने की अपेक्षा कम अनुकूल हो। अतः प्राधिकारी को निर्यातकों के संबंध में प्रतिकूल हस्तक्षेप करने और निर्यातकों के संबंध में अनुकूल हस्तक्षेप न करने की अपेक्षा है। दूसरे शब्दों में प्राधिकारी को निर्यातकों के असहयोग के कारण घरेलू उद्योग को दंड नहीं देना चाहिए तथा असहयोग के लिए निर्यातकों को पुरस्कार नहीं देना चाहिए।
  - पाटनरोधी शुल्क निर्धारित मात्रा के आधार पर –डॉलर में लगाया जाए।

(ii) मै. अरकेमा, फ्रांस ने निम्नलिखित अनुरोध किया है :

- अरकेमा, फ्रांस की ओर से मै. जीआईडीई द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां विशेष रूप से पाटन मार्जिन परिकलन और भारतीय प्राधिकारियों के अपर्याप्त प्रकटन के लिए त्रुटिपूर्ण आधार, चीनी उत्पादकों के असहयोग, और क्षति विश्लेषण के संबंध में हैं।
- "अरकेमा सीवी ऑन डीएम डॉक्स" नामक अरकेमा फ्रांस से संबंधित पाटन परिकलन के संबंध में गोपनीय प्रकटन विवरण में निर्धारित किए गए अनुसार पाटन राशि \*\*\* मी.ट. पाई गई है। यह मात्रा दूरभाष पर की गई पूछताछ के आधार पर 12 प्रतिशत पुष्ट की गई थी।
- प्रथमतः सामान्य प्रकटन के भाग के रूप में भारतीय प्राधिकारियों से प्राप्त दस्तावेज (गोपनीय एवं अगोपनीय दस्तावेज दोनों) चीनी उत्पादकों अथवा घरेलू उद्योग जैसे, कार्बाई में अन्य पक्षकारों से संबंधित हमारे ग्राहक अथवा जांच परिणामों के लिए पाटन मार्जिन का परिकलन करने हेतु भारतीय प्राधिकारियों द्वारा प्रयुक्त सिद्धांत को पूर्णतः समझने के लिए अपर्याप्त हैं।

- दूसरे हमारे ग्राहक अर्केमा फ्रांस के लिए परिकलित पाटन मार्जिन के संबंध में विशेष रूप से यह स्पष्ट नहीं है कि \*\*\* की मात्रा लगभग \*\*\* के पाटन मार्जिन के समतुल्य कैसे है। प्रकटन दस्तावेजों से तथा भारतीय प्राधिकारियों के साथ आगे के पत्राचार से यह दिखाई देता है कि पाटन मार्जिन का परिकलन सीआईएफ कीमत के बजाए कार्योत्तर निर्यात कीमत के आधार पर किया गया था।
- तथापि, यह परिपाटी डब्ल्यूटीओ करारों के प्रावधानों तथा डब्ल्यूटीओ सदस्यों की सामान्य रूप से स्वीकृत परिपाटी के विरुद्ध है। डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार ("एडीए") के अनुच्छेद 7.2 में यह उल्लेख है कि "अनंतिम उपाय अनंतिम शुल्क का रूप ले सकते हैं अथवा अधिमानतः नकद जमा अथवा बॉण्ड जो अनंतिम रूप से अनुमानित पाटनरोधी शुल्क की राशि के बराबर हो, द्वारा सुरक्षा हो जोकि पाटन के अनंतिम रूप से अनुमानित मार्जिन से अधिक न हो। मूल्यांकन को बनाए रखना एक उपयुक्त अनंतिम उपाय है; बशर्ते कि सामान्य शुल्क और पाटनरोधी की अनुमानित मात्रा दर्शायी जाए और मूल्यांकन को बनाए रखने तक अन्य अनंतिम उपायों के रूप में उन्हीं स्थितियों के अधीन हो।"
- इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुच्छेद 9.3 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि "पाटनरोधी शुल्क की राशि अनुच्छेद 2 के तहत स्थापित पाटन के मार्जिन से अधिक नहीं होगी।"
- पाटन मार्जिन के परिकलन के लिए आधार के रूप में कार्योत्तर निर्यात कीमत, जोकि स्वाभाविक रूप से सीआईएफ कीमत से कम है, का प्रयोग करते हुए भारतीय प्राधिकारियों ने लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क के स्तर को कृत्रिम रूप से बढ़ाया है, जोकि अब हमारे ग्राहक अर्केमा फ्रांस के लिए स्थापित पाटन मार्जिन के स्तर से अधिक है।
- अर्केमा की प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट-2 में जांच की अवधि में भारत को अलप्योर एक्स की सारी बिक्री के व्यौरे हैं। इस परिशिष्ट में औसत सीआईएफ कीमत 591,03 है। इस सीआईएफ कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन \*\*\*% (\*\*\*%) है। हम मानते हैं कि सीआईएफ कीमत पाटन मार्जिन के परिकलन के लिए उचित आधार है क्योंकि यही वह कीमत है जिसके आधार पर भारतीय सीमाशुल्क प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाएंगे। लगभग \*\*\*% शुल्क लगाने का अभिप्राय यह होगा कि शुल्क पाटन मार्जिन से अधिक है। भारतीय प्राधिकारियों द्वारा प्रयुक्त यह परिपाटी स्पष्टतः डब्ल्यूटीओ एडीए के प्रावधानों के विपरीत है। अतः हम यह मानते हैं कि प्रस्तावित शुल्क उपर्युक्त परिकलन पद्धति को दर्शाने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए।
- अगोपनीय सामान्य प्रकटन दस्तावेज में यह दर्शाया गया है कि जांच में किसी भी चीनी उत्पादक ने सहयोग नहीं किया और यह कि पाटन परिकलन भारतीय प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों पर किया गया था। तथापि, जांच द्वारा संबंधित अन्य विदेशी उत्पादकों की तुलना में चीनी उत्पादकों ने न्यूनतम पाटन मार्जिन (0-10%) प्राप्त किया है जबकि अर्केमा फ्रांस सहित अन्य उत्पादकों का पाटन मार्जिन 10% और 30% के बीच है।
- यह जांच परिणाम अर्केमा फ्रांस के लिए विशेष रूप से हतप्रभ करने वाला था क्योंकि हमारे ग्राहक ने भारतीय प्राधिकारियों के साथ अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ सहयोग किया। जैसा कि सामान्य प्रकटन में भी उल्लेख किया गया है कि हमारे ग्राहक ने मांगी गई समस्त सूचना आपको दी और प्राप्त समस्त आंकड़े अर्केमा फ्रांस के परिसरों में की गई सत्यापन यात्रा के दौरान सत्यापित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, जैसाकि प्रकटन दस्तावेजों में भारतीय प्राधिकारियों द्वारा स्वयं ही पुष्ट भी किया गया है, अर्केमा फ्रांस भारतीय प्राधिकारियों के साथ इस सीमा तक सहयोग करने के लिए एकमात्र विदेशी उत्पादक था।
- यह नोट किया जाना चाहिए कि उपर्युक्त परिणाम डब्ल्यूटीओ करारों की भावना के अनुरूप नहीं है, जोकि सहयोगी उत्पादकों की अपेक्षा असहयोगी उत्पादकों को अधिक अनुकूल परिणाम प्रदान करने के विचार का समर्थन नहीं करते। इसके अतिरिक्त, यह उस प्रोत्साहन को भी नहीं लेता जो एक विदेशी उत्पादक भारत द्वारा शुरू की गई भावी जांचों के साथ सहयोग करने के लिए हो, यदि यह स्पष्ट है कि असहयोगी उत्पादकों को अधिक अनुकूल परिणाम प्रदान करने के लिए यह भारत की परिपाटी है।
- अर्केमा फ्रांस मानता है कि चीनी उत्पादकों के संबंध में विशेष रूप से सामान्य मूल्य में पाटन मार्जिन के परिकलन के सिद्धांत के संबंध में प्रकट की गई सूचना पर्याप्त है। उदाहरण के लिए सामान्य प्रकटन दस्तावेज में उल्लेख है कि चीनी

निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य "प्रमुख कच्ची सामग्री और उपयोगी वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग के इष्टतम खपत मानदंडों पर विचार करके" उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर निर्मित किया गया था। इस प्रकार की अस्पष्ट शर्तें किए गए परिकलनों के पीछे सिद्धांतों को समझने हेतु कार्रवाई में अन्य हितवद्ध पक्षकारों को अनुमति नहीं देती। वास्तव में, "इष्टतम" शब्द यह बता सकता है कि अधिकतम अनुकूल खपत मानदंडों का प्रयोग किया गया है जिसके परिणामस्वरूप असहयोगी चीनी निर्यातकों के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिणाम आए हैं।

- अतः अर्केमा फ्रांस मानता है कि चीनी निर्यातकों के लिए परिकलन तथा अंतिम जांच परिणाम में संशोधन की आवश्यकता है।
- सामान्य अगोपनीय प्रकटन दस्तावेज के आधार पर क्षति एवं कारणात्मक तर्क किसी भी तरह समझ में आने वाले नहीं हैं और वे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए औचित्यपूर्ण नहीं हैं। उदाहरण के लिए यह दिखाई देगा कि घरेलू उद्योग को मालसूची (जो बहुत कम घटी है) को छोड़कर सभी कारकों में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि, प्रकटन दस्तावेज में यह उल्लेख है कि "घरेलू उद्योग को लाभ, कर-पूर्व लाभ तथा नकद लाभ की दृष्टि से वित्तीय हानियां हुई हैं" और "लगाई गई पूंजी पर आय क्षति अवधि में कम हुई है तथा वह पूरी क्षति अवधि में नकारात्मक स्तरों पर रही है" (कृपया सामान्य प्रकटन दस्तावेज का पैरा-48 देखें), ये जांच परिणाम प्रकटन दस्तावेज में प्रकट किए गए किसी भी आंकड़े द्वारा किसी भी तरह समर्थन प्राप्त नहीं करते।
- कारणात्मक के संबंध में प्रकटन दस्तावेजों से यह दिखाई देता है कि संबंधित देशों से आयात लगभग 21,000 मी.ट. से गिरकर लगभग 16,000 मी.ट. हो गया है। आयात का बाजार हिस्सा 79 प्रतिशत से घटकर 49 प्रतिशत हो गया है जबकि इसके साथ ही भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा नाटकीय रूप से 6 प्रतिशत से बढ़कर 49 प्रतिशत हो गया है।
- भारतीय प्राधिकारियों को चाहिए कि वे इस संबंध में अपने जांच परिणामों में संशोधन करने पर सशक्त रूप से विचार करें।

(iii) एग्जो नोबेल ईयू का प्रतिनिधित्व करने वाले मै. ए पी जे एसएलजी विधि कार्यालयों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- मै. एग्जोनोबल का कहना है कि वे उत्तरदायी उत्पादक/निर्यातक को अलग-अलग पाटन मार्जिन प्रदान न किए जाने के संबंध में अत्यधिक चिंतित हैं जोकि हाल के कुछ मामलों में प्राधिकारी द्वारा ली गई स्थिति के पूर्णतः विरोधाभासी हैं। दुर्भाग्यवश हमारे द्वारा किए गए विस्तृत अनुरोधों, तर्कों और पूर्व के उदाहरणों पर प्रकटन विवरण मौन है और वे वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर लागू क्यों नहीं हैं। हमने विस्तृत अनुरोध पूर्व के नोट दिनांक 12.6.2017 में दायर किए थे।
- प्राधिकारी ने केवल यह कहकर कि "मै. एग्जोनोबल द्वारा उल्लिखित कोई भी मामला वर्तमान मामले के समान नहीं है" हमारे द्वारा उल्लिखित कानूनी स्थिति तथा किए गए अनुरोधों को दरकिनार कर दिया है। प्राधिकारी मानेंगे कि यह "तथ्यों" की समानता नहीं है जोकि मामले में जांच किए जाने के लिए अपेक्षित हो बल्कि दृष्टिकोण का "अनुपात" और अन्य मामलों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ली गई स्थिति है। किसी भी स्थिति में प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वे कानूनी प्रावधानों तथा मामले से संबंधित कानूनों के अनुसार कार्य करें तथा उन कारणों को रिकॉर्ड करें कि वे विभेदकारी क्यों हैं। वर्तमान मामले के तथ्य हमारे द्वारा उल्लिखित मामलों से भिन्न हो सकते हैं परंतु हम अपनी बात को दोहराते हैं कि यह वहीं "अनुपात" है जो महत्व रखता है। हमारे द्वारा उल्लिखित मामलों पर एक सरसरी नजर डालने पर किसी संदेह से परे यह सिद्ध होगा कि अनुपात और परिपाटियां वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से लागू हैं।
- प्राधिकारी यूरोपीय संघ के उत्तरदायी उत्पादक/निर्यातक, मै0 एग्जोनोबल के लिए अच्छे व्यवहार तथा परिपाटी की सततता के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन/क्षति मार्जिन निर्धारित करें।
- इस संबंध में हमारे बार-बार अनुरोध करने के बावजूद प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के माध्यम से पहली बार हमें वर्तमान स्थिति से अवगत कराया है। अतः हम माननीय प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे हमें स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से संगत लागू मामले के कानूनों के साथ हमारे अनुरोधों को स्पष्ट करने के लिए सुनवाई का अवसर प्रदान करें।

(iv) (क) मै. जेनिथ इलेक्ट्रोकेम प्रा.लि., (ख) मै. बिन्दाल्स पेपर मिल्स लि. और (ग) मै. के आर पल्प एंड पेपर लिमिटेड की ओर से मै. पोथल एंड एसोसिएट चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने निम्नलिखित अनुरोध किया है।

- वर्तमान जांच के क्षेत्र में यू एस ए से विचाराधीन उत्पाद के न्यूनतम स्तर के आयात से ऊपर को स्पष्ट रूप से शामिल न किए जाने का गंभीर मुद्दा है। यह मुद्दा शुल्कों को गैर-विभेदकारी रूप से लगाए जाने के डब्ल्यू टी ओ सिद्धांत का सख्त उल्लंघन नहीं है बल्कि कारणात्मक संबंध को भंग करने का पहलू भी है। क्योंकि यू एस ए से कीमत संबंध देशों की कीमत से कम है। प्रकटन विवरण में इस मुद्दे को आयातकों आदि द्वारा किए गए अनुरोधों के रूप में कुछ स्थानों पर लिया गया है। तथापि, इन मुद्दों की जांच नहीं की जा रही है जोकि अनुचित है तथा इस प्राधिकारी द्वारा स्वयं विगत में भी की गई परिपाटी के अनुरूप नहीं है। ऐसे मुद्दों की जांच विगत में भी काफी सुसंगति से की गई थी जोकि प्राधिकारी द्वारा विभिन्न जांच परिणामों में देखी जा सकती है और इस मुद्दे को छोड़ने का अब कोई वास्तविक कारण अथवा कोई कानूनी कारण नहीं है। पुनरावृत्ति के निमित्त हम एक बार फिर निम्नलिखित रूप में इस मुद्दे पर अपने संगत अनुरोध प्रस्तुत करते हैं कि प्राधिकारी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कृपया ध्यान दें। यह बात दोहराई जाती है कि वर्तमान जांच को बिना किसी उपाय के समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यूएसए से न्यूनतम कम कीमत से अधिक पर आयात को हटाया जाए क्योंकि संबंध देशों ने वर्तमान जांच में कारणात्मक संबंध को भंग किया है और प्राधिकारी भेदभावपूर्ण स्थिति में शुल्क नहीं लगा सकते।
- वर्तमान जांच में संबंध देश के रूप में यूएसए को शामिल न करने से वर्तमान जांच में स्वतः धीमापन आया है। इससे कारणात्मक क्षति की जांच अनुचित होगी और हेराफेरी दिखाई देगी तथा एक देश विशेष के विरुद्ध भेदभाव की स्थिति भी होगी। जोकि पाटनरोधी करार के सिद्धांत के तहत प्रतिबंधित है। हमने अपने आरंभिक अनुरोधों में ही इस मुद्दे का उल्लेख किया है परंतु इस क्षेत्र में यूएसए को शामिल न करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा कोई औचित्य नहीं दर्शाया गया है जो इसे संदेहपूर्ण बनाता है कि घरेलू उद्योग ने यूएसए को हमें कोई जानकारी न देते हुए अलग किया है।
- घरेलू उद्योग द्वारा यह बात बनायी गई थी कि जांच की अवधि अपने विवेक से एल डी प्राधिकारी द्वारा एक तिमाही तक बढ़ाई गई थी और मूल जांच की अवधि के अनुसार अमेरिका का हिस्सा 2.14 प्रतिशत था। यह तर्क उस अडचन को समाप्त करने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं है जो हुई है। घरेलू उद्योग ने केवल चूक का भार एल डी प्राधिकारी पर डालने का प्रयास किया है जबकि मामले का तथ्य यह है कि जांच की अवधि को अपने विवेक से बढ़ाने का कार्य जांच की अवधि में शामिल किए जाने के लिए मांगी गई अवधि से संबंधित आधारभूत सूचना की जांच किए बिना किया गया है। हमारा विनम्र अनुरोध यह है कि घरेलू उद्योग ने इस प्रकार के विस्तार का लाभ लेने के लिए एल डी प्राधिकारी की जानकारी में यह तथ्य नहीं आने दिया और वस्तुतः हमारे आरंभिक अनुरोध में इस मुद्दे का उल्लेख किए जाने के बाद भी विगत 7 माह से अधिक तक इस मुद्दे पर घरेलू उद्योग मौन रहा।
- सोडियम क्लोरेड के आयात से संबंधित वर्तमान पाटनरोधी जांच कनाडा, चीन जन.गण. और यूरोपीय संघ के विरुद्ध शुरू की गई है और ये देश जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में संबंध देशों के रूप में संयुक्त रूप से उल्लिखित किए गए हैं। इस संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 14 और नियम 19 संगत हैं जिनमें नियम-14 में अन्य बातों के साथ-साथ किसी देश के विरुद्ध पाटनरोधी जांच चालू रखने के लिए स्तर के रूप में उस देश में कुल आयात की मात्रा में देश विशेष से 3 प्रतिशत की शुरुआत निर्धारित है और नियम-19 में भेदभावपूर्ण तरीके से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने अर्थात् किसी देश विशेष के विरुद्ध ही पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने तथा किसी शुल्क लगाए जाने के क्षेत्र से एक या अधिक देशों को छोड़ने का प्रतिबंध है। नियम-19 में सीधे ही डब्ल्यू टी ओ ए डी करार क अनुच्छेद 9.2 से संबंधित विश्वसनीयता है। डब्ल्यू टी ओ सदस्यों द्वारा गैर भेदभावपूर्ण कार्रवाई की संकल्पना को बड़ी कठोरता से अपनाया जाता है तथा डी जी ए डी भी कभी भी इसका अपवाद नहीं रहा है। पाटनरोधी करार के नियम-14, 19 और अनुच्छेद 9.2 इस संबंध में व्यवहारिक हैं।
- आवेदक संबंध देशों का चयन करने में अत्यधिक चुनिंदा रहा है और इस तथ्य के बावजूद यूएसए से संबंध सामानों के आयात की जानबूझकर उपेक्षा करता रहा है कि यूएसए से आयात जांच की अवधि के दौरान शुरुआती तौर पर न्यूनतम से काफी अधिक थे और जांच में शामिल किए गए संबंध देशों से कीमतों की तुलना में काफी कम कीमत पर भी थे। यह बात यह दर्शाती है कि जांच की शुरुआत संबंध देशों की तुलना में स्वभाव में भेदभावपूर्ण है और संबंध देशों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के मामले में भी भेदभावपूर्ण है तथा वर्तमान मामले में यूएसए के विरुद्ध कोई शुल्क न लगाए जाने से भेदभावपूर्ण उपाय होंगे, इस प्रकार, वर्तमान जांच कानून के तहत उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार की जांच की

शुरूआत केवल भेदभावपूर्ण कार्रवाई का संकेत नहीं देती बल्कि कारणात्मक संबंधों को स्पष्ट रूप से भंग करने का संकेत भी देती है।

- आवेदन पत्र के पृष्ठ-47 पर अद्यतन याचिका के साथ अनुबंध-1.2 द्वारा दिए गए विभिन्न देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात को दर्शाने वाला आवेदक द्वारा दिया गया संशोधित सारांश आयात आंकड़े यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि यूएसए से संबद्ध सामानों के आयात कानून के तहत निर्धारित शुरूआती न्यूनतम से काफी अधिक रहे हैं। इसके अतिरिक्त, यू एस ए से आयात इतने न्यूनतम कीमत स्तर पर रहे हैं जिन्हें आवेदक द्वारा घरेलू उद्योग को क्षतिकारक माना गया है। इस प्रकार, हम यह नहीं समझ पाए कि यूएसए को इस जांच में संबद्ध देश के भाग के रूप में क्यों नहीं माना गया है।
- यूएसए को एक संबद्ध देश के रूप में शामिल न किए जाने से एक ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें पाटनरोधी नियमावली के नियम-19 का उल्लंघन होता है। नियम-19 के अनुसार प्राधिकारी भेदभावपूर्ण आधार पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगा सकते जैसा कि ऊपर अनुरोध किया गया है।
- यूएसए को “संबद्ध देशों” के क्षेत्र से जानबूझकर अलग किया गया है क्योंकि प्रतिभागी घरेलू उद्योग संबद्ध सामानों का आयात कर सकता है अथवा यूएसए से संबद्ध सामानों के निर्यातक/उत्पादक से संबंधित हो सकता है और इस प्रकार, यूएसए के विरुद्ध किसी भी तरह से आवेदन पत्र दायर करने के लिए उसकी कोई “अधिस्थिति” नहीं हो सकती। शरारत स्पष्ट है क्योंकि आवेदक ने केवल घोषणाएं दायर की हैं कि प्रतिभागी घरेलू उत्पादकों ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है जैसा कि उन्होंने घोषित किया है कि उन्होंने किसी भी तरह संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया जोकि अपने आप में एक बहुत बड़ी असत्यता है।
- साथ ही, यह दिग्भ्रमित करने वाली बात है कि घरेलू उद्योग ने नई जांच की अवधि मानते हुए अद्यतन आवेदन के खंड-5 में अनुरोध किया है कि अन्य देशों से आयात या तो नगण्य हैं अथवा आयात कीमतें अधिक हैं जबकि मामले का तथ्य यह रहा कि यूएसए से आयात लगभग 3.14 प्रतिशत थे और कीमत 33 रूपए/किग्रा. थी जोकि संबद्ध देशों से कीमत की अपेक्षा काफी कम थी जो 37 रूपए से 42 रूपए प्रति किग्रा. के बीच थी। रोचक बात यह भी है कि घरेलू उद्योग ने अद्यतन याचिका में भी इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण नहीं दिया और उसके बजाए एक भ्रामक विवरण दिया। यदि उसको हटाया जाना जांच की अवधि का विस्तार के कारण था तो घरेलू उद्योग ने अद्यतन याचिका में उसे स्पष्ट दिया होता।
- यह अनुरोध है कि यूएसए को शामिल न करना एक बड़ा कानूनी मुद्दा है जोकि वर्तमान जांच में बड़ी गहराइयों तक जाता है। इस प्रकार, यूएसए को जांच के क्षेत्र के भीतर शामिल न करना एक भारी त्रुटि है जो समस्त जांच को आदितः निरर्थक बना देती है। अतः माननीय प्राधिकारी इस भारी त्रुटि का संज्ञान लेते हुए इस एकमात्र आधार पर इन कार्यवाहियों को समाप्त करें। कुल मिलाकर पाटनरोधी करार और पाटनरोधी नियमावली प्राधिकारी को पाटनरोधी जांच में भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई करने की अनुमति नहीं देते क्योंकि यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है।
- यह अनुरोध किया गया है कि भारत में 2 से अधिक उत्पादक हैं और इनमें से एक दूसरा ज्ञात उत्पादक राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी है। विषयगत प्रकटन विवरण में पैरा-11 में दिए गए अनुसार इस मुद्दे का प्रभावी रूप से समाधान किया गया। तथापि, यह बात दोहराई जाती है कि श्री क्लोरेट (मै. जेनिथ इलैक्ट्रोकेम प्रा.लि.) के पास अब भी संबद्ध सामानों के उत्पादों के लिए लाइसेंस है और एक दूसरा उत्पादक दि ट्रेवनकोर कोचीन कैमिकल्स लिमिटेड (राज्य पीएसयू) है जो संबद्ध सामानों का उत्पादन कर रहा है जिसका नाम याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राधिकारी को किसी भी तरह प्रकट नहीं किया गया है।
- सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में यह अनुरोध है कि यथानिर्धारित पाटन मार्जिन अत्यधिक प्रतीत होता है और हमारा यह मानना है कि याचिकाकर्ता ने बहुत ही अधिक पाटन मार्जिन दर्शाने के लिए रिकॉर्ड में भ्रामक सूचना रखी है तथा हम कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि पाटन मार्जिन के निर्धारण से संबंधित प्रत्येक सूचना गोपनीय रखी जाती है। निर्धारित किए गए पाटन मार्जिन पर हमारे पूर्व के अनुरोधों के मद्देनजर पुनः विचार किया जाए। हमाने अनुरोधों को संक्षिप्तता की दृष्टि से पुनः नहीं दर्शाया जा रहा है।
- घरेलू उद्योग को कोई भी क्षति प्रकटन विवरण में देखी जा सकती है और इस एकमात्र कारण से इस मामले को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। प्रकटन विवरण का सामान्य अध्ययन करने से हमारे दावे पुनः पुष्ट होते हैं कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है जैसा कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण आरोप लगाया गया है क्योंकि सोडियम क्लोरेड से आयात कम हुए हैं।
- इस मामले में कीमत कटौती स्पष्ट रूप से नकारात्मक है जो यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पहुंच कीमत का कोई प्रतिकूल कीमत प्रभाव नहीं था। यह कहना सही नहीं है कि याचिकाकर्ता ने आयात की कीमत से समानता रखने का

प्रयास किया। यदि वह मामला होता तो कटौती सकारात्मक होती। नकारात्मक कटौती का अभिप्राय है कि आयात की पहुंच कीमत घरेलू कीमत से अधिक थी तो याचिकाकर्ता का आयात कीमतों से समानता करने के प्रयास का प्रश्न कहां है। इसका उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है कि क्या घरेलू उद्योग को आयात की कीमतों के स्तर से अपनी कीमतें बढ़ाने से किसने रोका है। साथ ही, संबद्ध देशों से आयात जांच की अवधि तक काफी घटे हैं जो यह दर्शाता है कि निर्यातक कम कीमतें पेश कर अधिक बाजार हिस्सा लेने के लिए प्रयास नहीं कर रहे थे।

- आयात में कमी के अनुरूप संबद्ध देशों से नकारात्मक कटौती हमारे तर्क को आसान बनाती है कि घरेलू उद्योग को कोई तथाकथित क्षति का कारण यूएसए से कम कीमत पर आयात होगा और जब यूएसए से आयात कीमत के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है, जैसा कि इस तथ्य से सिद्ध है कि यूएसए के विरुद्ध कोई मामला शुरू नहीं किया गया है, संबद्ध देशों से तुलनात्मक रूप से अधिक कीमत पर आयात के कारण कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार, दावों की विभिन्नता की और जांच किए जाने की आवश्यकता है।
- वर्तमान मामले के तथ्यों में सकारात्मक कीमत कटौती का कोई अर्थ नहीं है और सर्वोत्तम रूप से कोई सकारात्मक कटौती बड़ी हुई उत्पादन लागत का परिणाम हो सकती है। यद्यपि, एनआईपी का निर्धारण अनुबंध-3 के अनुसार किया जाता है। नकारात्मक कटौती यह दर्शाती है कि संबद्ध आयातों का पूर्णतः कोई कीमत प्रभाव नहीं था और वास्तव में इन कीमतों से कोई कम बिक्री प्रभाव भी नहीं हुआ। इस प्रकार, हमारा यह मानना है कि उत्पादन लागत स्पष्ट रूप से बड़ी हुई है जिसकी याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए अनुसार ऐसी किसी भी लागत की अनुमति देने से पूर्व और जांच किए जाने की आवश्यकता है।
- प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण में यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों पूरी क्षति अवधि के दौरान कम हुई हैं। तथापि, बिक्री कीमत में कमी बिक्री लागत में कमी से कहीं अधिक है। प्राधिकारी ने यह भी पाया है कि बिक्री कीमत पूरी क्षति अवधि में उत्पादन लागत के स्तर से कम रही है। इस प्रकार, घरेलू बाजार में घरेलू कीमतों पर आयात ह्रासमान एवं न्यूनीकरण प्रभाव दर्शाते हैं। इन टिप्पणियों के संबंध में यह अनुरोध है कि पैरा 43 की तालिका बिक्री कीमत में कम कमी दर्शाती है तथा लागत में कटौती अधिक रही है। साथ ही, चूंकि कीमत कटौती नकारात्मक है अतः तथाकथित पाटित आयातों के कारण कोई ह्रासमान अथवा न्यूनीकरण प्रभाव नहीं हो सकता। ऐसे मामले में कोई भी क्षति किसी अन्य कारण से हो सकती है और ऐसे अन्य किसी कारण से क्षति आयातों के कारण नहीं हो सकती। इस पहलू की हमारे उपर्युक्त टिप्पणियों पर विचार करते हुए और अधिक जांच किए जाने की आवश्यकता है और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं।
- प्रकटन विवरण के अनुसार, मात्रा संबंधी सभी मापदंड आश्चर्यजनक वृद्धि दर्शाते हैं। आयातों के कारण कोई कीमत क्षति भी नहीं हुई है क्योंकि संबद्ध देशों से कीमत से घरेलू उद्योग की कीमत पर कटौती प्रभाव नहीं हुआ। इस प्रकार, तथाकथित पाटित आयातों से कोई क्षति नहीं हुई है और इस आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं हुई है।
- उत्पादकता की प्रवृत्ति गोपनीय रखी जाती है और वह प्रवृत्ति बताई भी नहीं जाती। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे उसकी जांच करें और उत्पादकता में कमी के कारण कोई क्षति आयातों के कारण नहीं हो सकती। हम कोई भी टिप्पणी देने में असमर्थ हैं क्योंकि मानदंड की प्रवृत्ति भी “वास्तविक प्रकटन” में उपलब्ध नहीं है।
- माल सूची स्तर में दावा की गई वृद्धि को देखने के लिए कोई आर्थिक औचित्य नहीं है जैसा कि वर्तमान मामले में क्षति के संकेतक के रूप में प्रकटन में दिया गया है क्योंकि घरेलू उद्योग के निष्पादन के प्रमुख मात्रात्मक मापदंड जांच की अवधि तक अत्यधिक विचलन दर्शाते हैं और इसके साथ ही संबद्ध देशों से आयात अत्यधिक कम हुए हैं। मालसूची में वृद्धि आयातों के कारण नहीं हो सकती।
- प्रकटन विवरण में इस मानदंड के महत्व पर कोई जोर दिए बिना वृद्धि के मुद्दे का समाधान किया गया है। यह टिप्पणी कि घरेलू उद्योग की वृद्धि कुछ मानदंडों में कम हुई है, पूर्णतः अपर्याप्त है, जब मामले का तथ्य यह है कि वृद्धि विषयगत प्रकटन के लगभग प्रत्येक मानदंड में काफी सकारात्मक रही है। इस दावे में सत्य का अंश भी नहीं हो सकता कि घरेलू उद्योग को वास्तविक हुई है जबकि प्रमुख क्षति मापदंड सकारात्मक वृद्धि दर्शाते हैं। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे इस पहलू कि विस्तार से जांच करें ताकि क्षति संबंधी सही निष्कर्षों पर पहुंचा जा सके।

- इस टिप्पणी के विपरीत कि वर्तमान मामले में कारणात्मक संबंध है, यह अनुरोध है कि यूएसए अर्थात् संबद्ध देशों से न्यूनतम स्तर से अधिक के आयातों पर कम कीमत वाले को हटाना तथा नकारात्मक कीमत कटौती वर्तमान मामले में कारणात्मक संबंध को भंग करना दर्शाते हैं। हमारे पास डी जी सी आई एंड एस के अनुसार यूएसए से आयात की मात्रा तथा कीमत के ब्यौरे नहीं हैं क्योंकि उन्हें गोपनीय रखा जाता है अथवा यहां नहीं दिए जाते हैं। यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि यूएसए से आयात न्यूनतम स्तर से अधिक के थे और कीमतें संबद्ध देशों से कम थीं तथा याचिका में यह सिद्ध था। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे यूएसए के आयातों को भी ध्यान में रखते हुए कारणात्मक संबंध के पहलुओं की पुनः जांच करें।

(v) यूरोपीय आयोग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुच्छेद 3.2 में यह प्रावधान है कि जांचकर्ता प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण रूप से अथवा उत्पादन और खपत के सापेक्ष काफी वृद्धि हुई है जैसाकि आयोग द्वारा अपने पूर्व के अनुरोध में पहले उल्लेख किया गया है, संबद्ध देशों से भारत में सोडियम क्लोराइड की आयात मात्रा में घरेलू उद्योग द्वारा संबंधित उत्पाद का उत्पादन प्रारंभ किए जाने के बाद काफी कमी आई है। भारतीय उत्पादन और खपत दोनों के संबंध में विश्लेषण की अवधि में (2012-13 से जांच की अवधि तक) संबद्ध देशों से आयात काफी कम हुआ है (-92% और -38%)। संबद्ध देशों से सभी आयात द्वितीय भारतीय कंपनी के घरेलू बाजार में प्रवेश होने और बाजार हिस्सा प्राप्त करने के बाद 2014-15 (जांच की अवधि में 20,118 मी.ट. से 15,849 मी.ट.) से घटना प्रारंभ हो गया है।
- यह भी दावा किया गया है कि घरेलू उत्पादन के आरंभ होने के बावजूद आयात पूरी क्षति अवधि में काफी रहे और लगभग सभी आयात संबद्ध देशों से आते हैं। परंतु यह उस स्थिति में पूर्णतः सामान्य है जब घरेलू मांग लंबे समय तक आयात पर पूर्णतः निर्भर हो और घरेलू उद्योग ने हाल ही में संबंधित उत्पाद का उत्पादन शुरू किया है।
- जहां तक कीमतों का संबंध है, कटौती सिद्ध करने के लिए तुलना को गोपनीय रखा गया है : घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमतों से संबंधित न तो कोई आंकड़े और न ही सूची उपलब्ध कराई गई है जिससे पक्षकारों के लिए तथाकथित रूप से क्षतिकारक स्थिति को स्पष्ट रूप से समझना असंभव हो जाता है। घरेलू उद्योग की आयात कीमतों के बारे में सामान्य रूप से दावा किया गया है, परंतु फिर भी इससे नए-नए स्थापित घरेलू उद्योग को एक छोटी सी अवधि में काफी बाजार हिस्सा लेने (जांच की अवधि में घरेलू खपत का 49 प्रतिशत) के लिए कोई रोक नहीं लगी है।
- यही बात कम बिक्री पर लागू होती है, जिसमें घरेलू उद्योग क्षतिरहित कीमत के संबंध में कोई सूची अथवा कोई प्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई हो (अनुबंध-4 (क) से परिकलन समझने में सहायता नहीं मिलती।
- आंकड़ों और परिकलनों को प्रकट न किए जाने के सार्थक सारांश के उपर्युक्त अभाव में पक्षकारों के अपने हितों की रक्षा करने के अधिकार समाप्त होते हैं तथा यह डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुच्छेद 6.5.1 के प्रावधानों के विपरीत है, जिसमें यह प्रावधान है कि प्राधिकारियों से हितबद्ध पक्षकारों को गोपनीय सूचना प्रदान करते हुए उसका अगोपनीय सारांश देने की अपेक्षा है और यह कि इन सारांशों में गोपनीय रूप में प्रस्तुत सूचना के सार की पर्याप्त समझ लेने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त ब्यौरे होंगे।
- घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री की मात्रा 2014-15 में बढ़ी है जोकि द्वितीय घरेलू कंपनी के अप्रैल, 2014 में उत्पादन शुरू करने के परिणामस्वरूप है तथा वह जांच की अवधि के दौरान बढ़ती रही है। इसी प्रकार क्षमता उपयोग, रोजगार, उत्पादकता प्रतिदिन तथा प्रति कर्मचारी बढ़ी है।
- सर्वाधिक क्षति संकेतकों की बढ़ती हुई सकारात्मक प्रवृत्ति के मद्देनजर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण गंभीर क्षति की स्थिति में रहा है। उद्योग जिस कठिनाई का अनुभव कर रहा है वह अधिकतर संभावित रूप से अन्य कारकों के कारण है जिनमें उल्लेखनीय यह है कि जब आयात विश्लेषण की अवधि के दौरान काफी कम हुए हैं।
- डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुच्छेद 3.5 के अनुसार यह दर्शाया जाना चाहिए कि पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध है। इस कारणात्मक संबंध को दर्शाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक कीमत कटौती है। तथापि, जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया गया है, कटौती संबंधी सूचना निष्कर्षात्मक नहीं है।
- इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता दावा करते हैं कि पाटित आयातों के कारण और घरेलू मांग में काफी वृद्धि के बावजूद वे अपनी क्षमता का विस्तार करने में सक्षम नहीं थे जैसाकि उन्होंने योजना बनाई थी। तथापि, चूंकि घरेलू उद्योग केवल 3 वर्ष के

भीतर ही लगभग 50 प्रतिशत बाजार हिस्से तक पहले ही पहुंच चुका है अतः यह माना जाता है कि घरेलू उद्योग की योजना और क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश अत्यधिक थे। उन्होंने भारतीय बाजार में इतने लंबे समय तक आयातित उत्पादों के नियंत्रण की सशक्त स्थिति को ध्यान में नहीं रखा/उसे कम आंका।

- याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि उन्हें अपनी बिक्री कीमतें कम करनी पड़ी, इस प्रकार उन्हें तथाकथित रूप से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप वित्तीय हानियां हुईं। इस संबंध में आयोग यह प्रश्न उठाता है कि दोनों को कैसे जोड़ा जा सकता है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात विश्लेषण की अवधि में काफी कम हुए हैं। अन्य कारक भी हैं जिन्हें हमारे पूर्व के अनुरोध में पहले ही उल्लिखित कर दिया गया है (दक्षता, क्षमता, आरंभिक लागत), जिसका घरेलू उत्पादकों की स्थिति पर प्रभाव पड़ा है तथा इसे उचित रूप से ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

76. प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि जहां तक चीन और कनाडा से सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों का संबंध है, प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6(8) के अनुसार अर्थात् घरेलू उद्योग के लिए अनुमत स्तरों पर प्रमुख कच्ची सामग्री तथा उपयोगी वस्तुओं, प्रवर्तन लागत, व्याज, एसजीए आदि के लिए घरेलू उद्योग के अधिकतम खपत मानकों पर विचार करते हुए इन सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्मित सामान्य मूल्य (सीएनवी) का मूल्यांकन किया है। व्याज को छोड़कर बिक्री की 5 प्रतिशत लागत डीजीएडी की विद्यमान परिपाटी के अनुसार उपयुक्त लाभ के रूप में अनुमत की गई है और उसे यहां अपनाया गया है। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि किसी संबद्ध देश विशेष के सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए मूल्यांकित पाटन मार्जिन की तुलना दूसरे देशों के उत्पादकों/निर्यातकों से नहीं की जा सकती, चाहे वह सहयोगी हो या असहयोगी हो क्योंकि किसी संबद्ध देश के असहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए सीएनवी का निर्धारण उस देश के लिए उपयुक्त सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, पाटन मार्जिन केवल सीएनवी का कार्य नहीं है अपितु निर्यात कीमत भी है, जो हर देश में अलग-अलग होती है। अतः प्राधिकारी चीन और कनाडा के लिए पहले ही मूल्यांकित पाटन मार्जिन को दोहराते हैं।

77. जहां तक अरकेमा फ्रांस के लिए पाटन मार्जिन के मूल्यांकन का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक ने पाटन के मूल्यांकन को इंकार नहीं किया है अपितु पाटन मार्जिन की प्रतिशतता के संबंध में अनुरोध किए हैं जो उनके अनुसार सीआईएफ की प्रतिशतता के रूप में मूल्यांकित किया जाना चाहिए नकि कारखानागत निर्यात कीमत (ईएक्सईपी) पर। प्राधिकारी ने कारखानागत निर्यात कीमत की प्रतिशतता के रूप में पाटन मार्जिन का मूल्यांकन पाटनरोधी नियमावली के अनुसार किया है। यद्यपि, पाटन मार्जिन कारखानागत निर्यात कीमत की प्रतिशतता अथवा सीआईएफ की प्रतिशतता के रूप में अलग-अलग हो, पूर्ण पाटन मार्जिन मूल्य अपरिवर्तित रहेगा। प्राधिकारी ने उत्पादन लागत तथा उत्पादन लागत में जोड़े जाने वाले लाभ मार्जिन सहित परीक्षण की साधारण अवधि के ब्यौरे अरकेमा फ्रांस को प्रकट किए हैं। उत्पादक/निर्यातक द्वारा दावा किए गए कारखानागत निर्यात कीमत मूल्य को उत्पादक/निर्यातक को प्रकट किए गए कारखानागत निर्यात कीमत गणना के संबंध में सभी संबंधित ब्यौरे स्वीकार कर दिए गए हैं। अतः प्राधिकारी उत्पादक/निर्यातक को पहले ही सूचित किए गए पाटन मार्जिन के मूल्यांकन की पुष्टि करते हैं।

78. जहां तक यूएसए को भी एक संबद्ध देश के रूप में शामिल किए जाने का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि यह केवल आयात कीमत ही नहीं है अपितु पाटन का तथ्य भी है जिसे याचिकाकर्ता द्वारा मामले की जांच की शुरुआत का अनुरोध करते समय प्रथम दृष्टया सिद्ध किए जाने की आवश्यकता होती है। प्राधिकारी को केवल 3 देशों के विरुद्ध याचिका प्राप्त हुई और प्रथम दृष्टया तथ्यों के आधार पर अनुरोध किए गए इन तीन देशों के विरुद्ध मामले की शुरुआत की गई जिसमें यूएसए शामिल नहीं था।

79. प्राधिकारी मै0 अकजोनोबल के अधिवक्ताओं द्वारा उनके द्वारा दी गई निर्यात कीमत के ही आधार पर उन्हें अलग-अलग पाटन मार्जिन प्रदान करने के अनुरोधों को नोट करते हैं क्योंकि सामान्य मूल्य के संबंध में उनका कोई दावा नहीं है। इस संबंध में प्राधिकारी ने उनके द्वारा उल्लिखित मामलों को नोट कर लिया है जिनमें इस प्रकार का अनुरोध पर विचार किया जाना है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक द्वारा उल्लिखित कोई भी मामला वर्तमान मामले के समान नहीं है। कोल्ड रोलड स्टील प्रोडक्ट उत्पादों के मामले में उत्पादक/निर्यातक ने वास्तव में उत्पादन लागत संबंधी आंकड़े दायर किए थे जिसे उपयुक्त नहीं माना गया था। ऐसीटोन के मामले में निर्यातक ने घरेलू बिक्री के आंकड़े दिए थे परंतु उत्पादन लागत नहीं बताई। मै0 आर्डकन के मामले में उत्पादक/निर्यातक के उत्तर में कमियां नोट की गईं। अतः इन सभी मामलों में उत्पादक/निर्यातक ने आंकड़े दायर करने के अपने इरादे और प्रयास को दिखाया जोकि सामान्य उम्मीद से कम था। मै0 अकजोनोबल के मामले में सामान्य मूल्य के प्रयोजनों से आंकड़े दायर करने के संबंध में उन्होंने पूर्ण रूप से मना किया। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि मै0 अकजोनोबल को अवशिष्ट श्रेणी में सही-सही माना गया है।

80. जहां तक घरेलू उद्योग के एनआईपी का प्रकटन करने के दावे का संबंध है, उन्हें एक विस्तृत कार्य तालिका पहले ही दे दी गई थी। जहां तक सीएनवी, वास्तविक पाटन मार्जिन का प्रतिशत, निर्यातक सत्यापन रिपोर्ट/पत्राचार आदि से संबंधित अन्य सूचना का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रकटन प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार कर दिया गया है। उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोगी समूह के लिए सीएनवी की गणना घरेलू उद्योग के आंकड़ों अर्थात् सर्वाधिक दक्ष उत्पादक तथा प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार आय की उपयुक्त मात्रा की अनुमति देकर, के आधार पर की गई है। चूंकि “सीएनवी” की गणना अन्य सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना सहित घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर की जाती है, अतः प्राधिकारी सीएनवी का परिकलन घरेलू उद्योग अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार, जिसमें गैर-उत्तरदायी उत्पादक/निर्यातक भी शामिल हैं, जिनके लिए पाटन मार्जिन की गणना की जाती है, प्रकट नहीं करते क्योंकि इसे गोपनीय माना जाता है। अतः मूल्यांकित पाटन मार्जिन का उल्लेख अंतिम जांच परिणाम में एक श्रृंखला के रूप में किया गया है और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक प्रतिशतता के रूप में नहीं किया गया है।

81. जहां तक घरेलू उद्योग के आधार का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रमुख प्रयोक्ता एसोसिएशनो ने अनुरोध किया है कि देश में विचाराधीन उत्पाद के केवल दो उत्पादक हैं। इसके अतिरिक्त, किसी अन्य उत्पादक के मौजूद होने के संबंधित कोई साक्ष्य किसी भी पक्षकार द्वारा दायर नहीं किया गया है और न ही जांच के दौरान प्राधिकारी को किसी ऐसे उत्पादक ने जानकारी दी है। अतः घरेलू उद्योग का आधार सही स्थापित किया गया है।

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्से से संबंधित सूचियां मजबूत हैं और किसी क्षति को सिद्ध नहीं करती हैं। इसके अतिरिक्त, कीमत कटौती भी नकारात्मक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन सभी सूचियों के बावजूद घरेलू उद्योग की कीमतें एनआईपी से काफी नीचे न्यूनीकृत रही हैं। नए उत्पादकों के मामले में नकारात्मक कीमत कटौती उनकी बाजार में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रयासों के संदर्भ में माने जाने की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग ने पाटित स्रोतों से आयातों के साथ अपनी बिक्री कीमतें निर्धारित की हैं। जब ऐसा होता है तो कम लाभप्रदता के संदर्भ में नकारात्मक कीमत प्रभाव होता है और काफी क्षति मार्जिन होता है। जिसे इस जांच में नोट कर लिया गया है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि कीमत न्यूनीकरण प्रभाव के कारण कीमत के संबंध में दृश्यमान क्षति हुई है।

### **निष्कर्ष**

83. विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा दी गई दलीलों की जांच करने के बाद और यथोक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि :

- i. संबद्ध देशों से संबंधित उत्पाद का पाटन हुआ है।
- ii. संबद्ध देशों से आयात के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण हो रहा है।
- iii. घरेलू उद्योग को कीमत की क्षति कीमत न्यूनीकरण के कारण काफी सकारात्मक क्षति मार्जिन सहित पाटित आयातों के कारण हुई है।

### **सिफारिशें**

84. यथोक्त निष्कर्ष के बाद प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका में यथा वर्णित ढग और तरीके से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

85. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित तालिका के कालम 8 में उल्लिखित राशि के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है।

**शुल्क तालिका**

क्र. सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का वर्णन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	28291100	सोडियम क्लोरेट	चीन	चीन	कोई	कोई	17.77	मी.टन	अम.डा.
2	-वही-	-वही-	चीन	कोई	कोई	कोई	17.77	मी.टन	अम.डा.
3	-वही-	-वही-	कोई	चीन	कोई	कोई	17.77	मी.टन	अम.डा.
4	-वही-	-वही-	कनाडा	कनाडा	कोई	कोई	120.14	मी.टन	अम.डा.
5	-वही-	-वही-	कनाडा	कोई	कोई	कोई	120.14	मी.टन	अम.डा.
6	-वही-	-वही-	कोई	कनाडा	कोई	कोई	120.14	मी.टन	अम.डा.
7	-वही-	-वही-	ईयू	ईयू	अर्केमा फ्रांस	अर्केमा फ्रांस	60.51	मी.टन	अम.डा.
8	-वही-	-वही-	ईयू	ईयू	ऊपर क्र. सं. 7 में उल्लिखित से इतर कोई अन्य	ऊपर क्र. सं. 7 में उल्लिखित से इतर कोई अन्य	95.35	मी.टन	अम.डा.
9	-वही-	-वही-	ईयू	कोई	कोई	कोई	95.35	मी.टन	अम.डा.
10	-वही-	-वही-	कोई	ईयू	कोई	कोई	95.35	मी.टन	अम.डा.

86. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी शुल्क शामिल होंगे।

**आगे की प्रक्रिया**

87. केन्द्र सरकार द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना पर आधारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

डा. इन्द्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th August, 2017

**FINAL FINDINGS**

**Subject: Anti-dumping duty investigation on the imports of Sodium Chlorate originating in or exported from Canada, China PR and EU.**

**No.14/13/2015–DGAD.**— Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

**A. BACKGROUND OF THE CASE**

1. Whereas M/s Gujarat Alkalies and Chemicals Limited and Teamec Chlorates Limited (hereinafter referred to as 'petitioners') had filed an application (also referred to as petition) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Sodium Chlorate" (hereinafter referred to as subject goods or product under consideration) originating in or exported from Canada, People's Republic of China and EU (hereinafter referred to as subject countries).

**B. PROCEDURE**

2. The procedure as described herein below has been followed:

- a. The Authority under the above Rules, received a written application from the petitioner on behalf of domestic industry of subject goods, alleging dumping of subject goods originating in or exported from subject countries and resultant injury to the domestic industry and requesting recommendations for imposition of antidumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.
- b. On the basis of sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and a causal link between the alleged dumping and injury, the Authority initiated an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of subject goods from the subject countries and to recommend an amount of antidumping duty, which if levied on the imports of Sodium Chlorate, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry..
- c. The Authority notified the Embassies/Representatives of the subject countries in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
- d. The Authority issued a public notice dated 12th May, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation against imports of the subject goods from the subject countries.
- e. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers and users association of the subject goods in India and advised them to make their views in writing within forty days from the date of the letter.
- f. The Authority provided a copy of the non-confidential version of application filed by the petitioner to the known exporters and the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the application was also provided to interested party whenever requested.

- g. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters of subject goods in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules.
  - a. M/s. Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals
  - b. M/s. Arkema France
- h. In response to the initiation notification, the following exporters/producers have filed questionnaire response along with legal submissions as well.
  - a. M/s. Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals
  - b. M/s. Arkema France
- i. Questionnaire was sent to the following known importers/users associations of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
  - a. M/s Zenith Electrochem Pvt. Ltd.
  - b. M/s Bindals Paper Mills Ltd.
  - c. M/s K R Pulp and Papers Ltd.
- j. The following Importers/user associations have filed Importer Questionnaire in response to the Initiation notification:
  - a. M/s Zenith Electrochem Pvt. Ltd.
  - b. M/s Bindals Paper Mills Ltd.
  - c. M/s K R Pulp and Papers Ltd.
  - d. M/s Indian Paper Manufacturers Association
  - e. M/s Bilt though filed a letter but did not file a questionnaire reply
- k. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by all interested parties. The public file was inspected by a number of interested parties a number of times. Interested parties, who requested inspection and copies of the documents from the public file, were provided with the same.
- l. The Authority accepted the confidentiality claims, wherever warranted after due examination and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis, which was made available through public file.
- m. Further information was sought from the petitioner and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.
- n. Investigation was carried on for the period October, 2014- December, 2015 (15 months) (hereinafter referred to as the 'period of investigation' or 'POI') with injury analysis covering the period 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 and the POI.
- o. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, and the said information was obtained from the DGCI&S and has been adopted for the purpose of the present investigation.
- p. The Authority has examined the information furnished by the domestic industry to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the AD Rules to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- q. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 10<sup>th</sup> April 2017 which was attended by various parties. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of these views for mutual exchange with opposing interested parties for filing rejoinders thereafter by others.
- r. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this document.

- s. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- t. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- u. The Authority issued a disclosure statement under Rule 16 on 27<sup>th</sup> July, 2017 and provided an opportunity to give comments to the disclosure statement till 7<sup>th</sup> August, 2017.
- v. In this Final Findings, \*\*\* represents information furnished by the interested parties on confidential basis, and so considered by the Authority under the AD Rules.
- w. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.64.17 = 1 US\$.

## **C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

### **C.1 Views of the Domestic industry**

3. The views of the domestic industry are as follows:

- a. The product under consideration in the present investigation, Sodium Chlorate, is an inorganic compound classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act. Sodium Chlorate, with its chemical formula  $\text{NaClO}_3$  is a white crystalline powder that is readily soluble in water. It is hygroscopic. It decomposes above 300 °C to release oxygen and leave sodium chloride.
- b. The main commercial use for Sodium Chlorate is for making chlorine dioxide ( $\text{ClO}_2$ ). The largest application of  $\text{ClO}_2$ , which accounts for about 95% of the use of chlorate, is in bleaching of pulp. All perchlorate compounds are produced industrially by the oxidation of solutions of sodium chlorate by electrolysis.
- c. The subject goods fall under Chapter 28 of the Act under subheading No. 2829 11 00. However, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
- d. There is no difference in Sodium Chlorate produced by the Indian industry and the product exported from the subject countries. Sodium Chlorate produced by the Indian industry and imported from the subject countries are comparable in essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable. Sodium Chlorate produced by the domestic industry should be treated as like article to the Sodium Chlorate imported from the subject countries in accordance with the Anti-dumping Rules.

### **C.2. Views of the other interested parties**

4. None of the importers, consumers, exporters and any other interested party has made any submissions with regard to product under consideration, and like article.

### **C.3. Examination by the Authority**

- 5. The product under consideration is "Sodium Chlorate", an inorganic compound with the chemical formula  $\text{NaClO}_3$ . Sodium Chlorate is a white crystalline hygroscopic powder readily soluble in water. It decomposes above 300 °C to oxygen and sodium chloride. The normal commercial unit of measurement for the product under consideration is kilograms. It is quoted on the basis of weights, and sold in kilograms or MT universally.
- 6. Subject goods are classified under Chapter 28 of Customs Tariff Act, 1975 under the subheading No. 2829 11 00. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the proposed investigations.

7. After considering the information on record, the Authority notes that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods and are like articles. The consumers are using the two interchangeably. Thus, for the purpose of present investigation the subject goods produced by the applicant in India are being treated as like article to the subject goods being imported from subject countries.

#### **D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**

##### **D.1. Views of the Domestic industry**

8. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to scope and standing of the domestic industry:

- a. The petition was filed by M/s. Gujarat Alkalies and Chemicals Limited and Teamec Chlorates Limited. There are no other producers of Sodium Chlorate in the country. While Teamec Chlorates commenced commercial production in April 2012, GACL commenced commercial production in April 2014.
- b. Production of petitioners constitutes a major proportion in Indian Production and therefore, the petitioners should be treated as “domestic industry” within the meaning of the Rules.
- c. The petitioners have not imported the subject goods during the period of investigation, and further, are not related to any exporter or producer of the subject goods in China or any importer or user of the product under consideration in India within the meaning of Rule 2(b).
- d. M/s. Teamec started production in April 2012 and GACL commenced production in April 2014. Thus to this extent the domestic industry is a new entrant in the domestic market.
- e. Chemfab Chlorates Ltd’ is petitioner’s own company and was closed in 2009. TCM Ltd has also winded up their operation long back. Further, both Both Chemofine and Triveni are consumers of Sodium Chlorate and not manufacturers. Travancore Cochin Chemicals Limited are doing contract manufacturing for ISRO and does not have any commercial activity in the domestic market No documentary evidence has been provided by the interested parties.

##### **D.2. Views of the other interested parties**

9. The following submission was made by the producers/exporters/importers/other interested parties in this regard.

- a. Applicants are not the sole producers as the name of Travancore Cochin Chemicals Limited, Chemfab Chlorates, Chemofine Industries, Triveni Interchem Pvt. Ltd. has not been disclosed. Shree chlorates (Zenith Electrochem) still hold valid license to produce subject goods.
- b. Acceptance by the authority of the applicant’s claim of accounting for 100% production is wrong as other producers are also present in the market. Chemfab Chlorates Ltd, TCM Ltd, Shree Chlorates, Chemofine Industries and Triveni Interchem Pvt. Limited are other domestic producers.
- c. The petitioners reached a significant production capacity only in 2015-16 and before that the production was not enough to meet the supply and thus cannot be called as domestic industry.
- d. It has been elaborated in our submissions that there two more producers of subject goods in India and the DI is still claiming that they are the sole producers. The Authority should subject the statement of the DI in this respect to strict scrutiny. It cannot be a new standard in AD investigations that the applicants can make any wrong statement if they fulfill the thresholds required under Rule 2 (b). It is reiterated that Shree Chlorate (M/s. Zenith Electrochem Pvt Ltd) (Capacity of 2500 MT/PA) and The Travancore Cochin Chemicals Limited (state PSU) (Capacity of 5000 MT/PA) are also producers having capacity to produce the subject goods in India.

- e. In relation to the claim of the petitioners that they are the sole producers of the Product Under Consideration, it is submitted that the instant claim is factually wrong and is an attempt to seriously mislead the Authority. It may be recalled that the said contention was also raised by the interested parties during the public hearing dated 10.04.2017. However, no explanation for the same has been provided by the applicant in its written submission.
- f. As provided by us in our written submissions dated 13.04.2017, it is evident that there are several other producers of the subject goods in India, a preliminary list of four other producers was also submitted by us in our written submissions. The Authority may kindly appreciate that it is for the applicant industry to provide correct and reliable information to the Authority in respect of their “standing” and the details of the Domestic Industry. With respect, it would not be procedurally appropriate or legally permissible to shift the onus on the interested parties who have given reasonable information to disprove the claim of the applicants with regard to the producers or the total production in the country.
- g. It is evident that the Petitioners have deliberately withheld this critical information from the Authority in order to prove their standing to file the present application and to claim its status as domestic Industry in terms of Rule 5 and rule 2(b) respectively. In view of the fact that such misdeclaration by the applicants has a direct implication on the initiation of the investigation itself, we humbly request the Authority to kindly terminate the investigation as the applicants have not come with clean hands.
- h. Without prejudice to the above, we also request the Authority that any new information received by the Authority subsequent to the hearing or that which has not been kept in the public file prior to the hearing, may kindly be communicated to us to enable us to defend our interests appropriately. We also request the Authority to kindly provide us a fresh hearing after the basic information about the “standing” of the applicant is obtained and conveyed to us.
- i. M/s. Indian paper manufacturer Association have stated that there are only two domestic producers of Sodium Chlorate, with approximately 20,000 MT of Sodium Chlorate being manufactured in India against which approximately 40,000 MT is consumed by the paper industry. There is a gap of approximately 20,000 MT which is filled by importing Sodium Chlorate from Canada, People’s Republic of China and EU as the domestic producers are not in a position to meet the domestic demand.

### **D.3. Examination of the Authority**

- 10. The application was filed by M/s. Gujarat Alkalies and Chemicals Limited and Teamec Chlorates Limited claiming that they are the sole domestic producers. None of the petitioners have imported the subject goods nor are they related to importers or exporters of subject goods. Interested parties have argued that there are certain other producers who are producing the subject goods, however no basis or evidence has been provided to substantiate the same. It is also noted that none of the said domestic producers have responded in the ongoing investigation.
- 11. The Authority however notes that a major user association of PUC i.e. Indian Paper Manufacturers Association in their submissions have mentioned that there are only 2 domestic producers i.e. M/s. Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. and M/s. Teamec Chlorates Ltd. Therefore the Authority keeping in view this and that no opposition to the initiation by any interested party who has evidenced itself as a producer of PUC has been made, considered the petitioners as the eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.
- 12. The Authority notes that subsequent to initiation and during the proceedings no producer has presented itself before the Authority with evidence as a production of PUC though certain interested parties have mentioned that there are certain other producers of PUC also.

## **E. CONFIDENTIALITY, DATA INTEGRITY AND OTHER ISSUES**

### **E.1 Submissions by various interested parties**

- a. The initiation is ab initio void owing to the exclusion of USA from the scope of present investigation and the present initiation is required to be terminated based on this ground alone.

- b. In relation to the claim that the petitioners were unaware of the fact that the respondent has not provided domestic sales as well as cost information and that the same is impossible to deduce from the non-confidential versions, it is submitted that the said allegations are frivolous, misconceived and mischievous. Kind attention is invited to our letter dated 23.03.2017, which is indeed also available in the public file, the respondent has clearly stated the reasons in detail as to why individual dumping margin should be granted to it irrespective of the data relating to normal value. The failure of the petitioner to inspect public file and take cognizance of the documents and information submitted by other interested parties, does not give them any right to raise frivolous and unsubstantiated remarks.
- c. In relation to the submission made by the applicant industry that the non-confidential version of the questionnaire responses filed by the respondent herein is excessively confidential, it is submitted that the said allegation is baseless and without any substance. The non-confidential version of the response of the respondent has been prepared exactly as per the directions of the Authority and the practice followed in this regard. Therefore, confidentiality has been claimed by the respondent giving adequate reasons that are fully consistent with the legal provisions and the settled practice of the Authority.
- d. The petitioners have illegally and mischievously altered the application Proforma as per their whim and fancy. In Proforma IV-A, critical information like opening stock and closing stock has not been provided.

## **E.2 Examination by the Authority**

13. With regard to confidentiality of information, the Authority notes that the information provided by the domestic industry on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim in accordance with Rule 7 of the AD Rules. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not kept it open in public file. The Authority has also considered the confidential claims of other interested parties in accordance with the aforesaid rule and its consistent practice.
14. As regards data integrity and correctness, the Authority has verified the data submitted by the domestic industry and M/s. Arkema, cooperative producer/exporter in France. Also the Authority has obtained the import data from DGCIS to validate the correctness of the import data.

## **F. Determination of Normal Value, Export Price and Dumping Margin**

### **F.1 Views of the Domestic industry**

- a. The interested parties have not provided any evidence to show availability of public information. Petitioners have constructed normal value based on best available information. It is also relevant to point that if any such information is publicly available, the interested parties are free to establish that the import price is not a dumped price.
- b. The investigation period considered by the Authority in the present case is October 2014 to December 2015 (15 months). The injury investigation period has been considered as the period 2012-13, 2013-14, 2014-15 and POI.
- c. The purpose of fixation of POI is to consider a period when the existence of dumping causing injury is claimed and established. The date of determination is not relevant to the moot question of dumping causing injury to the domestic industry. Since the factum of dumping causing injury to the domestic industry is established based on investigation period, the conditions prevalent during the investigation period alone should be considered relevant, appropriate and necessary for the purpose.
- d. The Chinese producers are required to be treated as non-market economy companies for the reason that the costs and prices in China do not reasonably reflect the market forces. Para 8 to Annexure-I specifies the parameters which should be considered for grant of market economy status. This also implies that unless these conditions are not fulfilled/ satisfied, the Chinese costs and prices cannot be adopted.
- e. The consideration of market economy status is based on parameters prevailing during investigation period. Since the reason for rejection of Chinese costs and prices is distortion in the costs and prices in China due to the factors listed in Para 8 to Annexure-I, petitioner submits that it is the investigation period that is relevant to decide consideration of Chinese producers as market economy companies.
- f. Since Chinese companies have been denied market economy status for the reasons mentioned in Para 8 of Annexure-I till December, 2016, petitioners submit that the Chinese producers are required to be treated as

non-market economy companies till such time the investigation period includes the period specified in Accession Treaty protocol.

- g. In the context of rule 2(b), it is well established legal position that the imports by a domestic producer or its relationship with an exporter or importer are examined with reference to the investigation period. If POI alone is relevant for standing purposes, POI alone should be relevant for normal value determination.
- h. Chinese producers are required to be treated as companies operating under non-market economy environment and the Authority may proceed to determine the normal value on the basis of Para 7 of Annexure-I.
- i. Normal value could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available. The petitioners have claimed consideration of normal value on the basis of cost of production in India duly adjusted.
- j. The dumping margin from China is not only significant, but also substantial, thus establishing existence of significant dumping of the product under consideration in India. The import volume of China has remained significant throughout the present injury period.
- k. Since the prices/quotations of the producers of the subject goods were not publicly available in spite of efforts made by the domestic industry, the domestic industry has determined normal value in EU and Canada on the basis of best estimates of cost of production in EU and Canada.
- l. Petitioners strongly refutes the allegation of Arkema that there is no dumping in their product. In fact, dumping margin in case of Arkema should be higher than the estimates drawn in the application.
- m. Akzo Nobel has not provided information with regard to their domestic sales or cost of production. Evidently, Akzo Nobel has resorted to significant suppression of facts in the public version of its questionnaire response.

## **F.2. Views of other interested parties**

- a. Normal Value as constructed is wrong as the data of Canada/EU has been claimed to be unavailable, which is not the case and false value has been calculated.
- b. The CNV is not in conformity with law as raw material has been taken at the price available to applicant and not that which is available to subject countries, Raw material and utility norms – the consumption factor has been taken as per standard norms when in fact it should be taken as per the most efficient company in India, Conversion cost and SGA expenses taken as per DI's data when capacity utilization of DI has been very low leading to higher costs and Interest cost also taken as per DI standard when in fact it is very high as the petitioners are relatively new.
- c. DI has claimed very high and unheard of Ocean Freight to reduce the net export price. We request the Authority not to accept the freight claims of the DI and the same may be adopted as per the verifiable data provided by the cooperating exporters/parties.
- d. Arkema has submitted to the Indian Authorities not only all information requested in the initial questionnaire, but also additional elements and clarifications that were requested by the Authorities at a later stage. Arkema did not engage in unfair dumping practices in India. Imposition of AD measures on EU imports would go against the interest of many users of its product in India. Domestic production of the product concerned is severely insufficient to satisfy local demand and imposing duties against the EU is likely without question to lead to a significant shortage of the product concerned on the local market and an increase in prices that could hardly be passed on to the downstream sectors.
- e. M/s. Akzo Nobel, the exporter from Sweden has not claimed normal value and accordingly information related to normal value. The exporter has requested the Authority to construct the normal value based on the best information available in terms of Rule 6(8). In this regard, the exporter has cited cases Stainless Steel Cold Rolled Flat Products of 400 Series having width below 600 mm originating in or exported from European Union, Korea RP and USA on POSCO Korea treatment, Acetone originating in or exported from European Union, Chinese Taipei, Singapore, South Africa & USA. (treatment of M/s. Mitsui & Co. Ltd., an exporter from Singapore) and Clear Float Glass from Iran (treatment of M/s. Ardakan Float Glass Co., Iran. In view of the above, the exporter has requested the Authority to accept the response filed by M/s. Akzo Nobel and grant them individual dumping margin.

- f. European Commission have submitted that it appears from the notice of initiation and petition that the complainant constructed normal value based on the conversion cost applicable in India using international rates for the cost of power (natural gas). As the price for gas may differ significantly from one region to another, the Commission considers that such international price should have been disclosed and the Commission fails to understand why the non-confidential version of the petition does not contain any precise or ranged information with regard to cost used. Further, the petition does not contain any information with regard to the origin or level of the cost data used for the other raw materials. The Commission cannot see why such information should be kept confidential either.
- g. European Commission have submitted that India is in clear breach of Article 6.5.1 of the WTO ADA which provides that a meaningful non confidential summary allowing a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence should be provided. The Commission thus hereby requests the investigating authority to provide a revised version of the non-confidential version of the petition in order to allow the Commission and other interested parties to understand the substance and exercise their rights of defense.
- h. European Commission have submitted that it should be noted that the producers in the EU are likely to have a different cost structure due to their size and the economies of scale derived thereof. The fact that the Indian petitioners started production only recently; i.e. respectively in April 2012 and 2014, also casts doubts concerning their level of efficiency and the conversion rates that have been applied to construct normal value. In the absence of information on the cost of the raw material used, the Commission is not in a position to comment neither on such cost items nor on the level of the normal value. Eventually, the range given in Annexure 3.2 concerning normal value (0.5-1.0) seems quite broad and does not seem to fulfill the requirement of Article 6.5.1 either.
- i. European Commission have submitted that doubts are cast concerning the methodology and the adequacy of the data used in order to establish normal values and the consequent level of the dumping margin. In view of the quality of the non-confidential file, the evidence presented to the investigating authority should not have been regarded as sufficient and the petition should have been rejected.

### **F.3. Examination by the Authority**

- a. Regarding European Commission's observations on Normal Value computation for the producers of European Union, the Authority has evaluated the cooperative exporter from European Union based on their response and for the residual category of producers/exporters from European Union, the data provided by the cooperative exporter from EU has been referenced appropriately.
- b. As regards computation of 'normal value' and adjustments claimed by the petitioners for computing the ex-factory export price for producers/exporter, the Authority notes that as from EU two responses have been filed, one complete and another incomplete, the Authority therefore could correlate adjustments for exfactory export price for the residual category with the domestic industry's claim. In case where none of the producers/exporters from the subject countries have cooperated, the Authority has no option but to adopt best available information which includes responses of importers, evidence by domestic industry, Authority's consistent practice and any other appropriate information which is feasible and reasonable. The Authority however notes that since evaluation of extent of dumping is specific to a producer/exporter, it is essential for the concerned producers/exporters to cooperate to assist the Authority in such determinations. Any observations on evaluation of dumping margin by other interested parties i.e. other than the concerned producers/exporters can only be referred to in the context of various options as enumerated above. The Authority has appropriately considered such submissions.

#### **F.3.1 Normal Value for all producers/exporters of China**

15. Under section 9A (1) (c) normal value in relation to an article means:

- i. The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or
  - ii. when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either.
    - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
    - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);
16. As none of the exporters/producers from China have responded through questionnaire response in the present investigation the Authority considered para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR. Normal value for the subject product imported from China PR into India has therefore been constructed on the basis of best available information as per Rule 6 (8) by considering optimum consumption norms of the domestic industry for major raw materials and utilities, conversion cost, interest, SGA, etc. at the levels allowed for the domestic industry. \*\*\* % of cost of sales excluding interest has been allowed towards reasonable profit as per DGAD practice. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table.

### **F.3.2 Determination of Export Price for all producers/exporters of China**

17. None of the producers/exporters from China have filed questionnaire response. Therefore, the Authority has determined the export price for all producers/exporters of China PR on the basis of the DGCI&S transaction wise data. Accordingly, the weighted average net export price at ex-factory level, in respect of all exporters from China PR has been determined after making due adjustments for Ocean Freight, Marine Insurance, Commission, Bank Charges, Port Expenses and Inland Freight Charges to an extent of \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT and \*\*\* US\$/MT respectively on the basis of best available information as per Rule 6 (8) and the same has been mentioned in the dumping margin table. The Exfactory Export Price and CIF value comes to \*\*\* US\$/MT and \*\*\* US\$/MT respectively.

### **F.3.3 Determination of Normal Value for all producers/exporters of Canada**

18. It is noted that none of the producers/exporters in Canada have cooperated with the Authority with questionnaire response. The Authority has therefore constructed the normal value for all producers/exporters in Canada in accordance with Rule 6(8) supra i.e. by considering optimum consumption norms of the domestic industry for major raw materials and utilities, conversion cost, interest, SGA, etc. at the levels allowed for the domestic industry. \*\*\*% of cost of sales excluding interest has been allowed towards reasonable profit as per DGAD's consistent practice. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table.

### **F.3.4 Determination of Export Price in Canada**

19. None of the producers/exporters from the Canada has filed questionnaire response. Therefore, the Authority has determined the export price for producers/exporters of Canada on the basis of the DGCI&S transaction wise data. Accordingly, the weighted average net export price at ex-factory level, in respect of all exporters from Canada has been determined after making due adjustments for Ocean Freight, Marine Insurance, Commission, Bank Charges, Port Expenses and Inland Freight Charges to an extent of \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT and \*\*\* US\$/MT respectively on the basis of best available information as per Rule 6 (8) and the same has been mentioned in the dumping margin table. The Exfactory Export Price and CIF value comes to \*\*\* US\$/MT and \*\*\* US\$/MT respectively.

**F.3.5 Determination of Normal Value and Export Price for producers/exporters from EU**

20. The Authority notes that the following producers and exporters of the subject goods from EU have filed questionnaire responses providing information for determination of dumping margins.

- (i) Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals
- (ii) ARKEMA France, EU

- (i) The Authority notes that M/s. Akzo Nobel has provided information only regarding their export price to India but not the cost of production and domestic sales. In this regard the Authority notes their submissions that Authority has in past considered only export price filed by certain producer/exporter and constructed the normal value for them. The Authority notes that none of the cases cited by M/s. Akzo Nobel are similar to the present case. The Authority holds that any producer/exporter cannot partially choose to respond to the prescribed questionnaire. The data sought by the Authority in the questionnaire response is required to be fully completed for the Authority to take a composite assessment. The Authority does not accept partially filed information of M/s. Akzo Nobel and therefore treats them non-cooperative and consider them only under the residual category and determine AD measure in accordance with the best available information referencing information available regarding the sales in EU filed by the co-operating exporter and also the DGCIS data.
- (ii) The information submitted by M/s. Arkema, France was verified to the extent possible through an on the spot verification and various issues raised have been examined to the extent relevant and feasible during the course of the investigation. The Normal Value, Export Price and Dumping Margin of the producer/Exporter has been determined on the basis of the verified data/information as detailed below.

The Authority notes that the producer/exporter has provided details of domestic sales of both flaked (Alpure X) and bulk (Alpure S) grades during POI to an extent of \*\*\* MT and \*\*\* MT respectively to pulp sector. The producer/exporter has claimed adjustments on account of packing, inland freight, and commission to an extent of \*\*\* Euro/MT, \*\*\* Euro/MT and \*\*\* Euro/MT respectively. For the sales made to non-pulp sector at retail level, the producer/exporter has further claimed adjustments for level of trade. The producer/exporter has provided details of export sales of flaked product type i.e. Alpure X to India during POI and claimed adjustments on inland freight, ocean freight, packing and other charges to an extent of \*\*\* Euro/MT, \*\*\* Euro/MT, \*\*\* Euro/MT and \*\*\*Euro/MT respectively.

The Authority notes that the producer/exporter during the course of investigation had reiterated submissions made in questionnaire response that comparison of domestic and export sales to India be made on a like to like basis i.e. the flaked product exported to India be compared with sale of flaked product in the domestic market of EU and not with bulk, and that too at same level of trade for the main user industry i.e. paper and pulp.

The Authority has undertaken comparison at a grade to grade level for paper and pulp sector where the majority sales have taken place and the level of trade is also comparable.

The Authority notes that the producer/exporter has since exported flaked grade to India in big bags (non-bulk) i.e. Alpure X and has also sold significant quantity of the same product type i.e. Alpure X in their domestic market which meets the threshold of significant sales. Based on the onsite verification undertaken by the team at the producer/exporter site in France, and data furnished during verification and later in response to clarifications sought/response to exporter verification report, the Authority has determined the exfactory cost of production for both flaked and bulk grades separately as \*\*\* Euro/MT and \*\*\* Euro/MT respectively.

Based on the ordinary course of trade test and after identifying that all domestic sales of flaked type are loss making during POI in the domestic market, the Authority has evaluated the normal value for the flaked product type as \*\*\* Euro/MT. In this regard the Authority has referenced average profit on the comparable grade Alpure S during POI in the domestic market, on its profitable transactions, to compute normal value for flaked category.

The exfactory export price for Alpure X grade to India during POI has been considered as \*\*\* Euro/MT after making adjustments on account of inland freight, ocean freight, packing and other charges.

The dumping margin after the aforesaid comes to \*\*\* \$/MT (\*\*\* %).

For the other producers/exporters of EU including M/s. Akzo Nobel, the Authority has considered the normal value in EU on the basis of the cooperative exporter's data on all domestic sales irrespective of grade/level of sales. Based on this the dumping margin is evaluated as \*\*\* \$/MT (\*\*\* %).

### **F.3.9 Dumping Margin**

21. Considering the Normal Values and the Export Prices as determined above, the dumping margins are calculated as below

Particulars	Unit	China (All Producers/ Exporters)	Canada(All Producers/ Exporters)	EU	
				Arkema	Others
Normal value	US\$/MT	***	***	***	***
Net export Price	US\$/MT	***	***	***	***
Dumping Margin	US\$/MT	***	***	***	***
Dumping Margin %	%	***	***	***	***
Dumping Margin (Range)		0-10	20-30	10-20	20-30

### **G. ASSESMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK**

22. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure –II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
23. The Authority notes that the application for imposition of antidumping duty has been filed by M/s. Gujarat Alkalies and Chemicals Limited and Teamec Chlorates Limited and is the only producers of subject goods in India. In terms of Rule 2(b) of the Rules the petitioners have been treated as the domestic industry for the purpose of this investigation. Therefore, for the purpose of this determination the cost and injury information of the petitioners, constituting the domestic industry as defined in Rule 2(b), has been examined.

#### **G.1 Views of the Domestic Industry:**

- Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from subject countries directly compete with the like goods offered by the domestic industry in the Indian market. The products manufactured by the producers from the subject countries inter-se and in comparison to the products manufactured by petitioners have comparable properties. In other words, goods supplied by subject countries and by the domestic industry are inter-se like articles.
- The demand increased throughout the injury period with a slight decline during the POI. The imports also increased during 2013-14 and had a slight decline afterwards because of commencement of production by Indian producers. In spite of having the capacity to cope up with Indian demand, the imports were significantly high. Imports in absolute and relative terms have been significantly high.
- Regarding price undercutting, the foreign producers have reduced their prices from US\$ 600-700 pmt to US\$ 470-440 pmt.

- d. The imports are depressing the prices of the domestic industry in the domestic market as the landed price of imports is much below the level of cost and sales prices of the domestic industry. The subject goods are forcing the domestic industry to sell the product under consideration at highly un-remunerative prices. There is significant price depression over the period despite the fact that there was no decline in the costs.
- e. The capacity of the domestic industry is at par with the level of demand but because of dumped imports the optimum level of capacity utilization that could have been achieved has not yet been achieved even though capacity utilization has increased.
- f. Growth of the domestic industry is positive in terms production. However, the optimum level of sales and market share has not been achieved because of dumped imports. Even the present level of sales is being made at much less than the optimum prices causing high financial losses.
- g. The increase in inventories is despite the low level at which the domestic industry produced the goods because of dumping in the Country.
- h. Profits, profit before interest, cash profits and return on capital employed, all have remained very adverse throughout the injury period in spite of increase in production and sales.
- i. Both dumping margin and injury margin in the current POI from each of the subject countries are positive and significant.
- j. The domestic industry is not able to realize non injurious price for the product. The delta being achieved by the domestic industry is far below what is considered reasonable and fair globally.
- k. Volume of dumped imports has remained significant despite commencement of production by the domestic industry.
- l. Price reduction led caused by the dumped imports forced the domestic industry to reduce its prices.
- m. The price depression effect of dumped imports from subject countries have resulted in significant increase in financial losses of the domestic industry.
- n. The domestic industry has been prevented from increasing its production, sales, capacity utilization and market share to the extent of capacities and despite existence of significant demand and capacities in the Country.
- o. Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits are directly a result of dumped imports.
- p. The contribution margin of the domestic industry has steeply declined, which is largely due to dumping.
- q. The growth of the domestic industry became negative in terms of a number of economic parameters.
- r. The inventories with the domestic industry have increased significantly.

## **G.2 Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties**

- a. There is no material injury to the domestic industry as capacity, production, capacity utilization and sales have increased. Profits have stayed same as in the base year but increased from 2013-14 and 2014-15 and the decline in profits cannot be attributed to imports. Price undercutting has been negative as the prices of goods of the domestic industry have been lower than the landed price from the subject countries.
- b. Share of DI increased to 51% in POI and share of subject countries decreased from 78% in base year to 48% in the POI. Capacity utilization of DI has gone up to and above 90% post. Period of Investigation and DI must have earned profits.
- c. Production, Capacity utilization and Sales have increased over the injury period.
- d. Profits have stayed same as in the base year but increased from 2013-14 and 2014-15 and the decline in profits cannot be attributed to imports.

- e. Price undercutting has been negative as the prices of goods of the DI have been lower than the landed price from the subject countries.
- f. Losses of petitioners have now been declining. Since petitioner companies are new initial losses cannot be attributed to imports/ alleged dumping.
- g. Petitioners have not claimed price underselling or negative cash flows nor the same has been found out even after analyzing it.
- h. Petitioners acknowledge no negative impact of imports on employment and productivity.
- i. In spite of the fact that petitioners are relatively new in the market, they have been able to capture 51% of the market in a short span of time and thus they have shown growth even during the claimed injury period/POI and so allegations of injury are baseless.
- j. There is no casual link between the alleged dumped imports and the injury to domestic industry.
- k. The price under cutting and suppression is positive and hence no such price under cutting took place.
- l. Sales, productivity, market share and ROI have increased while losses have come down for the domestic industry.
- m. No price underselling or any negative cash flows has been claimed by the domestic industry.
- n. The fact that USA is not included in the scope of subject countries though the import volume from USA is above de-minimis threshold and the price from USA is lower than subject countries cumulatively and individually.
- o. The claims of the DI are highly self- serving and misleading. There is no volume injury in the present case. The market share of DI increased to 51% in the POI from a 7% in the base year where as the share of subject imports which was 78% in the base year declined to 48% in the POI. This is when the DI started some significant production only during the 2015-16 after introduction of new capacity. In fact, the imports quickly made way for DI and there cannot be any injury caused by such imports and such imports were necessitated by lack of capacity in India.
- p. The DI have tried to play down the issue of USA from the scope of present investigation which vitiates the causal link qua subject countries and also have a discriminatory aspect in view of Rule 19. The Authority cannot proceed discriminately against a few countries by excluding some. In fact, the claim of 'low volume of imports' from USA has no logic. The Rule provides for 3% as a significant level and import from USA is above 3% as per the import statement submitted for the POI by the DI. Even a suo-motu extension of POI does not justify such exclusion, because even a suo-motu extension of POI takes place after examining the basic facts and no such extension can be expected to be done merely.
- q. The DI did not disclose the price from USA to conceal the fact that the price from USA are much lower than subject countries. The price from USA is Rs. 33/Kg whereas the price from subject countries is between Rs. 37 to 42 per Kg which is much higher than USA.
- r. In relation to the injury claim of the petitioner, the petitioner is not suffering any injury on account of imports from the subject countries. The petitioners have failed miserably in providing any evidence suggesting price undercutting or price suppression and depression. What is even more surprising is that the petitioner has not even alleged any price underselling in the petition or anywhere in their written submissions. This fact clearly proves that there is neither any price undercutting nor any price underselling and, therefore, it is absolutely baseless to suggest and injury being caused by the allegedly dumped imports. This is without prejudice to our contention, based on our detailed written submissions, that there is no injury to the Domestic Industry in the

very first place. Therefore, the claim of Domestic Industry of any injury on account of imports should be rejected outright. Detailed analysis of injury parameters showing negative injury has been already submitted in our written submission therefore the same is not repeated herein for the sake of brevity.

- s. It is pertinent to mention here that the petitioner made an attempt to mislead the Authority with regard to price undercutting by carrying out jugglery of numbers.
- t. In this context, kind attention of the Authority is invited to para 71 on page 21 and Proforma IV-B on page 38 of the updated petition provided by the petitioner. It can be seen that while the petitioner has claimed positive price undercutting in para 71 on page 21, the analysis of the same in Proforma IV-B on page 38 of the updated petition clearly shows negative price undercutting.
- u. In an attempt to work out a positive price undercutting, the petitioner has unfortunately misrepresented and manipulated the data in Proforma IV-B. It may be seen that the petitioner has computed the landed price after convertible amount in Row 9 by deducting from the landed value the CVD/ED as well as the SAD/ACD/ST. On the other hand, the average selling price after convertible credit (Row 15) has been computed by merely deducting excise duty and not the CST (which is the equivalent of SAD/ACD/ST). Thus, the petitioner has misrepresented the data and attempted to compare non-comparables with the sole objective of giving an indication of "positive" price undercutting which in reality is not there. Unfortunately, this glaring fact has also escaped the kind attention of the Authority. The Authority should take a serious view of this fact and draw adverse inferences against the petitioner for having made an attempt to mislead the statutory authority.
- v. The Authority may appreciate that in Proforma IV-B, while Sr. no. 16(iii) and 17(iii) clearly show negative price undercutting for 'price undercutting w/o ED & CVD' and 'price undercutting after ED & CVD' respectively, Sr. no. 18(iii) shows a positive price undercutting for "price undercutting after convertible credit". It is reiterated that this positive price undercutting in Sr. no. 18(iii) is there because, for the computation of convertible amount for "average selling price after convertible credit", the petitioner has intentionally and conveniently ignored the CST. On the other hand, for the purpose of computation of convertible amount for 'landed price after convertible credit', the petitioner has included SAD/ACD/ST. It is submitted that such calculation has, in effect, reduced the landed value of the imports and thereby, increasing the difference between landed price and average domestic selling price indicating positive price undercutting. The manipulation of the data done by the petitioner in Proforma IV-B is evident from various tables.
- w. The manipulation of data has been done with a clear intent to depict, somehow or the other, positive price undercutting and to mislead the Authority regarding the same. It is further submitted that such manipulation needs to be discouraged and dealt with strictly. Since the present investigation is based on tampered data provided by the petitioner, the same ought to be terminated forthwith. It is further submitted that the same distortion has been followed for the computation of quarter-wise price undercutting and for working out price undercutting for countries individually.
- x. Article 3.2 of the WTO AD agreement foresees that, in order to determine injury, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption. In this investigation it is rather the opposite. While consumption increased by over 18% over the period 2012-13 to the period of investigation (PoI), the level of imports from the countries concerned has dropped significantly by over 23% over the same period. Furthermore, it is also noted that imports from the subject countries have dropped from 25.747 MT in 2013-14 to 15.746 MT in the PoI, i.e. since both Indian producers started their activities and quickly gained significant market shares to the

detriment of the subject countries. It follows from the above that there has been no increase, neither in absolute nor in relative terms, (neither to production nor consumption) of the imports from the subject countries over the period 2012-13 to the PoI ('period of analysis'). The above developments do not point to an injurious situation.

- y. European Commission has submitted that the domestic producers have presumptuously assumed that their mere establishment in a market, which has been in the exclusive hands of third countries for several years, would suffice in order to gain significant market share and reach high profitability rates early after they started commercial production. The Commission cannot agree with such reasoning for obvious reasons.
- z. European Commission have also submitted that the petitioner seems to put excessive weight on the profitability of the domestic industry and the fact that the industry incurred losses over the last years. In this regard, it is first recalled that the domestic producers started their operation respectively in April 2012 and April 2014; i.e. very recently. In this context, it cannot be reasonably assumed that a newcomer on a market will generate immediate profit. On the contrary, start-up costs are usually only absorbed only after a few years of activity. Second, it is noted that the profitability situation of the domestic industry is not as dramatic as depicted in the petition. For instance, the loss per unit has been decreasing significantly since 2013-14 (from index - 148 to -99 during the POI). In the absence of any indicator on the actual level of profitability expressed as a percentage of turnover for the domestic Indian industry (reported as a range or index), the Commission is prevented from providing any more elaborate comments on the particular issue of profitability.
- aa. According to Article 3.4 of the WTO AD agreement all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry shall be evaluated and that nor one or several of the injury indicators listed can necessarily give decisive guidance on the finding of injury. The investigating authority is hereby invited not to focus only on certain indicators but to give the appropriate weight to all relevant injury indicators as listed in the WTO AD agreement. These indicators also show an inconclusive injury picture.
- bb. Given the position of new entrants on the market, it appears that the situation of the petitioners is encouraging not to say satisfactory in many respects. Indeed, the petitioners have gained significant market share in the record time of less than 42 months and attracted 47,84% of the domestic consumption in the PoI. The market share of the domestic industry even reached 51,66% in 2015-16/Q2. It is also noted that cost of sales has been decreasing much faster than selling price between 2013-14 and the PoI (-15 percentage points for cost of sales vs -7 percentage points for selling price). Other indicators such as capacity utilization, sales volume, employment, productivity per employee and per day all show a positive trend over the period of analysis.
- cc. As far as stocks are concerned, the investigating authorities are invited to ensure that the increase in inventories is not linked to the fact that the end of the PoI does not coincide with the end of a financial year where companies usually tend to reduce their inventories for balance sheet presentation purposes.
- dd. As far as price undercutting is concerned, the petitioners claim that the import price from the subject countries was below the cost of sales and selling price of the domestic industry. In this regard, it is suggested that the petitioners, as new producers, have to cover higher costs and have to offer higher prices, which may explain the alleged price undercutting. In any case, the higher costs / prices of the domestic industry did not prevent them from gaining significant market shares.
- ee. All in all, it appears that the domestic industry is progressively settling on the domestic market to the detriment of historical market players as evidenced by the continuous improvement of most injury indicators.

- ff. Imports from the subject countries have decreased significantly over the period of analysis following the penetration of two domestic producers in the Indian market. In this context, it is unclear how the decrease in imports may have contributed to the alleged injury suffered by the domestic producers. On the contrary, it appears that the situation of the domestic producers is improving in many respects, as indicated above. In view of the above elements, the Indian domestic industry did not suffer any injury and that any alleged injury could in any event not have been caused by imports. There seems to be other factors that have had an important impact on the situation of the domestic producers.
- gg. European Commission has also submitted that according to Article 3.5 of the ADA, the authorities shall also examine any known factor other than the dumped imports which, at the same time, are injuring the domestic industry, and the injuries caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Therefore, an in-depth analysis of other factors is necessary, in particular:
- (i) In view of the recent apparition of the two Indian producers on the market and in the absence of reliable historical data concerning production costs, conversion rates, scrap ratios, productivity..., the investigating authority should compare the above mentioned key performance indicators of the domestic Indian industry with those of long-established producers in the subject countries in order to assess whether the domestic producers are actually producing efficiently and can be competitive on the Indian market even though a 7.5% import duty is already applicable on sodium chlorate and serves as a first trade protection.
  - (ii) In view of the level of domestic consumption in the period of analysis which ranged between 26.159 and 31.718 MT and the apparent absence of significant exports by the petitioners, doubts are cast concerning the level of capacity of the domestic producers (+/- 31.500 MT). It appears that, in view of the historical presence of other market players, the domestic Indian producers have been careless, not to say presumptuous when estimating the level of capacity to be installed. It follows from the above that the installed capacity appears oversized in comparison with the extent of the market and that such overestimate is likely to lead to excessive fix costs having a negative impact on the financial performance of the domestic industry.
  - (iii) Start-up costs and other factors inherently affecting the beginning of any production activity before it reaches its normal cruise speed should also be analysed as their extend can have a negative impact on the financial performance of the domestic industry. The Indian authorities are therefore invited to improve the quality of the non-confidential version of certain documents to allow all interested parties to exercise their rights of defence. The Commission also requests the Indian authorities to assess the overall evolution of all injury factors, including the absolute and relative evolution of imports, and not to focus on certain isolated indicators. The Indian authorities are also invited to compare the actual performance of the petitioners with that of long-established petitioners to assess whether the domestic industry is operating in an efficient way and can indeed be competitive. The impact of other factors should also be analysed thoroughly.

### **G.3 Examination by the Authority**

24. The Authority has taken note of submissions made by various interested parties. The Authority has examined the injury to the domestic industry in accordance with the Antidumping Rules and considering the submissions made by the other interested parties.
25. The AD Rules require the Authority to examine injury by examining both volume and price effect. A determination of injury involves an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic industry. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.

26. As regards the consequent impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure II of Antidumping rules states as under:-
- (iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.*
27. It is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration; while some may show improvement. The Designated Authority considers all injury parameters and thereafter concludes whether the domestic industry has suffered injury due to dumping or not.
28. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments in the submissions.

### **G.3.1 Cumulative assessment**

29. With regard to cumulative assessment Annexure II (iii) to the Rules provides as follows:
- In cases where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the designated authority will cumulatively assess the effect of such imports, only when it determines that (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the import of the like article or where the export of individual countries less than three percent, the imports collectively accounts for more than seven per cent of the imports of like article and (b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.*
30. In the instant case, investigations in respect of subject goods are from more than one sources. The Authority, therefore examined the injury to the domestic industry cumulatively for these countries. The Authority notes that
- The margins of dumping of product under consideration from each of the subject countries are more than the de-minimis limit;
  - The volume of imports of product under consideration from each of the subject countries is more than de minimis;
  - The information furnished to the Authority gives a reasonable indication that the exports made from the subject countries compete inter se and in the same market, thus are like product.
31. In view of the above, the Authority holds that it would be appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry in the light of conditions of competition between imported products and like domestic products.
- a. **Assessment of Demand**
32. For this purpose, demand or apparent consumption of the product in India is taken as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. Share of imports for each of the subject countries in demand/consumption in India determined by the Authority is as under-

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Sales of Domestic Industry	MT	1,725	4,612	11,496	15,699
Imports from Subject Countries	MT	21,233	25,184	20,118	15,849
Canada	MT	525	2,982	3,964	1,078
China	MT	7,573	11,650	1,918	975
EU	MT	13,135	10,552	14,235	13,797
Other Countries	MT	3,844	1,870	158	571
Total Demand	MT	26,802	31,666	31,772	32,118

33. The Authority notes that demand has increased over the injury period.

### **G.3.2 Volume Effect of Dumped Imports - Import Volumes and Share of Subject Countries**

34. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The Authority has examined the volume of imports of the subject goods from the subject countries and other countries based on the transaction-wise import data provided by DGCI&S data. The import volumes of the subject goods and share of the dumped import during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Subject Countries	MT	21,233	25,184	20,118	15,849
Canada	MT	525	2,982	3,964	1,078
China	MT	7,573	11,650	1,918	975
EU	MT	13,135	10,552	14,235	13,797
Other Countries	MT	3,844	1,870	158	571
Total Imports	MT	25,077	27,054	20,276	16,420
Share of imports in total imports					
Share of subject countries	%	85%	93%	99%	97%
Share of other countries	%	15%	7%	1%	3%
Subject Country Imports in relation to					
Indian production	%	1228%	534%	174%	103%
Consumption	%	79%	80%	63%	49%

35. Imports have increased in 2013-14, and started declining thereafter to some extent because of commencement of commercial production by domestic industry. However, despite commencement of domestic production, the imports remained significant throughout the injury period. Almost entirety of imports is from subject countries. Further imports in relation to production and consumption are also significant in the POI.

### **G.3.3 Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry**

36. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

*“With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.”*

37. It has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports of the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

#### **Price Undercutting**

38. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product from each of the subject countries and the

average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at ex-factory level.

SN	Particulars	Unit	China	Canada	EU	Subject countries
1	Landed Price	Rs/MT	45,290	43,974	41,801	42,163
2	Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
3	Price undercutting	Rs/MT	(***)	(***)	(***)	(***)
4	Price undercutting	%	(10-20%)	(0-10%)	(0-10%)	(0-10%)

39. The Authority notes that the price undercutting is negative for which domestic industry has claimed that they had no option but to match the landed prices.

**Price Underselling**

40. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from the subject countries. For this purpose, the cost of sales determined for the domestic industry has been compared with the landed price of imports. The landed price of imports considered for the purpose of price undercutting has also been adopted for the purpose of determining price underselling. Comparison of weighted average cost of sales of the domestic industry with weighted average landed price of imports shows as follows:

SN	Particulars	Unit	China	Canada	EU	Subject countries
1	Landed Price	Rs/MT	45,290	43,974	41,801	42,163
2	Non-Injurious Price	Rs/MT	***	***	***	***
3	Price underselling	Rs/MT	***	***	***	***
4	Price underselling	%	30-40%	30-40%	40-50%	40-50%

41. It is noted that the landed price of imports were below the non-injurious price of the domestic industry. The Authority notes that the domestic industry has suffered price underselling during the investigation period on account of imports of the subject goods from the subject countries.

**Price Suppression and Depression**

42. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree and prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the Table below.

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	93	90	69
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	80	77	71

43. It is noted that, both, cost of sales and selling price of the domestic industry declined throughout the injury period. However, decline in selling price is much more than the decline in cost of sales. The selling price has remained below the level of cost of production throughout the injury period. Thus, imports indicate suppressing and depressing effect on the domestic prices in the domestic market.

**G.3.4 Impact on Economic Parameters of the Domestic Industry**

44. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry indicates that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below:

**a) Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales**

45. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization is as follows:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Capacity-Plant	MT	11,500	11,500	31,500	31,500
Trend	Index	100	100	274	274
Production	MT	1,729	4,712	11,543	15,454
Trend	Index	100	273	668	894
Capacity Utilization	%	15%	41%	37%	49%
Sales volume	MT	1,725	4,612	11,496	15,699
Trend	Index	100	267	666	910

46. It is noted that both the petitioner companies have commenced commercial production recently. Production and sales of the domestic industry has therefore increased as a natural consequence of domestic industry commencing production during the injury period. Capacity utilization of the domestic industry has also increased, but continue to be sub optimal.

**b) Profits, Return on Capital Employed and Cash Profit**

47. The cost of sales, selling price, profit/loss, cash profits and return on investment of the domestic industry has been analyzed as follows:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Profit/ (Loss) per unit	Rs./MT	(***)	(***)	(***)	(***)
Profit/ (Loss) – Total	Rs.Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
Cash Profit	Rs.Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
Profit before Interest and Tax	Rs.Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
Return on Investment	%	(***)	(***)	(***)	(***)

48. The Authority notes that the domestic industry suffered financial losses in terms of profit, profit before interest and cash profits. The return on capital employed has seen a decline over the injury period and remained at negative levels throughout the injury period.

**c) Market Share in Demand**

49. The effects of the dumped imports on the market share in demand of the domestic industry have been examined as below:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Subject Countries Imports	%	79.22	79.53	63.32	49.35
Other Countries- Imports	%	14.34	5.91	0.50	1.78
Sales of domestic industry	%	6.44	14.56	36.18	48.88
Total	%	100	100	100	100

50. The Authority notes that the market share of the domestic industry has increased with commencement of production. However, subject imports holds significant market share and that domestic industry is also having sufficient capacity to cater the domestic demand. It indicates that dumping of the product is impacting the market share of the domestic industry, which commenced commercial production only recently.

**d) Employment, Wages and Productivity**

51. The position with regard to employment, wages and productivity is as follows:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
No. of Employees	Nos	***	***	***	***
Trend	Index	100	100	136	136
Wages	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	100	132	206	176
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Productivity per day	MT/day	***	***	***	***

52. The Authority notes that employment level has increased and so has the level of wages. Further, productivity per day and per employee has also increased over the injury period.

**e) Inventory**

53. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Opening Stock	MT	***	***	***	***
Closing Stock	MT	***	***	***	***
Average Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	967	2,567	10,114

54. The Authority notes that level of inventories with the domestic industry have increased significantly over the injury period.

**f) Magnitude of Dumping**

55. It is noted that imports from each of the subject countries are entering the country at dumped prices and the margin of dumping are above de-minimis limits and significant.

**g) Ability to raise capital investment**

56. Petitioners have submitted that they have already planned capacity expansion in view of significant demand in the country. The Environmental approval and other statutory approvals have already been made. However in view of dumping causing injury to the domestic industry, the expansion is not being pursued. It indicates that the ability of the petitioner to raise capital is being affected.

**h) Growth**

57. The data relating to growth of the domestic industry is shown in the following table:

<b>Growth</b>	<b>Unit</b>	<b>2012-13</b>	<b>2013-14</b>	<b>2014-15</b>	<b>POI</b>
Production	Y/Y	-	173%	145%	34%
Domestic Sales	Y/Y	-	167%	149%	37%
Cost of sales	Y/Y	-	-7%	-3%	-23%
Selling price	Y/Y	-	-20%	-3%	-8%
Profit/Loss	Y/Y	-	295%	139%	-43%
ROI	Y/Y	-	-462%	12%	52%
Cash Profit	Y/Y	-	-335%	-77%	78%

58. The Authority notes that growth of the domestic industry has lowered in some parameters.

**i) Factors Affecting Domestic Prices**

59. The examination of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that the landed value of imported material from the subject countries is below the selling price and the non-injurious price of the domestic industry, price underselling in the Indian market. The authority notes that the prices of the product under consideration in general should move in tandem with the prices of key raw materials and the domestic industry has been fixing its prices considering these input prices and landed price of imports. Domestic industry has claimed that since they have commenced production recently, the domestic industry had no option but to align its prices to the market prices, which are dictated by the prices offered by the foreign producers in subject countries. Thus, the landed value of subject goods from the subject countries is an important factor for determination of domestic prices.

**G.3.5 Other Known Factors & Causal Link**

60. The Authority has noted other factors listed under the Antidumping Rules which could have contributed to injury to the domestic industry for examination of causal link between dumping and material injury to the domestic industry.

**Imports from third countries**

61. The Authority has examined import data of the subject goods obtained from DGCI&S on transaction-wise basis and notes that almost entirety of imports are from subject countries as compared to imports from other country imports.

**Contraction in demand**

62. The demand for the subject goods has increased thus possible decline in demand have not caused injury to the domestic industry.

**Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

63. There is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

**Developments in technology**

64. The existing technology and process adopted by the domestic industry is comparable with foreign producers as regards production of the final product.

**Changes in pattern of consumption**

65. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Change in the pattern of consumption is unlikely to contribute to the injury to the domestic industry.

**Export performance**

66. The domestic industry has not exported the product under consideration. Thus injury to the domestic industry is on account of domestic operations only.

**Performance of the domestic industry with respect to other products**

67. The performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

**Productivity of the domestic industry**

68. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has increased. Deterioration in productivity is not a cause of injury to the domestic industry.

**Factors establishing causal link**

69. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has deteriorated due to dumped imports from subject countries. Causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:
- a. Volume of dumped imports has remained significant despite commencement of production by the domestic industry.
  - b. Price reduction caused by the dumped imports have forced the domestic industry to reduce its prices;
  - c. The price depression effect of dumped imports from subject countries have resulted in significant increase in financial losses of the domestic industry.
  - d. The domestic industry has been prevented from increasing its production, sales, capacity utilization and market share to the extent of capacities and despite existence of significant demand and capacities in the Country;
  - e. financial losses and negative return on capital employed are directly a result of dumped imports;
  - f. The growth of the domestic industry became negative in terms of a number of economic parameters.
  - g. The inventories with the domestic industry have increased significantly.
  - h. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry. For the purpose the Authority has considered best consumption norms of the raw materials & utilization. The Authority has segregated and excluded injury suffered by the domestic industry due to other factors, in accordance the provisions of Annexure-III to the Rules.

**H. Magnitude of Injury and Injury Margin**

70. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the imports from the subject country for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as under:

Particulars	Unit	Canada	China	EU	
				Arkema	Others
Non Injurious Price (NIP)	US\$/MT	***	***	***	***
Landed Price	US\$/MT	***	***	***	***
Injury Margin	US\$/MT	***	***	***	***
Injury Margin %	%	***	***	***	***
Injury Margin (Range)	%	30-40	30-40	50-60	50-60

71. It is seen that the injury margin for each of the subject country is positive and substantial.

**I. User Industry's Interest & other issues**

72. The Indian Paper Manufacturers Association have submitted the following:
- The Pulp & Paper Industry is passing through a very difficult phase, to survive under the current scenario of significantly increased raw material and input and energy cost and very aggressive competition in the domestic market from imports of finished products allowed at concessional / nil import duty under the different Free Trade Agreements (FTAs) signed by India. The Pulp & Paper Industry has made substantial investments in the last 5 years and it is becoming very difficult to meet its financial obligation in view of significant drop in margins. As things stand today, there is a very serious threat of existing investments in capacities turning economically unviable. 2/3 large Paper Mills have already closed down in the last couple of years, and if no urgent steps are taken by the Government, it is feared that some more Mills may face closure. This will not only create revenue loss to the Government, but also adversely impact an industry that has strong backward linkages with the farming community and generates significant employment in the rural areas.
  - India Pulp & Paper Industry is deeply concerned with the Initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of 'Sodium Chlorate' originating in or Exported from Canada, People's Republic of China and EU vide Notification dated 12th May 2016, since the Pulp & Paper Industry is a major consumer of Sodium Chlorate, and some Paper Mills have been importing the same even before M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. (GACL) and M/s Teamec Chlorates Ltd. (TCL) commenced their production.
    - Many Paper Mills, in order to avoid hazardous liquid chlorine for bleaching of pulp, have eliminated its use and have started the use of Sodium Chlorate in its place. In the revised process, Chlorine Dioxide is produced from Sodium Chlorate, which is used for bleaching of pulp and making the paper produced 'Eco Friendly' and 'Elemental Chlorine Free (ECF)'. Many more Paper Mills are in the process of moving towards ECF bleaching of pulp.
    - Purity of the Sodium Chlorate imported from Canada, People's Republic of China and EU is much higher than the Sodium Chlorate available in the domestic market. The monthly running cycle for imported Sodium Chlorate is also better being 45 days against 35 days for indigenously produced Sodium Chlorate.
    - Sodium Chlorate, being a hazardous item, which comes under the Arms Act, cannot be dumped in the domestic market like other materials as only licensed customers can use it for their own use.
    - Presently, the price of imported Sodium Chlorate is at par with domestically procured Sodium Chlorate, and it is anticipated that any imposition of anti-dumping duty on the import of Sodium Chlorate will result in increase in its domestic prices also, and as a result, add further to the overall manufacturing cost of the

domestic Pulp & Paper Industry and further squeeze the thin margins under which the industry is currently operating.

- In order to safeguard the interests of the end consumers of paper as a whole, and especially the school children under the 'Sarva Shiksha Abhiyan', it is requested that anti-dumping duty on the import of Sodium Chlorate should not be even considered till the demand-supply gap in the country is eliminated.

#### **Examination by the Authority**

73. The Authority notes the submissions of users and holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the India market, which is in the general interest of the country, Imposition of antidumping measures is not to restrict imports from the subject countries in any way, and to affect the availability of the products to the consumers.
74. The Authority also holds that though in an event of imposition of anti-dumping duties the price level of product in India may be affected but fair competition in the Indian market will not be reduced by such anti-dumping measures. On the contrary, the anti-dumping measures may mitigate the unfair advantage gained by dumping practices, which would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Consumers could still maintain two or more sources of supply.

#### **Post disclosure comments**

75. The post disclosure comments by domestic industry and various interested parties are as under:

(i) Domestic Industry has submitted the following:

- NIP has been determined on the basis of the data of the domestic industry. Petitioner requests complete disclosure of detailed break up of NIP determined, including (i) element of expenses disallowed, (ii) adjustments made in cost of production claimed, (iii) any modifications done in the capital employed to enable the petitioner to provide comments on the same.
- The Authority may disclose the non-confidential version of the verification report of the exporters/producers from subject country to offer meaningful comments on the dumping margin calculated.
- The Authority may kindly make available a copy of all the communications sent via mail or letter, to the opposing interested parties and replies filed by these interested parties. Petitioner is not requesting any confidential information. Petitioner is requesting only NCV of this information.
- Since Normal value is based on the domestic industry data and information publicly available/used; it may be disclosed.
- Authority may disclose the actual dumping margin. The actual dumping margin cannot be confidential in this case for the following reasons
- In case of participating exporter – Since the injury margin is much higher than dumping margin, in any case, once the Designated Authority issues final findings, the interested parties shall know the actual dumping margin determined. What would not remain confidential at that stage cannot be confidential at this stage.
- In all other cases – as the information is based on petitioner/domestic industry's data, the same is not confidential.
- Since the actual data adopted in the injury analysis pertains to the domestic industry, the same may be disclosed to the domestic industry. This has in fact been disclosed to the domestic industry in the past.
- The above is vital for the domestic industry to offer their meaningful comments on the disclosure statement. However, pending such disclosure, the domestic industry offers hereunder following preliminary submissions

to the Disclosure Statement. The domestic industry craves leave to make further submissions, as and when the above essential facts are disclosed.

- Petitioners conclude from the disclosure statement that the domestic producers are the only domestic producers of subject goods in India; the product under consideration is exported at prices below normal value, resulting in dumping from each of the subject countries. The dumping margin determined is very low; Domestic Industry has suffered material injury and such injury is evidenced by adverse price effect of dumped imports from the subject countries. Anti-dumping duty is required to be imposed to address dumping causing injury to the domestic industry.
  - The Authority has noted that one of the major user industry has itself admitted that petitioners are the only two domestic producers of subject goods hence the comments on standing of DI have been reiterated. Petitioners have neither imported nor related to any importer or exporter of subject goods and thus are eligible domestic industry and satisfy the provision of standing in terms of AD Rules.
  - The dumping margin determined for Chinese producers is too low. Petitioners earlier requested disclosure of calculations of normal value. While the said calculations have not been disclosed to the petitioners so far, the analysis of information provided by the petitioners and the information contained in the disclosure statement clearly shows that the authority has determined normal value on the basis of NIP determined for GACL. However, petitioners submit that determination of normal value on the basis of GACL data alone is inappropriate in the present case for the following reasons.
  - Production of PUC generates hydrogen gas. While GACL consumes this hydrogen gas in production of Hydrogen Peroxide, Teamac does not consume hydrogen gas and allows it to be let off. The research done by the petitioner with regard to Chinese producer's operations shows that there are Chinese producers who have no utilization of hydrogen. Since there exists producers of PUC in China who cannot utilize hydrogen in production of some other product, determination of normal value on the assumption that Chinese producers are generating hydrogen and utilizing the same in production of downstream product is without any basis. Petitioners request the authority to kindly determine normal value on the basis of data/information pertaining to Teamac alone. Petitioner refers to rule 6(8) in this regard.
  - The scope of best available information has also been well explained in the WTO Agreement. Therefore if an interested party does not cooperate and thus relevant information is being withheld from the authorities, this situation could lead to a result which is less favourable to the party than if the party did cooperate.
  - The Hon'ble Supreme Court has also held in the matter of Fairdeal Polychem LLP vs Union of India & Anr that the WTO Agreement is directly applicable on to the authority. Thus, in the absence of relevant provision in Indian Rule as is prescribed under WTO Agreement, it must be concluded that the scope of Rule 6 (8) implies that if an interested party does not cooperate and thus relevant information (in the instant case, information on normal value) is being withheld from the authorities, this situation could lead to a result which is less favourable to the party than if the party did cooperate. The authority is therefore required to draw adverse inference in respect of the exporters and not a favourable inference with regard to exporters. In other words, the authority should not penalize the domestic industry because of non-cooperation of the exporters and should not reward the exporters for their non-cooperation.
  - AD Duties be levied on fixed quantum basis in Dollar terms.
- (ii) M/s Arkema, France has submitted the following:
- The comments submitted by M/s GIDE on behalf of Arkema, France are in particular regarding the erroneous basis for the dumping margin calculation and the insufficient disclosure of the Indian authorities, the non-cooperation of the Chinese producers, and the injury analysis.

- As set out in the confidential disclosure document relating to the dumping calculation relating to Arkema France, named "Arkema CV on DM.docx", the dumping amount is found to be \*\*\*MT. This amount was confirmed as 12%, on a telephonic enquiry.
- Firstly, the documents received from the Indian authorities as part of the general disclosure (both confidential and non-confidential documents) are insufficient to fully understand the methodology used by the Indian authorities to calculate the dumping margin for our client or the findings relating to other parties in the proceeding, such as the Chinese producers or the domestic industry.
- Secondly, specifically with regard to the dumping margin calculated for our client, Arkema France, it is not clear how the amount of \*\*\* is equivalent to a dumping margin of around \*\*\*. It appears from the disclosure documents and further communication with the Indian authorities that the dumping margin was calculated on the basis of the ex-works export price rather than the CIF price.
- However, such practice is contrary to the provisions of the WTO Agreements as well as the generally accepted practice of WTO members. Article 7.2 of the WTO Anti-Dumping Agreement ("ADA") states that "Provisional measures may take the form of a provisional duty or, preferably, a security - by cash deposit or bond - equal to the amount of the anti-dumping duty provisionally estimated, being not greater than the provisionally estimated margin of dumping. Withholding of appraisement is an appropriate provisional measure; provided that the normal duty and the estimated amount of the anti- dumping be indicated and as long as the withholding of appraisement is subject to the same conditions as other provisional measures."
- Furthermore, Article 9.3 of the WTO ADA expressly provides that "the amount of the anti-dumping duty shall not exceed the margin of dumping as established under Article 2".
- By using the ex-works export price as a basis for the calculation of the dumping margin, which is naturally lower than the CIF price, the Indian authorities have artificially increased the level of the anti-dumping duty to be imposed, which now exceeds the level of the dumping margin established for our client, Arkema France.
- Appendix 2 of Arkema's questionnaire reply sets out details of all sales of Alpure X to India in the POI. The average CIF price in this appendix is €591,03. On the basis of this CIF price, the dumping margin is \*\*\*% (\*\*\*). We consider that the CIF price is the appropriate basis for calculating the dumping margin as this is the price on which the Indian customs authorities will levy the anti-dumping duty. To levy a duty of around \*\*\*% would mean that the duty exceeds the dumping margin. Such practice used by the Indian authorities is clearly in contradiction to the provisions of the WTO ADA. We therefore consider that the proposed duty should be revised to reflect the above calculation method.
- It is indicated in the non-confidential general disclosure document that no Chinese producers cooperated with the investigation and that the dumping calculation was made on the best facts available to the Indian authorities. However, compared to the other foreign producers concerned by the investigation, the Chinese producers have obtained the lowest dumping margin (0-10%) whereas the other producers, including Arkema France, have dumping margins between 10% and 30%.
- This finding was particularly shocking to Arkema France as our client cooperated to the best of its capabilities with the Indian authorities. As also stated in the general disclosure, our client provided you with all the information requested and all of the data received was verified during a verification visit conducted at the premises of Arkema France. Moreover, as is also confirmed by the Indian authorities themselves in the disclosure documents, Arkema France was the only foreign producer to cooperate to this extent with the Indian authorities.
- It should be noted that the result above is not in line with the spirit of the WTO Agreements, which do not support the idea of granting more favorable results to non-cooperating producers than cooperating producers. Moreover, it takes away any incentive a foreign producer may have to cooperate with any future investigations initiated by India if it is clear that it is India's practice to grant a more favorable result to non-cooperating producers.

- Arkema France considers that information disclosed with regard to the methodology of the calculation of the dumping margin, in particular the normal value, with regard to the Chinese producers is insufficient. For example, the general disclosure document states that the normal value for Chinese exporters was constructed on the basis of best facts available “by considering optimum consumption norms of the domestic industry for major raw materials and utilities”. Such vague terms do not allow the other interested parties in the proceeding to understand the methodology behind the calculations made. Indeed, the word “optimum”<sup>1</sup> could suggest that the most favorable consumption norms have been used which results in the most favorable outcome for the non-cooperating Chinese exporters.
- Arkema France therefore considers that the calculation and ultimate finding for the Chinese exporters requires revision.
- Based on the general non-confidential disclosure document, the injury and causation arguments are not at all convincing and do not justify the imposition of anti-dumping duties. For example, it would appear that the domestic industry has seen improvements in all factors, except inventories (which have only decreased slightly). Furthermore, although the disclosure document states that “the domestic industry suffered financial losses in terms of profit, profit before interest and cash profits” and that “the return on capital employed has seen a decline over the injury period and remained at negative levels throughout the injury period” (please see par. 48 of the general disclosure document), such findings are not at all supported by any data disclosed in the disclosure document. In fact, no data at all in this regard was disclosed.
- With regard to causation, it appears from the disclosure documents that imports from the countries concerned have fallen from approximately 21 000 MT to around 16 000 MT. The market share of imports has decreased from 79% to 49% while at the same time the market share of the Indian producers has increased dramatically from 6% to 49%.
- The Indian authorities should strongly consider revising their findings in this regard.

(iii) M/s APJ SLG Law offices representing Akzo Nobel, EU have submitted the following:

- M/s Akzo Nobel has stated that they are extremely concerned regarding not granting the individual dumping margin to the responding producer/exporter is in stark contradiction to the position taken by the authority in some of the recent cases. Unfortunately, the disclosure statement is silent on the detailed submissions, arguments and precedents advanced by us and why the same are not applicable to the fact and circumstances of the present case. The detailed submissions were filed by us in the earlier note dated 12/6/2017.
- The Authority has brushed aside the submissions and legal position cited by us merely by stating that “none of the cases cited by M/s Akzo Nobel are similar to the present case.” The Authority may appreciate that it is not the similarity of ‘facts’ which is required to be examined in a case, but the ‘ratio’ of the approach and the position taken by the Designated Authority in other cases. In any event, it is obligatory on the Authority to deal with the legal provisions and the case laws and to record reasons as to why the same are distinguishable. The facts of the present case may be different from the cases cited by us, but we reiterate that it is the ‘ratio’ which matters. Even a cursory glance of the cases cited by us would establish beyond any doubt that the ratio and practices are clearly applicable in the facts and circumstances of the present case.
- Authority may determine individual dumping margin / injury margin for the responding producer/exporter from European Union, M/s Akzo Nobel for the sake of fair treatment and the consistency of practice.
- Despite our repeated submissions in this regard, the Authority has conveyed the present position to us for the first time through the disclosure statement. We, therefore, request the Hon'ble Authority to grant us an opportunity of hearing to explain our submissions along with the relevant applicable case laws in person in accordance with the principles of natural justice.

- (iv) M/s M.S. Pothal & Associates Chartered Accountants on behalf of (a) M/s Zenith Electrochem Pvt Ltd, (b) M/s Bindals Papers Mills Ltd, and (c) M/s K R Pulp & Papers Ltd has submitted as under:
- There is a serious issue of non- inclusion of apparently above de-minimis level imports of PUC from USA in the scope of present investigation. The issue is not just a blatant violation of WTO principle of non-discriminatory imposition of duties, but has a causal link breach aspect as well since the price from USA is lower than price from subject countries. The disclosure statement captured the issue at some places as submissions by importers etc. However, no examination of the issues is being carried out which is unfair and inconsistent to the practice of this Authority itself in the past. Such issues have been examined with great relevance in the past as can be seen from various findings by the Authority and there is no legal or factual reason now to give the issue a skip. At the cost of repetition, we once again reproduce our relevant submission on this issue as below to seek the kind attention of the Authority to this significant issue. It is reiterated that the present investigation should be terminated without any measures as the exclusion of above de-minis low priced imports from USA viz. subject countries have breached the causal link in the present investigation and the authorities cannot impose duties in a discriminatory passion.
  - Non-inclusion of USA as a subject country in the present investigation has vitiated the present investigation itself. It would cause the causal injury examine unfair and look manipulative and also it has its nuances of discrimination against a particular country which is prohibited under the ethos of AD Agreement itself. We have pointed out this issue in our initial submissions itself but no justification whatsoever has been advanced by the DI for non- inclusion of USA in the scope which makes it doubtful that the DI excluded USA with a design unknown to us.
  - It was coined by DI that the POI was suo motu extended by one quarter by the Ld. Authority and as per the original POI the share of USA was 2.14%. This arguments itself is not sufficient to remove the impediment that has happened. The DI has merely attempted to shift the burden of the lapse to the Ld. Authority whereas the fact of the matter is that no such suo motu extension of POI would have carried out without checking the basic information pertaining to the period considered to be included in the POI. Our humble submission is that the DI did not bring this fact to the knowledge of the Ld. Authority to take advantage of such exclusion and in fact the DI remained silent on the issue for the past more than 7 months even after we pointing out this issue in our initial submission. We wish to submit as follows on the issue.
  - The present anti- dumping investigation concerning imports of Sodium Chlorate is initiated against Canada, China PR and EU and these countries are jointly referred to as subject countries in the initiation notification. Rule 14 and Rule 19 of the ant dumping rules are relevant in this respect wherein rule 14, inter alia, sets the threshold of 3% from a particular country in the total import volume into the country as level to continue an anti- dumping investigation against a country and rule 19 prohibits imposition of anti- dumping duties in a discriminatory manner i.e imposing AD duties against only a particular country or countries and leaving one or more countries from the scope of any duty imposition. Rule 19 has its direct reliance on Article 9.2 of the WTO AD Agreement. The concept of non- discriminatory action is very strictly followed by WTO members and DGAD also has never been an exception to it. Rule 14, 19 and Article 9.2 of the AD Agreement are pertinent in this regard.
  - The Applicant has been highly selective in choosing the subject countries and have deliberately ignored imports of the subject goods from USA despite the fact that the imports from USA were significantly above the de-minimis thresholds during the POI and were also at significantly lower price as compared to the prices from the subject countries that have been included in the investigation. This shows that the initiation is discriminatory in nature vis-à-vis subject countries and any imposition of AD duties against the subject countries and no duty against USA in the present case will lead to discriminatory measures, thus, the present initiation is untenable under the law. Such an initiation not only hints at discriminatory action but also an apparent breach of causal link also.
  - The revised summary imports data provided by the applicant reflecting the imports of the PUC from various countries provided vide Annexure 1.2 along with the updated petition at page 47 of the Application clearly

shows that imports of the subject goods from USA have been significantly higher than the de-minimis thresholds prescribed under the law. Further, imports from USA have taken place at such lowest price levels which have been considered as injurious to the domestic industry by the Applicant qua the subject countries. We, thus, fail to fathom as to why USA has not been considered as a part of the subject countries in this investigation.

- Non-inclusion of USA as a subject country has led to a situation whereby Rule 19 of the AD Rules stands violated. Rule 19 enjoins the Authorities not to impose Anti-dumping duty on discriminatory basis as submitted herein above.
- The exclusion of USA from the scope of 'subject countries' has been deliberate as the participating domestic industry may have imported the subject goods or could be related to some of the exporter/producer of the subject goods from USA and, thus, may not have had the 'locus standi' to file the application at all against USA. Mischief is apparent, as the Applicant has merely filed declarations that the participating domestic producers have not imported the subject goods from the subject countries as against declaring that they have not imported the subject goods at all, which is a major fallacy in itself.
- Also, it is misleading that the DI has submitted in Section V of the updated application considering the new POI that the imports from other countries are either negligible or import prices are high when the fact of the matter remained imports from USA were at about 3.14% and the price was Rs 33/kg which was substantially lower than the price from subject countries which ranged between Rs 37 to 42 per KG. What is interesting is that the DI did not clarify on this issue in the updated petition also and gave a misleading statement instead. If the exclusion was the fallout of extension of POI, then the DI would have clarified the same in the updated petition.
- It is submitted that non-inclusion of USA is a larger legal issue and which goes into the very roots of present investigation. Thus, non-inclusion of USA within the scope of the investigation is a fatal error that makes the entire investigation ab initio void. Hence, the Hon'ble Authority taking cognizance of this fatal error must terminate these proceedings on this ground alone. After all, the AD Agreement and AD rules do not permit the Authority to proceed discriminately in an AD investigation which is a bilateral issue.
- It has been submitted that there are more than 2 producers in India and one of such other known producer is a state owned company. The subject disclosure statement addressed the issue effectively as in para 11. However it is reiterated that Shree Chlorate (M/s Zenith Electrochem Pvt Ltd) still has the license to produce the subject goods and there is another producer namely The Travancore Cochin Chemicals Limited (state PSU) which is also producing the subject goods, name of which is not at all disclosed to the Authority by the petitioner.
- The normal value and export price, it is submitted that the dumping margin as determined appears extremely high and it is our apprehension that the petitioner has placed misleading information on record to show a very high dumping margin and we are handicapped to place any comments as every information relating to dumping margin determination is held as confidential. The dumping margin determined may be revisited in view of our earlier submissions also which is not reproduced for sake of brevity.
- Any injury to the domestic industry is visible from the disclosure statement and the case needs to be terminated for this reason alone. A plain reading of the disclosure statement reaffirms our claims that there is no injury suffered by the domestic industry as alleged on account of imports from subject countries as imports from Sodium Chlorate have declined.
- Price under cutting is clearly negative in the case which shows there was no adverse price effect of landed price from subject countries on domestic industry. It is incorrect to say that the petitioner tried to match the price of imports. Had that been the case, then the undercutting would have been positive. Negative undercutting means the landed price of imports were higher than domestic price so where is the question of petitioner trying to

match the import prices. It needs to be answered as to what has stopped the domestic industry from increasing its prices to the levels at least that of imports. Also, the imports from subject countries declined significantly by the POI which shows the exporters were not attempting to gain more market share by offering lower prices.

- The negative undercutting from subject countries coincided with decline in imports buttresses our argument that the cause of any alleged injury to the domestic industry would at the best be low priced imports from USA and when import price from USA has not been causing any injury to the domestic industry as evident from the fact that no case is initiated against USA, a comparatively higher priced imports from subject countries ought not have caused any injury. Thus, the veracity of the claims needs further examination.
- Positive price underselling has no meaning in the facts of present case and any positive underselling at the best could be the result of an inflated COP though the NIP is determined as per Annexure III. The negative undercutting shows there was absolutely no price effect of subject imports and such prices could not have created any underselling effect in reality, thus, it is our apprehension that the COP is clearly inflated which needs further scrutiny before allowing any such costs as claimed by the petitioner.
- It is observed by the Authority in the disclosure statement that both, cost of sales and selling price of the domestic industry declined throughout the injury period however, decline in selling price is much more than the decline in cost of sales. It is also observed by the Authority that the selling price has remained below the level of cost of production throughout the injury period, thus, imports indicate suppressing and depressing effect on the domestic prices in the domestic market. With regard to these observations, it is submitted that the table at para 43 shows less decline in selling price and reduction in cost has been higher. Also, since the price undercutting is negative, there cannot be any suppressing or depressing effect on account of alleged dumped imports. Any injury in such case could be due to other reason and injury on account of any such other reasons cannot be attributed to imports. This aspect needs further examination considering our above comments and we pray for the same.
- All the volume parameters as per the disclosure statement show stupendous growth. There hasn't been any price injury also on account of imports as the price from subject countries were not undercutting the price of domestic industry. Thus, there is absolutely no injury triggered by alleged dumped imports and based on this the Authority may conclude that the domestic industry did not suffer any injury during the POI.
- The trend of productivity is kept as confidential and the trend is also not provided. We request the Authority to check the same and any injury on account of decline in productivity cannot be attributed to imports. We are unable to offer any comment as not even trend of the parameter is available in the 'factual disclosure'.
- There isn't any economic justification to see the claimed increase in inventory level as given in the disclosure as a an indicator of injury in the present case as the key volume parameters of domestic industry's performance shows extreme spurt by the POI and at the same time the imports from subject countries have sharply declined. The increase in inventory cannot be attributed to imports.
- The disclosure statement has addressed the issue of growth without giving any emphasis to the significance of this parameter. The observation that growth of domestic industry has lowered in some parameters is grossly insufficient an examination when the fact of the matter is the growth has been significantly positive in almost every parameter of the subject disclosure. There cannot be even an iota of truth in the claim that the domestic industry suffered material injury when key injury parameters showed positive growth. We request the Authority to examine the aspect in detail so that correct conclusions on injury are reached out.
- Contrary to the observation that there is causal link in the present matter, it is submitted that negative price undercutting and exclusion of low priced above de-minimis level imports from USA viz. subject countries shows breach of causal link in the present case. We do not have the details of import volume and price from USA as per DGCI&S as the same is held confidential or not provided here. There is enough reason to believe that the imports from USA were more than de-minimis threshold and the prices were less than subject countries

and this was evident in the petition. We request the Authority to re-examine the causal link aspect by taking USA imports also into consideration.

(v) European Commission have submitted the following:

- Article 3.2 of the WTO ADA provides that the investigating authorities shall consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production and consumption. As already pointed out by the commission in its previous submission, import volumes of Sodium Chloride in to India from the subject countries have decreased considerably after the domestic industry has started producing the product concerned. Import from the subject countries in relation to both Indian production and consumption have also decreased significantly (-92% and -38%) over the period of analysis (2012-13 to the POI). All imports from the subject countries have started to decrease in particular from 2014-15 (from 20, 118 MT to 15,849 MT in the POI), after the second Indian company entered the domestic market and gained market share.
- It is also claimed that, despite the start of domestic production, imports remained significant throughout the injury period and almost all imports come from the subject countries: but this is absolutely normal in a situation where the domestic demand has completely relied on imports for so long and the domestic industry has started producing the product concerned only recently.
- As regards prices, the comparison to establish undercutting has been kept confidential: no data nor index on net selling prices of the domestic industry has been made available, making it impossible for parties to have a clear understanding of the allegedly injurious situation. It is simply claimed that import prices of the domestic industry; but, even so, this has not prevented the newly established domestic industry to gain significant market share (49% of domestic consumption in the POI) in a short period of time.
- The same applies to underselling, where no index nor trend on the non-injurious price of the domestic industry has been made available (Annex IV (A) does not help in understanding the calculation).
- The above mentioned absence of meaningful summaries of the non-disclosed data and calculations undermines the parties rights of defence and is contrary to the provisions of Article 6.5.1 of the WTO ADA, which provides that the authorities shall require interested parties providing confidential information to furnish non-confidential summaries thereof and that these summaries shall be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence.
- Production and sales volume of the domestic industry have increased in 2014-15 as a consequence of the second domestic company starting production in April 2014, and kept on increasing during the POI. So did capacity utilization, employment, productivity per day and per employee.
- In view of an increasing positive trend of most injury indicators, the domestic industry does not seem to be in a situation of serious injury caused by dumped imports. Any difficulty the industry is experiencing is most likely due to other factors, notably when imports have decreased significantly during the period of analysis.
- According to Article 3.5 of the WTO ADA, it must be demonstrated that there is a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry. An important element in order to show this causal link is price undercutting. However, as explained above, the information on undercutting is not conclusive.
- Furthermore, the petitioners claim that due to the dumped imports, and despite the significant increase in domestic demand, they were not able to further expand capacity as they has planned. However, since the domestic industry has already reached nearly 50% market share within three years only, it is considered that the domestic industry's plan and investment to increase capacity were excessive. They did not take into account/underestimated the strong position the imported products hold for so long on the Indian Market.

- The petitioners also claimed that they has to reduce their selling prices thus suffering financial losses as a consequence of the allegedly dumped imports. In this regard, the Commission questions how the two can be linked, since imports from the subject countries have significantly decreased over the period of analysis. There are other factors, already outlined in our previous submission (efficiency, capacity, start-up costs), that have has an impact on the situation of the Domestic Producers and that need to be taken appropriately into account.

#### **Examination by the Authority**

76. The Authority clarifies that as regards all non-cooperative producers/exporters from China and Canada, the Authority has evaluated constructed normal value (CNV) for all these producers/exporters in accordance with Rule 6(8) supra i.e. by considering optimum consumption norms of the domestic industry for major raw materials and utilities, conversion cost, interest, SGA, etc. at the levels allowed for the domestic industry. 5% of cost of sales excluding interest has been allowed as reasonable profit as per DGAD's consistent practice and the same has been adopted here. The Authority also holds that dumping margin evaluated for a cooperative producer/exporter of a particular subject country cannot be compared with producers/exporters from other countries be it cooperative or non-cooperative, as determination of CNV for non-cooperative producer/exporter of a subject country are based on best available information as appropriate for that country. Further Dumping Margin is a function of not only CNV but also export price, which varies country to country. The Authority therefore reiterates the dumping margin already evaluated for China and Canada.
77. As regards dumping margin evaluation for Arkema France, the Authority notes that the producer/exporter has not per se denied the evaluation of dumping but has made submissions on the percentage of dumping margin which according to them should be evaluated as a percentage of CIF and not ex-factory export price (ExEP). The Authority has as per the AD Rules evaluated dumping margin as a percentage of ExEP. While dumping margin as percentage of ExEP or CIF may vary, the absolute dumping margin value would remain unchanged. The Authority has disclosed the cost of production and further details of ordinary course of test along with profit margin to be added on cost of production to Arkema France. The ExEP value claimed by the producer/exporter has been accepted with all relevant details regarding exfactory export price computations disclosed to the producer/exporter. The Authority therefore confirms the evaluation of dumping margin already conveyed to the producer/exporter.
78. As regards inclusion of USA also as a subject country, the Authority holds that it is not only the import price but also the fact of dumping which needs to be prima facie established by a petitioner while requesting initiation of a case. The Authority received petition against three countries only and initiated the case against these three requested countries on the basis of prima facie facts which did not include USA.
79. The Authority notes the submissions made by the advocates for M/s Akzo Nobel to grant individual dumping margin to them on the basis of only the export price furnished by them as they have no claim on the normal value. The Authority has in this regard noted the cases cited by them where such a consideration has been submitted to have been made. The Authority notes that none of the cases cited by the producer/exporter is similar to the present case. In case of Cold Rolled Steel Products, the producer/exporter had filed actually data on cost of production which was not considered appropriate. In case of Acetone the exporter had provided the Domestic Sales data but not the cost of production. In case of M/s Ardakan, there were deficiencies noted in the response of the producer/exporter. Therefore in all these case the producer/exporter showed their intention and effort to file data which fall short of normal expectation. In case of M/s Akzo Nobel, there is a total denial regarding filing of data for normal value purposes. Therefore the Authority holds that M/s Akzo Nobel has therefore been appropriately considered in the residual category.
80. As regards Domestic Industry's claim to disclose NIP, a detailed worksheet was already provided to them. As regards other information on disclosing CNV, exact dumping margin %, exporter verification reports/communications etc., the Authority holds that the disclosure on various aspects has been made as per the Authority's consistent practice. The CNV computed for a non-cooperative group of producers/exporters has been based on Domestic Industry's data viz. the most efficient producer and by allowing an appropriate quantum of return as per Authority's consistent practice. Since 'CNV' is computed based on domestic industry's data along with other best available information, the Authority does not disclose computation of CNV to Domestic Industry or any of the interested parties including the non-responding producers/exporters, for whom the dumping margin

is computed as this is treated as confidential. The dumping margin evaluated is therefore mentioned as a range in the final finding and not as an exact percentage to ensure confidentiality.

81. As regards the standing of Domestic Industry the Authority notes that the major user associations has submitted that there are only two producers of the product under consideration in the country. Further no evidence on existence of any other producer has been filed by any interested party nor has any such producer made itself known to the Authority during the course of investigation. The standing of the Domestic Industry has therefore been correctly established.
82. The Authority notes that various interested parties have submitted that the Domestic Industry's indices on production, sales, market share are strong and not evidencing any injury. Further the price undercutting is also negative. The Authority notes that despite all these indices, the prices of Domestic Industry have remained suppressed well below the NIP. The negative price undercutting in case of new producers needs to be appreciated in context of their efforts to ensure their market presence. The domestic industry has benchmarked its selling prices with imports from the dumped sources. While this happens, there is a negative price effect in terms of reduced profitability and a significant injury margin which have been noted in this investigation. Therefore Authority holds that there has been a visible injury on price account due to price suppression effect.

### **Conclusions**

83. Having examined the contention of various interested parties and on the basis of the analysis as above, the Authority concludes that:
- i) There is dumping of product concerned from the subject countries.
  - ii) Imports from subject countries are suppressing the prices of the domestic industry.
  - iii) The price injury to domestic industry has been caused by dumped imports, with a significant positive injury margin due to price suppression.

### **Recommendations**

84. Having concluded as above the Authority considers it necessary to recommend following definitive Anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner as described in the duty table given below.
85. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, antidumping duty equal to the amount mentioned in Col 8 of the table below is recommended to be imposed by the Central Government, on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

**DUTY TABLE**

S.No	Heading/ Sub heading	Description of goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	28291100	Sodium Chlorate	China	China	Any	Any	17.77	MT	US\$
2	-do-	-do-	China	Any	Any	Any	17.77	MT	US\$
3	-do-	-do-	Any	China	Any	Any	17.77	MT	US\$
4	-do-	-do-	Canada	Canada	Any	Any	120.14	MT	US\$
5	-do-	-do-	Canada	Any	Any	Any	120.14	MT	US\$
6	-do-	-do-	Any	Canada	Any	Any	120.14	MT	US\$
7	-do-	-do-	EU	EU	Arkema	Arkema	60.51	MT	US\$

					France	France			
8	-do-	-do-	EU	EU	Any other than mentioned in S. No. 7 above	Any other than mentioned in S. No. 7 above	95.35	MT	US\$
9	-do-	-do-	EU	Any	Any	Any	95.35	MT	US\$
10	-do-	-do-	Any	EU	Any	Any	95.35	MT	US\$

86. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

**Further Procedure**

87. An appeal against the order of the Central Government arising out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority